हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 अक्तूबर,1977

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 19 अक्तूबर, 1977

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न संख्या 88 पर अनुपूरक प्र न (पनरारम्भ)	(3)1
तारांकित प्र न एवं उतर	(3)4
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नो के उतर अतारांकित प्र न एवं उतर	(3)23 (3)29
ध्यानाकर्शण सूचना–	(3)33
(1) उधोग मंत्री द्वारा ध्यानकर्शण सूचना न. 2 पर वक्तव्य	(3)34
(2) मुख्यमंत्री द्वारा ध्यानाकर्शण सूचना न. 1 पर वक्तव्य	(3)35
दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (न.5) बिल, 1977	(3)38
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट)बिल, 1977	(3)66
बहिर्गमन	(3)68

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट)बिल, 1977 पनुराम्भ	(3)68
बहिर्गमन	(3)68
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट)बिल, 1977 पनुराम्भ	(3)68
बैठक का समय बढाना	(3)71
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट)बिल, 1977 पनुराम्भ	(3)72
बैठक का समय बढाना	(3)85
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमैंट)बिल, 1977 पनुराम्भ	(3)85
दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स(हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977 (पुनराम्भ)	(3)97
दि पंजाब लैंड रेवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977	(3)99
दि पंजाब आयुर्वैदिक एंड युनानी प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977	(3)100

हरियाणा विधान सभा

बुधवार,19 अक्तूबर, 1977

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1 चण्डीगढ, में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (बिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न संख्या 88 पर अनुपूरक प्र न (पुनराम्भ)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान, कल जो सवाल रह गया था, बहिन जी पहले अब उसकी सप्लीमैटरीज का जवाब देगी।

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, कल भी हैल्थ मिनिस्टर साहिबा ने यह बताया था कि ऐसे केसिज जो हमारे पास आये है, हमने उनको इन्कवायरी के लिए भेजा है । मैने सवाल यह किया था कि एडमि ान का टाईम तो इन्कवायरी में ही निकल जायेगा । क्योकि हो सकता है कि इसमें साल लगे या 6 महीने। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि जिन बच्चो का नम्बर कट गया है जबकि उनकी परसैटेज बनती थी। और उनको एडमि ान नहीं मिला है, उनके लिये क्या सोचा है उनका साल जो खराब हो रहा है, उसको कैसे बचाया जाये ?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री(श्री मति डाक्टर वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैने कल भी निवेदन किया था कि इस बात पर विचार करना युनिवर्सिटी का काम है क्योकि वह एक ओटोनोमस बौडी है, हम केवल उनसे इनक्वायरी के लिये प्रार्थना कर सकते हैं। हमने उनको इन्कवायरी के लिए केसिज भेजे है लेकिन निर्णय तो उन्ही ने लेना है।

कंवर राम पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, बहिन जी ने कल भी यह जवाब दिया था कि फैसला तो युनिवर्सिटी ने करना है । मै उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यह जो एग्जामिने ान का सिस्टम चालू हुआ है, यह पहली सरकार ने चालू किया था या इसी साल इसी सरकार ने चालू किया है ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्माः यह फैसला पहली गवर्नमैंट ने ही किया था जो कि 1–07–1977 को हमने इम्पलीमैंट किया है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः क्या मंत्री महोदया यह बताने का कश्ट करेगी कि यह जो टैस्ट सिस्टम लागू किया गया था, इसको आगे के लिए बन्द किया जायेगा या नहीं ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्माः यह तो स्थिति के अनुसार विचार किया जायेगा।

चोधरी बीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या कोई ऐसी स्टेट भी है जिसमें एक से ज्यादा

यूनिवर्सिटीज है, और वहां पर भी यह एगजामिने ान सिस्टम लागू हो ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्माः आन्ध्र है, पंजाब है। सारे दे ा में केवल तीन ही स्टेट्स के अन्दर यह सिस्टम चालू हुआ है और हरियाणा चोथी स्टेट है जिसके अन्दर यह सिस्टम चालू किया गया है।

श्री गुलजार सिंहः हमारी जनता सरकार का देहातों में तालीम के बारे में जो विचार है कि वह पिछड़े हुए इलाको के लोगो को आगे ले जाना चाहती है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि पिछले टैस्ट में कितने देहातों के लड़कों को एडमि ान मिला है ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो जितने भी एडमि ान मिले है, वे सब हरियाणा डोमीसाइल को ही मिले है। कोई बाहर से नहीं आया। हरियाणा कि जितने लड़को ने बाहर की यूनिवर्सिटियो से परीक्षा दी है, अगर वे यह जानना चाहे तो वह भी मै बता सकती हूं।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहिबा को याद होगा कि पिछले असैम्बली के सै ान के दौरान इसी विधानसभा के 32 मैम्बरो ने एक मैमोरैन्डम चीफ मिनिस्टर साहब को द दिया था कि मैडिकल कालेज रोहतक के साथ जो हास्पिटल है इसको यूनिवर्सिटी के कन्ट्रोल से निकाल कर सरकार

अपने हाथ में ले ले। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके ऊपर कोई एक ान हुआ है, अगर हुआ है तो क्या एक ान लिया गया है ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह मैमोरैन्डम भी मुख्यमंत्री महोदय ने वाइस–चांसलर को भेज दिया था जोकि यूनिवर्सिटी के अधिकारी होत है ।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदया, यह बताने का कपा करेंगी यह जो दाखिले हुए है इनके अन्दर हरिजनो के लिए सीट्स भी रिजर्व है या नहीं, अगर है तो क्या वे पूरी हो गयी है ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह प्र न तो वाइस–चांसलर से पूछ कर ही बताया जा सकता है।

चौधरी राम कि ान: मै मंत्री साहिबा से यह पूछना चाहता हूं कि इस क्वै चन के अन्दर स्पैसिफिकली यह दिया हुआ है कि 50 प्रति ात वाले लड़के–लड़कियो को तो वहां पर एडमि ान मिल गये हैं लेकिन 70 प्रति ात वालो को इग्नोर कर दिया गया है, ऐसा क्यो किया गया ? क्या जिनको इग्नोर किया गया, उनके नाम बतायेंगे ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इंडियन मैडिकल कोंसिंल के साथ जब यह अनबन्ध हो गया तो वि ववविद्यालय ने यह परसैंटेज का मियार खत्म करके केवल

एन्ट्रैन्स टैस्ट के बेसिज पर ही एडमि ान दी है आपको पता ही है कि एन्ट्रैन्स टैस्ट में कोई 50 प्रति ात वाला पास भी हो सकता है और कोई 70 परसैंट वाला रह भी सकता है ।

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महादेया यह बताने की कृपा करेंगी कि इन एडमि ान के अन्दर हरिजनो के लिए कोई रिजर्वे ान भी है या नहीं ? यह जो एग्जामिने ान लेने के बाद एडमि ान हुई है, उसमें गवर्नमैंट की पालिसी के मुताबिक हरिजनो को पूरी रिजर्वे ान मिली है या नहीं ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्माः रिजर्वे ान जरूर है लेकिन यह क्वै चन के अन्दर तो नहीं पूछा था कि वहां पर क्या रिजर्वे ान है ?

कंवर राम पाल सिंहः मंत्री महोदया को पता है कि जब लड़के एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करके आते है तो उनको बेस मानना चाहिए था, लेकिन इन्होने यहां पर दूसरा ही एग्जामिने ान सिस्टम चालू कर दिया है। जो बेस मानना चाहिए वह तो मानते नहीं लेकिन अपने एग्जामिने ान को बेस मानते चल रहे है। मै मंत्री महादेया से यह जानना चाहता हूंकि यह जो जो नया एग्जामिने ान सिस्टम चालू किया है, इसको दरूस्त करने का कोई विचार है या नहीं ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्माः इंडियन मैडिकल कोंसिल का विचार है कि यदि किसी प्रान्त में एक से अधित यूनिवर्सिटीज

है तो वहां पर एन्ट्रैन्स एग्जामिने ान होना चाहिए क्योंकि यहां पर भी दो यूनिवर्सिटीज है। इसकलए यह हमारे चहां पर भी होना चाहिए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मंत्री महोदय ने यह बताया कि वह एग्जामिने ान वहां पर होना चाहिए जहां पर एक से अधिक युनिवर्सिटीज हो। इस किस्त की तीन स्टेट्स है और चोथी हरियाणा जिसने यह सिस्टम लागू किया है। मै मंत्री महादेया से यह जानना चाहता हूं कि इस बात की क्या आव यकता थी कि यह सिस्टम हरियाणा में भी लागू किया जाता ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्माः इसका जवाब तो वाइस–चांसलर साहब ही दे सकते है लेकिन जहां तक हमे पता चला इंडियन मैडिकल कोंसिल धीरे–धीरे इस सिस्टम को अन्य प्रोविसिन्ज के अन्दर भी चालू कर रही है।

श्री मूल चन्द जैनः मै मंत्री महादेया से यह जानना चाहता हूं कि यह सजै ान इंडियन मैडिकल कांसिल की तरफ से आया था जो हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया है या हरियाणा सरकार ने इस बात का निर्णय अपने आप लिया है या हरियाणा के लोगों की तरफ से ऐसी मांग आयी थी,, और क्या यह सरकार हरियाणा के लोगों की मांग को देखते हुए इस सिस्टम को रद्द करने के लिये तैयार है ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम पिछली सरकार ने ही लागू करने का फैसला किया था। इस गवर्नमैंट ने तो सिर्फ उसको इम्पलीमैंट किया है । जहां तक इसको छोड़ देने का सवाल है, इस पर विचार किया जा सकता है।

मास्टर ि ाव प्रसाद: मंत्री महोदया ने कल बताया था कि राजस्थान या दूसरी यूनिवर्सिटियों से लड़के अधिक मात्रा में नम्बर लेकर यहां जाते थै। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि क्या ऐसा विचार किया जा सकता है कि उन यूनिवर्सिटियों के लिए कोई डैफिनिट रिजर्वे ान कर दी जाये जैसे 10 प्रति ात या 15 प्रति ात ही लड़के दूसरी यूनिवर्सिर्टीयो से लिये जाये और बाकी सीट्स हरियाणा से पास किये हुए विद्यार्थियो के लिए ही दी जाये ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्मा: माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है यह एक बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर विचार किया जा सकता है।

तारांकित प्र न एवं उतर

Embezzlement cases detected in Central Co-operative Bank

***60. Rao Dalip Singh:** Will the minister for irrigation and Power be pleased to state-

a the total number of embezzlement cases detected in the Central Co-operative Banks during the years 1973-74,1974-75,1975-76,1976-77 and 1977-78, respectively, to date in the State; and

b the total amount involved in embezzlement cases referred to in part (a) above and the steps taken by the Government to recover the same ?

सिचाई एवं विधुत मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)

(क) तथा (ख) स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूची

वर्श	पकड़े गये गबन क केसो की संख्या	रा ि ा	वसूली के लिए सरकार द्वारा उठाये गये पग
1973-74	1	4200-00	वसूली के लिए मामला नयायालय में विचाराधीन है।
1974-75	-----	-------	
1975-76	1	1654-00	केवल 438.25 रूपये की वसूली अभी बाकी है जो

			कि भीघ्र होने की संभावना है।
1976-77	-----	-------	
1977-78	-----	-------	

राव दलीप सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करे कि यहां पर आडिट एक साल मे एक दफा होता है या दो साल में एक दफा होता है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब इसके बारे में पहले नोटिस दे तो यह भी बता दिया जायेगा।

Rent Cases under the Haryan(Control of Rent and Eviction) Act,1973

***93. Chaudhri Birinder Singh:** Will the Industries Minister be pleased to state-

(a) the total number of cases transferred from Civil Courts to Executive side after the enforcement of Haryana (Contrl of Rent and Eviction) Act, 1973;

(b) the total number of cased instituted before the Rent Controller up to 31-08-1977 after the enforcement of the said Act;

(c) the total number of cases disposed off by the Rent Controller up to 31-08-1977 out of the cases mentioned in parts(a) and (b) above; and

(d) the total number of cases pending before the Rent Controller on 1-9-1977 under said Act ?

Industries Minister (Dr. Mangal Sein):

(a) 2820

(b) 13279

(c) 11459

(d) 4650

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जवाब के भाग (डी) में इन्होने यह बताया है कि 4650 केसिज पैडिंग है। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि इनकी क्विक डिसपोजल के लिए वह इन केसिज को एडी ानल कलैक्टर से निपटारा करवाना चाहते हैं या फिर दोबारा जुडी ीयरी के अन्दर सिविल कोर्टस में भेजना चाहते है ?

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि सिविल कोर्टस में देने का फैसला कर लिया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसको कब तक लागू कर देगें ?

डाक्टर मंगल सैनः बहुत भीध्र ।

Power Meters Removed in District Mohindergarh

***101. Sathi Ayodhya Pashad:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there are any cases in district Mohindergarh as on 1.7.77 in which the Power Meters were removed for not paying the electricity bills amounting to RS.400/- or less, if so the number of such cases; and

(b) whether there are any cases where the rules/instruction in pursuance of which the Power Meters as referred to in part (a) above, have been removed were not followed in such like cases in the aforesaid district; if so, the total number of such cases and the reasons there for ?

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हां। 1.7.77 को जिला महेन्द्रगढ़ में 64 केसो में बिजली के मीटर उतारे हुए थे ।

(ख) हां। ऐसे 40 केस थे जिनमें निम्न कारणो हेतू बिजली के मीटर नहीं उतारे जा सके ।

(1) परिसर बन्द होने के कारण 35

(2) क्षेत्र पानी से धिरा होने के कारण 4

(3) बिल में झगड़े के कारण 1

चोधरी बीरेन्द्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के विचाराधीन ऐसी बात है कि फ्लैट रेट पर इलैक्ट्रिसिटी चार्जिज कर ले ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में एक अलग क्वै चन आया है उसी समय का इसका जवाब भी दे दिया जाएगा।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सैलाबजदा इलाके मं जहां बहुत अर्से से लाग बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे है, उनके मीटर खराब हो गए है, ट्यूबवैल्ज भी सिंक हो गए है। ऐसी हालत में वे लोग बिजली का अदा करने की स्थिति में नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि सरकार ने उनको कोई रियायत देने का एलान किया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस समय तक कोई रियायत का एलान नहीं किया है । बिजली बोर्ड एक कमि र्यल आर्गेनाइजे ान है और कोई बिल इस आर्गेनाइजे ान के ऐकूमुलेट नही हो सकते ।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, जहां पानी गहरा है और किसानो को ट्यूबवैल्ज के लिए ज्यादा हार्स पावर की म ाीनरी लगानी पड़ती है, वहां उनका ज्यादा खर्चा आता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कुछ रियायत देने का सरकार का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इसके लिए आप अलग से नोटिस दे या कोई सुझाव दें तो जवाब दे दिया जायेगा।

चौधरी लाल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार ने जो खराब खम्बे हमारी स्टेट में गाढ़ दिए थे, वे खम्बे उखाड़ लिये जायेगे ?

श्री अध्यक्षः डिसअलाउड।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, फ्लड की वजह से हमारी स्टेट में बेहद नुक्सान हुआ है। हमारी सरकार सोच रही थी कि फ्लड अफैक्टिड ऐरियाज में लोगो को कुछ सुविधाएं दी जाये क्योकि यह सब से जरूरी चीज थी। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने अभी विचार ही नहीं किया है। स्पीकर साहब, अगर लोगो के ट्यूबवैल सिंक हो जाएं, जान और माल की भारी तबाही हुई हो और सरकार ने फ्लड रिलीफ एडवाइजरी कमेटी भी बनाई है। क्या उस कमेटी की तरफ से आपके पास कोई सिफारि ा नहीं आई ? सरकार बिजली बोर्ड के साथ बातचीत कर सकते थे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि फ्लड अफैक्टिड एरियाज को बिजली के मामले मे रियायत देने के बारे में सोचा क्यों नहीं गया ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, फ्लड रिलीफ कमेटी की रिर्पोट अभी वसूल नहीं हुई है। राव साहब ने यह फरमाया कि फ्लड अफैक्टिड एरियाज में ट्यूबवैल्ज डूब गए है, मीटर खराब हो गए है। हमारे पास ऐसी काई ि ाकायत कि मीटर खराब हो

गये है या ट्यूबवैल्ज सिंक हो गए है, नहीं आई है और अगर इस तरह की ि ाकायत हमें मिलेगी तो जरूर विचार किया जायेगा।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय के स्टेटमैंट को चैलेन्ज करता हूं। जो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर फ्लड अफैक्टिड एरियाज को देखने जाते है उनको लोंगो की तरफ से दरखास्तें मिलती है। चीफ मिनिस्टर साहब मेवात के इलाके में गए है । हर जगह पर लोगो की तरफ से दरखास्ते दी जाती है कि हमें बिजली के मामले में रियायत दी जाए।

मुख्यमंत्री (चोधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, जहां तक राव साहब के सवाल का ताल्लुक है मै कहना चाहता हूं कि अभी तक इस सिलसिले में मुझे काई ि ाकायत नहीं मिली । हरेक जगह पर यह मांग की गई कि हमारे यहां से पानी निकाला जाए, पम्पिग सैट लगाए जाए। जहा तक फ्लड रिलीफ कमेटी का ताल्लुक है उसकी रिर्पोट नहीं आई है। अब उसकी मियाद बढा दी गई है।

राव बीरेन्द्र सिंहः क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेगें कि जो मैने उनको चिट्ठी लिखी थी क्या उसके अन्दर यह ि ाकायत नहीं थी ? मेरी दरखास्त में इस बात का जिक था और आपने उसका मुझे जवाब भी दिया कि गौर कर रहे है ?

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, जितनी भी दरखावस्ते आती है वे सब कमेटी को फारवर्ड करे देते है। पढ़ने के बाद चिट्ठी फाइनेन्स कमिटी या कमेटी को भेज दी जाती है।

Minimum Pirce Fixed for Paddy,Maize and Millet

***108. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state-

(a) the minimum price fixed by the Government for Paddy, Maize and Millet for the forthcfoming Kharif crop of 1977; and

(b) the quantity of each foodgrain as referred to in part(a) above, proposed to tbe purchased by the Government during the period as referred to in part(a) above?

Food and Supplies Minister(Shrimati Dr. Kamla Verma):

(a) (1) **Paddy**

Coarse	Rs. 77/- per quintal.
Begmi/IR 8	Rs. 79/- per quintal.
Parmal/ Ratna/RP-5-3	Rs. 83/- per quintal.
Basmati	Rs. 88/- per quintal.
(ii) Maize	Rs. 74/- per quintal.
(iii) Millet (Jowar/Bajra)	Rs. 74- per quintal.
(b) The state Government dono propose to purchase any of	

these foodgrains.

श्री ि ावराम वर्मा: मंत्री महोदया जो कीमते बताई गई है वे इस प्रकार है:– 77.00 रूपये, 79.00 रूपये, 83.00 रूपये, 88.00 रूपये, मक्का 74.00 रूपये, ज्वार बाजरा 74.00 प्रति क्विटल। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह कम से कम कीमत है, इससे कम तो कीमत नहीं की जायेगी और इससे उप्श्र नहीं जायेगी ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्मा: स्पीकर साहब, इससे कम कीमत नहीं जायेगी। यह कीमत केन्द्र की और से फिक्स की गई है।

चौधरी राम कि ान: अभी बताया गया है कि इससे कम कीमत नहीं आएंगी। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि अगर कीमत कम हो जायेगी तो सरकार क्या करने का विचार कर रही है ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्मा: स्पीकर साहब, अब जोनल सिस्टम खत्म हो गया है अब तो कोई भी खरीद सकता है, इसके लिए कोई भी बन्धन नहीं है।

कंवर राम पाल सिंह: मंत्री महोदया ने बताया कि पैडी या दूसरी चीजों की(कोर्स ग्रैन) की कीमत फिक्स कर दी गई है। दूसरे उन्होने बताया कि जोनल सिस्टम अब खत्म कर दिया गया

है और कोई भी मार्किट में खरीद सकता है। लेकिन भाव इससे भी नीचे जा रहे है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जब सर्पोर्ट प्राईस फिक्स कर दी गई है तो उससे कम कीमत पर क्यों सरकार बिकने दे ? सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्मा: स्पीकर साहब, अगर स्पोर्ट प्राईस से कीमत नीचे जाएंगी तो सरकार खरीदना भुरू कर देगी।

चौघरी हरस्वरूप बूरा: क्या मंत्री महादेया यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार ने जो कीमत तय की है उस कीमत में और किसान की जा लागत आयी है उसमें कितना फर्क है ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह एक सैपरेट क्वै चन है। इसके लिए ये अलग से नोटिस दे तो बता दिया जायेगा।

चौधरी गंगा राम: क्या मंत्री महोदया बताने का कश्ट करेंगी कि जब मक्की का मूल्य कास्ट आफ प्रोडक ान के हिसाब से 117रूपये प्रति क्विटल है तो फिर सरकार ने यह 75 या 74 रूपये पर क्विटल का भाव क्यों मुकर्रर किया है ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह भी सैपरेट क्वै चन है, इसके लिए अलग से नोटिस चाहिये। वैसे यह सब सैन्टर से सम्बन्धित है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जो कीमते केन्द्र सरकार ने तय की है हरियाणा सरकार ने उन्हे इससे ज्यादा कीमतो की सिफारि ा की थी या कि उन्होने स्वयं की ये कीमते निर्धारित कर दी है।

श्री मति डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने सैन्टर को ज्यादा कीमतो के लिए सिफारि ा की थी लेकिन केन्द्र ने जो कीमते फिक्स की है वह दूसरे राज्यो से तालमेल रखते हुए फिक्स की है। उदाहरण के लिए हमने कोर्स चावल की 85,परमल की 93, मक्की 126, बाजरा 138 आदि कीमते फिक्स की है।

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महादेय,इन्होने जो स्पोर्ट प्राईस इस साल खरीद करने के लिए रखी है उसके लिए कितनी रा ि ा रखी गई है और कौन सी एजेन्सी उस काम के लिए मुकर्रर की है ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार पैडी की खरीद नार्मल नही करती है। एफ.सी.आई. वाले पैसा देते है और हरियाणा सरकार उनके लिए चावल खरीदती है । बाद में उनको दे दिया जाता है । पैडी तो भौलर वाले ही खरीदते है।

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब तो आया नहीं । मै पूछना चाहता था कि अगर इस काम के लिए

एफ.सी.आई. वाले रूपया देते है तो उन्होने इस काम के लिए कितना रूपया रखा है ?

श्री मति डाक्टर कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह भी सैपरेट क्वै चन है, इसके लिए मैम्बर साहिबान अलग से नोटिस दे तो बता दिया जाएगा। वैस पिछले वर्श 90 प्रति ात एफ.सी. आई. ने खरीद कर पैसे दिए। इस वर्श 80 प्रति ात खरीदने की योजना है।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय केन्द्र सरकार ने पैडी और राईस के ऊपर से पाबन्दी हटा दी और अब कोई भी व्यापारी राज्य से बाहर ले जा या ला सकता है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि हमारी हरियाणा सरकार ने अपने व्यापारियो के लिए अभी तक कोई ऐसा कदम उठाया है या नहीं, क्योंकि अभी तक हमारी सरकार ने ऐसी कोई मन्जूरी व्यापारियो को नहीं दी है। इसके कारण है ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्मा: स्पीकर साहब, आदे ा जारी कर दिए है । और व्यापारियो को हमने बाहर ले जाने के लिए इसकी परसेन्टेज पहले से ज्यादा बढा दी है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय इन्हाने केन्द्र सरकार को प्राईस बढाने के लिए मांग की थी पर केन्द्र ने कम कीमत मुकर्रर की है । क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि इससे जो किसान को नुकसान होगा उस बारे में सरकार ने

क्या कदम उठाए है ? दूसरी बात यह है कि क्या जीरो का भाव 88 रूपये कम नहीं है ?

श्री अध्यक्षः वर्मा साहब, पहले जवाब तो आने दो फिर आप बोलिये।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, कास्ट आफ प्रोडक ान इन्हे मालूम नहीं है, कितना रूपया इन्हाने खरीदने के लिए रखा है, यह भी इन्हे मालूम नहीं है। इन्होने केन्द्र को कुछ न कुछ तो रिकमेन्डे ान की होगी। कम से कम इन्हे कास्ट आफ प्रोडक ान का तो पता होना चाहिए कि किसान की कितनी लागत बैठती है। ये तो हर सवाल के जवाब में कह देती है इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए। इनको तो कुछ पता ही नही है । ये हरेक बात को टालने की कोि ा ा कर रही है ?

श्री मती डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर इसके लिए सेपरेट नोटिस दे तो अच्छा होगा। वैसे तो मै उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर माननीय सदस्य ध्यान देते तो किसान की जो लागत आती है यह सब बता दिया है, सैन्टर की नीति भी बता दी है, वैसे बोलना है तो इनकी इच्छा है ।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप इन पुराने बजीरो से हमारी तरफ से दरखास्त कर दे कि नये वजीरों को सुबह तैयारी करवा दिया करे।(हंसी)

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, अगर यह परम्परा हो जाए कि पुराने मैम्बर सवाल ही न पूछे तो नये मैम्बर ही सवाल करेंगे और नये मिनिस्टर की जवाब देंगे। यह ठीक रहेगा ।(हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अगर पूरी इंफर्मे ान ही न मिले तो फिर क्वै चन आवर का ही क्या फायदा ?

श्री अध्यक्षः चौधरी राम लाल जी वधवा जो कि एक पुराने पार्लियामेन्टेरियन है गल्त सीट से बोल रहे है। (हंसी)

चौधरी ि ाव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया । मैने पूछा था कि क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र को यह कहा था कि जीरी की भिन्न–भिन्न किस्म है उसका भाव यह होना चाहिये । ऐसा उन्होने पैदावार की लागत के आधार पर किया होगा लेकिन केन्द्र सरकार ने कम कीमत फिक्स की। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या हरियाणा सरकार ने इस बारे में कोई प्रोटैस्ट किया कि इससे तो किसान का धर भी पूरा नहीं होगा ? इसके साथ–साथ मैने यह भी पूछा था कि जो बासमती जीरी का भाव 88 रूपये पर क्विटल बताया है क्या यह कम नहीं है और ऐसा करने से आगे के लिए बासमति की पैदावार बिल्कुल बन्द होने का खतरा पैदा नहीं होगा।

श्री मती डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, पहले तो उन्होने बासमति और परमल में तीन–तीन रूपये पर क्टिल के

हिसाब से कीमत बढा दी है । और उसके बाद लैवी में उन्होने बढा दी है जिसके कारण किसान काफी मात्रा में चावल बाहर भेज सकेगा। पहले 90 परसेन्ट केन्द्र प्रोक्योर करता था ओर 10 परसैन्ट किसान बाहर बेच सकता था। लेकिन अब इन्होने कोर्स के लिए 20 परसैन्ट की छुट दे दी है और बासमति की 50 परसैन्ट छुट दे दी है । इससे किसान को लाभ होगा ओर वह अपना नुक्सान पूरा कर सकेगा। ाोर एवं विध्न)–

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, मै राव साहब को बता रहा था कि पिछली दफा तो सवाल का जवाब मिलता ही नहीं था। (हंसी व तालियां)

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर होने के बाद आदमी नान–पार्टीमैन हो जाता है ।(हंसी)

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): स्पीकर साहब, आपने बजा फरमाया है।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इनको अभी कितने दिन और लगेगे सीखने में हम उतने दिन चुप रहे।

मुख्यमंत्री चौधरी(चौधरी देवी लाल): और तो ओर स्पीकर साहब को भी बोलने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। (हंसी)

चौधरी रिजक रामः स्पीकर तो जो न बोल वही होता है । (हंसी)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, इन्होने बताया कि बाजरे की कीमत यिा की है। जो हाइब्रिड बाजरा है वह किसानो को मार्किट से 1000 या 1100 रूपये क्विटल मिलता है क्या सरकार उसी प्राइस पर जिस पर वह बाजरा प्रोक्योर करती है, किसानो का देने का कश्ट करेगी ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः स्पीकर साहब, सरकार द्वारा बाजरा प्रोक्योर किया ही नहीं जाता है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया कि जीरी और बासमति की कुल उपज का 80 परसेन्ट और 50 परसेन्ट सरकार खरीदेगी। मै यह पूछना चाहता हूं कि सरकार किस भाव पर खरीदेगी। और किस भाव पर बेचेगी और उस पर कोई सेल्ज टैक्स भी चार्ज किया जायेगा?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः आनरेबल मैम्बर जरा सवाल को फिर क्लीयर कर दे।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब आप जरा सवाल को और क्लीयर कर दे।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह है कि सरकार जो प्रोक्योर करेगी उसे प्रोक्योरमेंट के भाव पर बेचेगी या मुनाफा लेकर बेचेगी ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः स्पीकर साहब नामिनल चार्जिज पर उसको बेचा जायेगा।

चौधरी रिजक रामः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया यह बताएं कि सरकार नो–प्रोफिट नो–लोस पर बेचना चाहती है या कोई प्रोफिट लेना चाहती है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, कोर्स चावल 152.57 रूपए क्विटल के हिसाब से खरीदते है और रिटेल में उसे 169.40 रूपए के हिसाब से बेचते है । परमल की खरीद 176.59 रूपये के हिसाब से की जाती है और 194.00 के हिसाब से उसे बेचा जाता है । बासमती 187.16 रूपये खरीदने के बाद 205. 00 रूपए पर बेचा गया और बासमति जो कि बढिया है वह 237.12 के हिसाब से खरीद सकने के बाद 257.00 रूपए बेचा गया । इनके ऊपर जो रिटेल मार्जिन है वह सेल्ज टैक्स एण्ड कास्ट आफ बेगज आदि लगाकर है ।

चोधरी रिजक रामः जो रेटस मंत्री महोदया ने बताया है उससे स्पश्ट है कि पीछे वाली सरकार ने जो जीरी और बासमति प्रोक्योर करके बेची उस पर उसने मुनाफा कमाया। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार भी उसी नीति पर

चलेगी या उस नीति को बदलेगी ? दूसरे क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि फूड कार्पोरे ान ने जो बासमति चा जीरी सरकार से खरीदी उस दूसरी कन्ट्रीज मे कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया ? क्या उस मुनाफे को किसानो के पास पहुंचाने की सरकार के पास काई तजवीज है ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः बासमति को एफ.सी.आई. नहीं खरीदती तो सिर्फ स्टेट गवर्नमैंट की खरीदती है। जो कोर्स चावल है वह एफ.सी.आई. को दिया जाता है । इस वर्श प्रोफिट के अन्दर 5रूपये का मार्जिन ज्यादा रखा गया है जैसे तीन रूपये पैडी के अन्दर बढ़ाए गए है और दूसरो में भी ।

श्री लहरी सिंह महरः स्पीकर साहब, कुछ मन्डियां ऐसी है जहां फिक्सड रेट से कम पर चीजे बिकती है और वहां पर सरकारी खरीद नहीं हो रही है । क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगीं कि वहां पर क्या इंतजाम किया जाएगा। ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी कोई भी ि ाकायत आएगी तो उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा ।

सरदार सुखदेव सिंह– क्या मंत्री महोदया, बताएंगी कि जिन किसानो को कम रेट मिले है उनका नुकसान किस तरह से पूरा किया जायेगा ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, यह सैन्ट्रल गवर्नमैंट की पालिसी है । इस विशय पर हम विचार कर सकते है ।

राव वीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महादेया बताएंगी कि चावल की कीमते जो इस वक्त मण्डी में है उसको देखते हुए और जो चावल की मूवमैंट पर रिस्ट्रक ान हटी है उसको देखते हुए जिस प्राइस पर सरकार खरीदना चाहती है उस कीमत पर इनको चावल मिल सकेगा ? दूसरे क्या सरकार को इस बात का इल्म है कि इस वक्त चावल की कीमते मंडी में 7–8 रूपये किलो तक है ? क्या कीमतो को देख कर सरकार ने काई कदम उठाया है कि अपने स्टाफ से चावल बेचकर कीमतो को कम किया जाए ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः सरकार फेयर प्राइस भाप्स पर बासमती चावल दे रही है। क्योंकि हम सिर्फ बासमती ही प्रोक्योर करते है इसलिए बासमती ही दी जाती है। हरियाणा में चावल कीमत सात–आठ रूपया नहीं हो सकती। राव साहब को गल्ती लगी है।

चौधरी संत कंवरः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि क्या सरकार ने हरियाणा के किसान की कास्ट आफ प्रोडक ान का ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को रेट तय करने के लिए लिखा था ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः इसका उतर पहले ही दिया जा चुका है । सैंटर के फूड मिनिस्टर साहब के साथ हमारे मुख्यमंत्री का पूरा विचार विम र्श हुआ था उसके बाद ही यह रेट तय हुए है।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, जब किसी सरमाएदार के कारखाने में कोई नुकसान हो जाता है तो हरियाणा सरकार उसको कम्नसेट करती है। मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चूंकि हमारे किसानो के मक्की , बाजरा और धान 99 प्रति ात तबाह हो गए । इसलिए क्या सरकार उनको भी कम्पनसेट करेगी ? अगर करेगी तो कितने परसैंट करेगी ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल की इसके साथा कोई रैलेवैंसी नहीं है ।

चौधरी लाल सिंहः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि कणकी जो गरीब लोग खाते है उसका क्या भाव है।

श्रीमती डाक्टर कमला वर्माः कणकी पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। वैसे इसका इस सवाल से कोई संबंध नहीं हैं।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि हरियाणा सरकार ने मक्की, बाजरा और ज्वार के केन्द्र सरकार से क्या भाव मांगे थे और दूसरी बात यह है कि जब हमे पूरे भाव नहीं मिले तो सरकार ने किसानो को क्या–क्या सुविधाएं देने की योजना बनाई है ताकि उसका खर्चा पूरा कर सके ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: हमने जो प्राइस मांगी थी वह कोर्स के लिए 85 रूपये परमल के लिए 93 रूपये मांगी थी। बासमति पर कोई भाव तय नहीं हुआ था, बाजरा 138 रूपये और मक्की के लिए 126 रूपये मांगे थे। किसानो को क्या लाभ हुआ वह यह है कि एक तो वे 20 प्रति ात फी सेल कर सकेगें जिससे उनको लाभ होगा दूसरे हरियाणा सरकार ने खाद ओर पानी की कीमतो का धटा कर भी उन्हे राहत देने का फैसला किया है।

कंवर राम पाल सिंह: मंत्री महोदया ने बताया कि 80 प्रति ात लैवी लगा दी है और दूसरी बात कही कि वे सिर्फ बासमती प्राक्योर करते है। तो फिर जब सरकार मोटा चावल प्रोक्योर नही करती है तो 80 प्रति ात लैवी लगाने का क्या लाभ होगा ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा: कोर्स चावल की यहां पर खपत नहीं होती क्योंकि लोग इसे खाते नहीं है इसे एफ.सी.आई. वाले सीधा खरीदते है।

Poly-steel Ltd., Hissar

***125. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for industries be pleased to state-

(a) the share of Haryana Government in Poly-Steel Ltd. Hissar;

(b) the total capital investment in the said plant; and

(c) the date since when the said plant is functioning and the yearwise balance-sheet thereof be laid on the table of the House ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन):

(ए) रूपये 10 लाख

(बी) रूपये 420 लाख (लगभग)

(सी) यह प्लांट नवम्बार 1975 से कार्य कर रहा है। वर्श 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 की बैलेंस भीट सदन में प्रस्तुत की जाती है।

राव बीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस प्लांट मे किस किस के हिस्से है ?

डाक्टर मंगल सैनः हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट कार्पोरे ान और पब्लिक का हिस्सा है, इनका कोलैबोरे ान है ।

राव बीरेन्द्र सिंहः वे कौन कौन से मोटे–माटे आदमी है, उनके नाम बता दे ।

डाक्टर मंगल सैनः जितने भी मोटे–मोटे होगे वे राव साहब के साईज के मुकाबल में कम ही होगे.....(हंसी)

चौधरी रिजक रामः क्या मंत्री महोदय बताऐंगे कि पालीस्टील लिमिटिड हिसार में धाटा है या नफाफ

डाक्टर मंगल सैनः लगभग 1 करोड़ रूपये का घाटा है ।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मंत्री महादेय बताएगे कि यह जा 1 करोड़ रूपये का घाटा है, इसका सालवार ब्योरा क्या है, किस–किस साल मे कितना–कितना धाटा हुआ है ?

राव बीरेन्द्र सिंहः यह भी बता दे कि आपके आने के बाद कितना घाटा रहा है ?

डाक्टर मंगल सैनः अगर आपक इसके लिए अलग नोटिस दें तो अच्छा होगा, जवाब दे दिया जायेगा। बाकी राव साहब ने जो कहा कि आपके आने के बाद कितना धाटा हुआ है, मै उन्हे सूचित करना चाहता हूं कि हमारे आने के बाद मामला सम्भला है, मै खुद वहां पर गया था और मैने उनको तम्बीह की है ।

श्री मूल चन्द मंगलाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस घाटे की पूर्ति के लिए क्या स्टैप्स लिए है ?

डाक्टर मंगल सैनः पावर के ऊपर जो कट लगा करती थी उसको खत्म कर दिया और यह भी कहा कि इस प्लांट को को कट से पूरी तरह मुक्त किया जाए, पूरी बिजली मिले। दूसरे फाइनैि ायल असिस्टैंस के लिए हमने सैन्टर को रिक्वैस्ट की, तीसरे रा–मैटीरियल जो बाहर से इम्पोर्ट होता था उस पर रिस्ट्रिक ान थी, इस रिस्ट्रिक ान को लिबरेलाईज करने के लिए

सैन्ट्रल गवर्नमैंट को लिखा और चोथे इसकी मैनेजमैंट के लिए होल डायरैक्टर एप्वायंट करने जा रहे है।

फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, जिन कंसर्न्ज के अन्दर धाटा है या धाटा किन्ही खास आदमियो की वजह से हुआ है ? क्या मंत्री महोदय इनकी इन्क्वायरी करावाएंगे और गुनहागारो को सजा देंगे ?

डाक्टर मंगल सैनः पिछले दिनो ऐसे कोलेबोरे ान्ज जिन्होने हेराफेरी की है, हमने उनके खिलाफ ब्रीच आफ ट्रस्ट का मामला दर्ज किया है।

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, कई ऐसे आदमी है, जैसे गुरमुख सिंह है, इन्होने वहां पर चार पांच फर्म बना रखी है, चाहे उन फर्मो में उनके हिस्से है चाहे वे उनके रि तेदारो के है। यह आदमी मार्किट रेट से 25 या 25 परसैंट रूपये ज्यादा प्रति टन के हिसाब से उनसे माले ले लेता है और उसको नाजायज फायदा पहुंचाता हैं। अगर किसी दूसरे ने कम्पीटी ान मैं माल दे भी दिया तो उसको पेमेंट नही हाने देता। क्या ऐसे मामलो की इन्कवायरी करवायेंगे ।

डाक्टर मंगल सैनः मै आनरेबल मैम्बर का बड़ा भाुकगुजार हूं कि उन्होने मुझे जानकारी दी। मै जरूर इन्क्वायरी करवाऊंगा और अपराधी को सजा दी जायेगी।

चौधरी मेहर सिंह राठीः इसके बारे में मैने मिनिस्टर साहब के दफतर में दरख्वास्त 11–12 दिन पहले दी थी। आप इसकी इन्क्वायरी करवाएं।

श्री नारायाण वर्माः क्या मंत्री महादय बताएंगे कि हरियाणा पोलीस्टील में कितने बेरोजगार लोगो को रोजगार देने का प्रावधान है और भर्ती करने की क्या पद्वति अपनाई जा रही है ?

डाक्टर मंगल सैनः जो प्र न पूछा गया है उसका तो मैं अभी उतर दे सकता हूं लेकिन पोलिस्टील लिमिटेड में कैसे नोकरियां दी जाती है, वहां पर क्या प्रकिया है , क्या मैथेड अडाप्ट किया हुआ है, इसके लिए अलग नोटिस दे, जरूर दिया जायेगा।

चोधरी पीर चन्दः मंत्री महोदय ने जो 1 करोड़ रूपये का नुक्सान बताया है, क्या यह नुक्सान अफसरो की वजह से हुआ है या बेचने–खरीदने के कारण घाटा पड़ा है ?

डाक्टर मंगल सैनः यह घाटा कई कारणो से हुआ है। सबसे अधिक पहला कारण यह है कि उस जमीन की जहां पर प्लांट स्थित है, ज्योग्रफिकल लोके ान ठीक नहीं है, दूसरा कारण रा–मैटीरीयल, स्क्रैप जो फरीदाबाद में मिलता है उस पर भाड़ा लगता है, खर्च ज्यादा पड़ता है; तीसरे जब प्लांट लगाया था उस वक्त सोचा गया था कि भाव कम रहेगे लेकिन बाद मे भाव

बढ़ गये; चौथे बिजली की कट लगती रही, इस तरह कई कारण है जिन के कारण टोटा पड़ता रहा। अभी जैसे कि राठी साहब ने मेरा ध्यान आकर्शित किया है उसकी वजह से घाटा हुआ है।

चौधरी रिजक रामः मिनिस्टर साहब ने इस घाटे का पूरा करने के लिए तीन चार कदम उठाए जाने का जिक्र किया है । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जहां सरकार का हिस्सा है, जिन अदायरों में सरकार का हिस्सा है, चाहे प्राइवेट कंसर्न्ज है, चाहे ट्यूबवैल्ज है, या कई दूसरे अदायरे है, उनमें बिजली का कट खत्म करने का विचार है ?

डाक्टर मंगल सैनः ट्यूबवैल्ज का मामला मेरे से सम्बन्धित नहीं है।

चौधरी रिजक रामः मंत्री महोदय ने कहा कि इस प्लांट पर बिजली का कट नहीं है । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि इसी प्रकार के दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिटस है, क्या उन पर भ्झी यही असूल लागू है या नहीं ?

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब मै आपके द्वारा मानीय सदस्या से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हमने यह नहीं कहा कि बिजली की रैगुलर सप्लाई नहीं मिलनी है, सप्लाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

चौधरी सन्त कंवरः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस प्लांट का मैनेजिंग डायरैक्टर कोई प्राइवेट आदमी है ?

डाक्टर मंगल सैनः इसके मैनेजिंग डायरैक्टर महोदय बाहर के आदमी थे, वे छोड़ कर चले गए है । अब एक टैम्परेरी डायरैक्टर रखा है । परमानैंट डारैक्टर मार्किट से लेने का बन्दोबस्त कर रहे है।

स्वामी अग्निवे ाः स्पीकर साहब, पोलिस्टील लिमिटिड प्लांट ज्योग्राफिकल प्वायंट आफ व्यू से फरीदाबाद से काफी दूर पड़ता है । दूर हाने के कारण घाटा होता है । क्या सरकार इस घाटे को बरदास्त करती रहेगी या इसको किसी और जगह पर ि ाफट करने पर विचार करेगी।

डाक्टर मंगल सैनः ि ाफ्ट करने से टोटे में और टोटा हो जाएगा।

श्री मूल चन्द जैनः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस फर्म में गवर्नमैंट का भोयर किस रूप में है–इक्विटी भोयर है, प्रेफ्रे ि ायल भोयर है या लोन देती है।

डाक्टर मंगल सैनः दस लाख रूपये का इक्विटी भोयर है।

चौधरी गंगा रामः बहुत से अदोर ऐसे है जिन को ऐसे स्थानो पर लगाया गया है जहां बिल्कुल कामयाब हो ही नहीं सकते। मै आपके द्वारा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा विचार रखती है कि ये प्लांट ऐसी जगहो पर ि ाफट कर दिये जाएं जहां पर रा–मैटीरियल मिल सकता हो ? ऐसा

करने से वे कामयाब भी हो सकते है । मिसाल के तोर पर सोनीपत में भूगर मिल लगाया है, वह बिल्कुल मरधट के ऊपर लगा दिया और ऐसे एरिया में लगाया है जहां टमाटर, गाजर आदि होते है । जहां बहुत ज्यादा गन्ना होता है वहां पर भूगर मिल लगानी चाहिए।

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, मै अपने आदणीय अजीज और माननीय सदस्य से निवेदन करूगा कि, जैसे आपने कहा कि वहां गाजर मूली बिकते है, यह मिल कोई गाजर मूली ता है नहीं जिसको आसानी से ि ाफ्ट किया जाए, वह तो कारखाना है। इस पर 4 करोड़ रूपए की लागत है । इसको ि ाफ्ट करने में बड़ी मजबूरी है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, इन्होने माननीय सदस्य को 'अजीज ' कह दिया, भाायद वे इनसे बड़े हो..... (हंसी)

डाक्टर मंगल सैनः मैने अजीज भी कहा है और माननीय सदस्य भी कहा है।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, मै समझने का प्रयत्न कर रहा था कि पोलिस्टील क्या होता है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पोलिस्टील क्या होता है और किस काम आता है..... (हंसी)

चौधरी पीर चन्दः दो तीन सदस्यो ने इस बात पर चर्चा की है कि अगर धाटा है तो इस प्लांट को हिसार से उठाया जाए। कहीं मंत्री महोदय के दिमांग में यह बात तो नहीं बैठ गयी कि धाटे के कारण इसको उठाया जाये । हिसार में और भी ऐसी फैक्ट्रियां है जो मुनाफा कमाती है। इसको उठाने की बात दिमांग में नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नहीं है ।

श्री फतेह चन्द विजः मंत्री महोदय ने बताया कि मैनेजिंग डारैक्टर भाग गया। क्या वे बताएंगे कि वह बता कर भागा या वैसे ही भाग गया ?

डाक्टर मंगल सैनः वह अपना भोयर छोड़ गया था इसलिए चला गया। ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। (विध्न)

लाला बलवन्त राय तायलः क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि इसमें कितने डायरैक्टर्ज है, सरकारी डायरैक्टर्ज कितने है और प्राइवेट कितने है ?

डाक्टर मंगल सैनः वर्तमान स्थिति मे जो बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज है वह इस प्रकार हैः—

श्री वी. के. सिब्बल, आई.ए.एस चेयरमैन

श्री के. के. भार्मा, आई.ए.एस मैनेजिंग डारैक्टर

श्री के. आर. पुनिया, आई.ए.एस डायरैक्टर

श्री एल. एम. गोयल, आई.ए.एस डायरैक्टर

श्री निरंजनदत डायरैक्टर

श्री पी. ए. महरोत्रा डायरैक्टर

श्री विक्रम प्रसाद डायरैक्टर

श्री आर. सी. ढल डायरैक्टर

श्री जी. एस. मुसाफिर ऐगजैक्टिव डायरैक्टर

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, मैने तो यह मालूम किया था कि कितने सरकारी है और कितने गैर–सरकारी ?

श्री अध्यक्षः वह तो आपने देख लिया होगा क्योंकि उन्होने नाम पढ़ दिए है । (विध्न)

डाक्टर मंगल सैनः श्री जी.एस. मुसाफिर तो निि चत ही प्राईवेट हैं और बाकी जैसे श्री निरंजनदत, श्री विक्रम प्रसाद और श्री आर. सी. ढल, भी भाायद बाहर के है।

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, पहले इसका फैसला करा दे ।

श्री अध्यक्षः इसका डैफिनिट आन्सर मिल जायेगा।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि मैनेजिंग डायरैक्टर छोड़ कर भाग गया। मै उनसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है क्योंकि वह कुछ लेकर ही भागा होगा ?

डाक्टर मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, भागने से मेरा मतलब छोड़ जाने से था और वह रातो रात नहीं भागा था वह दिन दिहाड़े गया था।

चौधरी मेहर सिंह राठीः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फरीदाबाद में कौन सा रामैटीरियल पैदा होता है ? मेरे ख्याल के मुताबिक तो रा–मैटीरियल तो दिल्ली की मार्किट से आता है।

डाक्टर मंगल सैनः मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं था कि वहां वह खेत में उगता है या पेड़ पर लगता है। मेरे कहने का तात्पर्य तो यह था कि वहां वह छोटे उद्योगों में तैयार होता है। राठी साहब का यह कहना भी ठीक है कि दिल्ली भी बड़ी भारी मार्किट है।

श्री गुलजार सिंहः क्या मिनिस्टर साहब बतलाने की कृपा करेंगे कि पोलिस्टील लिमिटिड में जो करोड़ों रूपये का घाटा है इसको मुनाफे में बदला जा सकता है ? अगर इसे मुनाफे में नही बदला जा सकता और इसने घाटे में ही रहना है तो क्यों न इसको बंद कर दिया जाए ?

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपके माध्यम से इस माननीय सदन को मैं यह बात निवेदन कर चुका हूं कि हमारी ईमानदारी से कोि ा ा है कि इस घाटे को पूरा करें और आयंदा घाटा न हो। अगर लगातार टोटा पड़ता चला गया तो विचार कर लेंगे।

श्री मूल चन्द जैनः क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि यह जो घाटा इस कन्सर्न में हो रहा है इसकी जिम्मेदारी हमारी इस मौजूदा सरकार के अफसरों पर है या पहली सरकार के अफसरों पर है ?

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आदरणीय बुजुर्ग सदस्य महोदय को निवेदन कर दूं कि यह तो पहली सरकार के समय से ही बहुत मात्रा में घाटा हो रहा है। इस सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने, तो इस घाटे को रोकने की कोि ा ा की है ताकि जनता के गाढ़े पसीने का पैसा बचाया जा सके।

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, मैं मालूम करना चाहता हूं कि हरियाणा में मिनि–स्टील प्लांट कितने हैं ?

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्होंने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दिया गया है। अगर ये कभी इस तरह का सवाल करेंगे तो इसका भी जरूर जवाब देंगे।

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से मालूम करना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह कहा कि

हिसार में रा–मैटीरियल नहीं होता बल्कि फरीदाबाद में होता है और यह कारखाना गलत जगह लग गया है जबकि हिसार में ही इसी तरह का दूसरा प्लांट भी लगा हुआ है, यह बैलैन्स ाीट देख कर अपनी राय बनाई है या राय बनाने का कोई और कारण है ?

डाक्टर मंगल सैनः यह तो मैंने विभिन्न कारणों में से एक कारण बताया है। अभी एक और सदस्य चौधरी पीरचन्द जी इसको ि ाफ्ट करने की बात कह रहे थे लेकिन मैंने उन्हें बताया कि अभी ऐसा कोई विचारनहीं है और मुझे यह कन्फैंस करने से भी संकोच नहीं है कि ऐसे कोलैबोरेटर्ज द्वारा लगाई हुई इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडस्ट्री में बड़ा फर्क हैं। इसमें तो घाटा है ही नहीं।

चौधरी लाल सिंहः मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो पौलीस्टली फैक्टरी हैं इसमें हरियाणा के मुलाजिम हैं या बाहर के हैं ? अगर बाहर के हैं तो क्या उनकी जगह हरियाणा के लगाइए जाएंगे ?

(कोई उतर नहीं दिया गया)

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, स्टेट के तमाम हैड आफ दी डिपार्टमैंट्स आई.ए.एस. अफसरान, इस प्लांट की मैनेजमैंट में लगा रखे हैं लेकिन फिर भी घाटा है। क्या मिनिस्टर साहब इन हालात में ऐसा सोचते हैं कि किसी टैक्नीि ायन की या ऐक्सपर्ट की ऐडवाइस वे लें क्योंकि इस स्टेट की

हालते–इन्तजामिया से उन्होंने देख लिया होगा कि यहां ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल फेल हो चुकी है ?

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे आदरणीय मित्र ने यह फरमाया कि गवर्नमैंट के सारे हैड आफ दी डिपार्टमैंट्स इसमें लगा दिए गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी घाटा चल रहा है और क्या इन हालात में मैं किसी टैक्नीयि ायन की ऐडवाइस लेने को तैयार हूं। स्पीकर साहब, मैं ओपन माइन्ड का आदमी हूं, जरूर उनकी ऐडवाइस लूंगा और उसमें जो घाटा है उसे रोकने की कोि ा ा करूंगा।

लाला बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि ऐग्जैक्टिव डायरैक्टर भाग गया है। मैं मिनिस्टर साहब से यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या कहीं वही तो सरे घाटे का जिम्मेदार नहीं था ? क्या सरकार उसकी इन्कवायरी करवाएगी ?

डाक्टर मंगल सैनः मैं तायल साहब की बात की जांच कर लूंगा और अगर वह जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ जरूर इन्कवायरी कराएंगे।

स्पीकर साहब, मेरे मित्र तायल साहब ने एक बात पूछी थी उसका मैं जवाब अभी दे देता हूं। कल किसने देखा। इन्हौंने पूछा था कि डायरैक्टर्ज में से कौन प्रायवेट हैं, कौन नोमिनेटिड हैं ? इसके बारे में निवेदन यह है कि श्री पी.एन. महरोत्रा, इंडीयन

फाइनैन्स क्रैडिट इंस्टिच्यू ान के प्रतिनिधि हैं, श्री विक्रम प्रसाद एस.आई.एल. के प्रतिनिधि हैं और श्री आर.सी.ढल. आई.डी.बी.आई. के प्रतिनिधि हैं और दूसरे प्राईवेट हैं जैसे श्री निरंजनदत और श्री जी.एस. मुसाफिर।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, तायल साहब ने जो सप्लीमेंटरी किया था उसका जवाब नहीं मिला। मिनिस्टर साहब ने तो दूसरी चीज ही पढ़ दी। यह क्या तरीका है सवाल जवाब का ? जरा आप भी इन्हें कुछ कहें।

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, जवाब राव साहब के मुताबिक नहीं है। राव साहब के मुताबिक हो भी नहीं सकता। जवाब तो हमारे मुताबिक है और यह इनकी बरदा त करना ही पड़ेगा। मैने पहले पार्ट का भी जवाब दे दिया है।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, मै उद्योग मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं। कि जो बैकवर्ड एरियाज है जैसे सफीदों, गोहाना जहां पर अभी तक इन्डस्ट्री नही लगायी गई, क्या वहां उन पिछड़ै हुए इलाकों में इन्डस्ट्री लगाने की स्कीम है?

डाक्टर मंगल सैनः जब से जनता पाटी की सरकार पावर में आयी है तब से देहातों के विकास के लिए हर जिले में दस देहातों के अन्दर उद्योग लगाने का फैसला किया गया है देहातों में तो हमारे पढ़े लिखे युवक है उनकों भी आगे बढ़ने का

मौका दिया जायेगा। पिछड़े हुए इलाकों का जरूर ख्याल रखा जायेगा।

लाल बलवन्ता राय तायलः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बड़ा मोटा और लम्बा–चौड़ा जवाब दिया है।

श्री अध्यक्षः तायल साहब, इस प्र न पर कम से कम बीस मिनट लग गए है। (ाोर)

लाला बलवन्त राय तायलः यह ठीक है कि 20 मिनट रहा लकिन 20 मिनट में मैने तो केवल दो ही सप्लीमेंटरी किये है।

श्री अध्यक्षः नही, आपने तीन सप्लीमेंटरी किये है। (विध्न)

डा० मंगल सैनः जी हा, तायल साहब ने केवल तीन सप्लीमेंटरी किये है। (ाोर)

लाल बलवन्त राय तायलः अभी इस सवाल के बारें में कुछ फैक्ट्स आने बाकी है।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, 20 मिनट में 18 मिनट तो डाक्टर साहब ने अपनी एक्टिंग में लगा दिये।

डाक्टर मंगल सैनः मै तो बड़ा मुख्तसर सा आदमी हूं, प्रिसाइज सा आदमी हूं और प्रिसाइज सी बात करता हूं।

श्री अध्यक्षः क्वै चन आवर खत्म हुआ।

लाल बलवन्त राय तायलः स्पीकर साहब, आपकी मेहरबानी हो तो कल के लिए 10 सप्लीमैंटरी की और इजाजत दे दें क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फ्राड है और सही पोजी ान का निचोड़ आ जायेगा।

श्री अध्यक्षः कल के लिए कोई टाईम नही दिया जा सकता।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र न तथा उनके लिखित उत्तर

***130 Ch. Gajraj Bahadur Nagar:** Will the Minister for food and supplies be pleased to state—

(a) The total number of Primary Health Centers in District Gurgaon; and

(b) The total number of Health centers which are proposed to the opened in District Gurgaon, in the year 1977-78?

खाद्य एंव पूर्ति मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा):

(क) 13

(ख) कोई नही

Loan Advanced by the Co-operative societies

***61 Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) The total amount of loan advanced by the Co-operative societies during the years 1973-1974. 1974-1975, 1975-1976, 1976-77 and 1977-78 to date separately;

(b) The total amount of loan recovered by the co-operative societies during the year 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77 and 1977-78 to date separately; and

(c) The total amount of loan which has not been recovered by the co-operative societies, for more than two years and five years separately?

सिचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(ए) (बी) तथा (सी): स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी जाती है।

(अ) सहकारी समितियों द्वारा वर्श वार दिये गये ऋण की रा ि ा

रा ि ा लाखों में

वर्श	रा ि ा		जोड़
	अल्पकालीन	मध्यकालीन	

1973—74	2,914,.39	1,088.50	4,002.89
1974—75	3,594.18	1,585.17	5,179.35
1975—76	4,479.83	1,513.89	5,993.72
1976—77	7,309.20	1,583.59	8,892.79
1977—78	1,478.02	284.88	1,762.90
(1—7—77 से 30—9—77)			
(ब) सहकारी समितियों द्वाराकी गई वसूली रा ि ा:—			
1973—74	2,772.93	590.30	3,363.23
1974—75	2,886.44	825.31	3,711.75

1975–76	3,727.99	994.54	4,722.53
1976–77	5,583.45	1,094.20	6,677.65
1977–78	365.79	33.32	399.11
(1–7–77 से 30–9–77)			

(स) सहकारी समितियों द्वारा वसूल न किये ऋण की राि ाः–				
(i)	दो से अधिक	391.41	9.20	400.61
(ii)	पांच से अधिक	172.84	2.24	175.08

Murder Cases.

***94 Ch. Birinder Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The total number of murders committed since the present Government took over after the General Elections of the vidhan Sabha in the state to-date;

(b) The number of murder cases out of those referred to in part (a) above brought on record and traced out; and

(c) The number of persons murdered belonging to scheduled castes?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(अ) 86

(ब) क्रम I: 86 और 73

(स) 8

Complaints against Chairman Central Co-operative Bank, Mohindergarh

***102 Sathi Ayodya Parshad:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) Whether any complaints against the chairman of the central co-operative bank, Mohindergarh for committing irregularities by him were received by the government during the last five years; if so, whether any enquiry has been conducted thereon; and

(b) Whether any officer of the Haryana Land Mortgage Bank visited the foreign countries during the last five years, if so, the number of such visits together with the amount spent from the public money on such visits along with the names of officers who made foreign visits?

सिचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) जी हां, इस मामले में जांच हो चुकी है।

(ख) जी हां, हरियाणा राज्य भूमि विकास बैक लि० चण्डीगढ़ के तीन अधिकारियों द्वारा पिछले पांच वर्श में विदे ा यात्रा की गई है। इन यात्राओं से सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। इन यात्राओं पर व्यय पब्लिक धन से नही किया गया।

सूची

क्रमांक	नाम	पद	जिन दे ाों की यात्रा की गई	यात्रा की अवधि
1.	श्री आर.एस. गिल	सहायक सचिव (विधि)	वर्तानिया (कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत ट्रेनिग पर)	7—7—1975 से 30—10—1975
2.	कैप्टन भाी ा राम	भूतपूर्व प्रधान	साऊथ ईस्ट एि ायन कन्ट्रीज जैसा	27—10—1976

			कि थाईलैंड, ताईवान, हांगकाग, जापान, रिपब्लिक आफ कोरिया तथा मलेि ाया	से 10—11—1976
3.	श्री फूल चन्द	भूतपूर्व निदे ाक	जैसा ऊपर	जैसा ऊपर

Supply of Electricity

***109 Ch. Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) The number of hours for which the electricity was supplied daily to the farmers for agricultural purposes in the quarter falling from 1st April, 1977 to 30th June, 1977;

(b) The number of hours for which electricity is supplied to the farmers during the period from 1st July, 1977, to 31st October, 1977; and

(c) Whether there is any proposal under consideration of the Government to lay the electric lines in such a way that power break-down may not occur frequently; if so, the details thereof?

सिचाई एवं विद्युत मंत्री (वीरेन्द्र सिंह):

(क) किसानों को कृशि के लिए प्रतिदिन बिजली देने के घण्ओं की माहवार संख्या इस प्रकार है:–

मास	प्रति दिन बिजली दिए जाने के घण्टों की संख्या
अप्रैल 1977	8 घंटे से 14 घंटे
मई 1977	14 घण्टे से 22 घण्टे
जून 1977	10 घण्टे से 22 घण्टे

(ख) किसानों को जुलाई में 10 से 24 घण्टे प्रतिदिन तथा अगस्त में 8 से 16 घण्टे प्रतिदिन बिजली दी गई थी। सितम्बर 1977 में धान उगाने वाले क्षेत्रों में 14 घण्टे से 16 घण्टे तथा बाकी क्षेत्रों में 5 से 8 घण्अे प्रतिदिन बिजली दी जा रही थी। अक्टूबर, 1977 मास में 10 घण्टे से 14 घण्टे तक प्रतिदिन, किसानों को बिजली देने की संभावना है।

(ग) हां। बोर्ड के पास ब्रेक डाउनों की संख्या कम से कम करने के लिए योजनाएं है। इन योजनाओं का लागू करने के लिए चालू वित्तीय वर्श में 1.43 करोड़ रूपये की रा ि ा गई है।

The Haryana State Small Industries corporation Ltd. Haryana

***129 Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for industries be pleased to state—

(a) The date on which the Haryana State small industries and export corporation was set up in Haryana;

(b) The names of commodities with quantity thereof in each case separately for which it got quota from its date of inception till 30-09-1977; and

(c) the number and names of small scale industries in Haryana to which it rendered help?

Industries Minister (Dr. Mangal Sain):

(a) 16 July, 1967.

(b) A statement is laid on the table of the House.

(c) The time and Labour involved in compiling the information will not be commensurate with any possible benefits to be obtained.

STATEMENT

Types of Material Handled by the Corporation for the last then years in quantity (Metric tonnes)

Year	Iron & Steel	Pig Iron	Mutton Tallow Fatty Acid	Stainless Steel	Imported Sheets	Cotton & Syapple yarn	Hard Coke	Cement	Zinc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1967-68	450	1200	-	-	-	-	-	-	-
1968-69	1972	6260	400	-	-	-	-	-	-
1969-70	2652	15160	566	171	-	-	-	-	-
1970-	10982	8000	823	72.987	1315	-	-	-	-

71									
1971-72	17916	16305	1028	15	-	-	-	-	-
1972-73	22243	15736	369	104	-	9710 (Pales)	-	-	9
1973-74	22874	20056	531	85	-	-	4912	-	137
1974-75	15909	22152	310	-	-	-	34185	65343 bags	14
1975-76	14303	10605	145	-	-	-	24489	94612 bags	394
1976-77	20887	26532	327	-	-	-	21357	11185 bags	175
July, 1977 to sept.	7148	8115	15	-	-	-	5261	22350 bags	100

1977									

Upgradation of schools in district Gurgaon

***131 Ch. Gajraj Bahadur Nagar:** Will the Minister for Education be pleased to state the total number of Primary and Middle schools which are proposed to be upgraded in District Gurgaon daring the year 1977-78?

ि ाक्षा मंत्री (कर्नल राव सिंह): यह मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Water supply schemes in the state

23. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state—

(a) The district-wise total number and names of the water supply schemes inthe state at present;

(b) The district-wise total number of villages covered by the water supply schemes in the state at present;

(c) The number of public drinking posts provided in the Mohallas of the persons belonging to scheduled castes in each village;

(e) Whether the Government has received any complaint in connection with the supply of drinking water in the mohallas of the persons belonging to scheduled castes in the state to date; and

(f) if the reply is in the affirmative then the copy or copies of the complaints/complaints be laid on the table of the House and whether the complaints have been redressed?

Interim Reply

Subject: Unstirred Assembly Question No. 23 Extension of time.

The reply to unstirred Assembly Question No. 23 Appearing in the list of unstirred questions for the 19the October, 1977 in the name of Rao Dalip Singh, M.L.A. is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

Minister for Irrigation & Power

To

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha

Chandigarh

U.O. No. 7666—PWIV (4)—AQ-77, dated Chandigarh, the 1977

Ambulances in the State

24. Rao Dalip Singh: Will the Minister for food and supplies be pleased to state—

(a) The district wise total number of ambulances inthe state at present;

(b) The district wise total number of ambulances out of those referred to in part (a) above which are not in working order in the sate;

(c) The rates at which the ambulance is provided to the patient; and

(d) Whether there is an proposal under consideration of the Government to increase the number of ambulances in the state?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा): राज्य मे एम्बूलैंस सर्विसिज उपलबध करना सैन्ट जोहनएम्बूलैंस एसोसिये ान, ब्रांच हरियाणा की जिम्मेवारी है। उनके पास 33 एम्बूलैसीज है। जिले वाईड विवरण निम्न प्रकार। इसके अलावा दो एम्बूलैस राज्य सरकार के पास है जिनमें एक बी.के. अस्तपाल, फरीदाबाद तथा दूसरी सिविल अस्पताल नारनौल में है। दो मैडीकल कालेज रोहतक के पास है:—

(क) 37

अम्बाला 5 (एक साकेत अस्पताल, चंडीमन्दिर को मिलाकर)

भिवानी	3
गुड़गांवा	3 (एक सरकारी एम्बूलैंस को मिलाकर)
हिसार	4
जींद	3
कुरूक्षेत्र	3
करनाल	4
महेन्द्रगढ़	3 (एक सारकारी एम्बूलैस को मिलाकर)
रोहतक	5 (2 मैडीकल कालेज रोहतक को मिलाकर)
सिरसा	2
सोनीपत	2
(ख)	3
अम्बाला	1
भिवानी	1
गुड़गांवा	1

(ग) राज्य सरकार ने 85 पैसे प्रति किलोमीटर चार्चिज नियत किये हुए है। परन्तु सेन्ट जोहन एम्बूलैंस ऐसोसिये ान के केस में यह चाचिर्जज भिन्न जिलों में

अलग–अलग है हालांकि वे कभी 60 पैसे प्रति किलों मीअर से अधिक चर्जा नही करते। इसके इलावा गरीब मरीजों की मुक्त सेवाएं उपलब्ध है।

(घ) अभी नही।

M.B.B.S. Doctors

25. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) The district wise total number of M.B.B.S. Doctors working in the state; and

(b) The number of doctors out of those referred to in part (a) above who have not been confirmed for more than two years together with the reasons therof?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा):

(ए) सम्भवतः मागी गई सूचना उन्ही डाक्टरों के बारें में है जो कि एम.बी.बी.एस. और इससे उच्च स्तर की योग्यताएं रखते है और जो इस समय स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा में कार्य कर रहे है अतः उनके बारें में आंकड़े निम्न प्रकार हैः–

अम्बाला	100
भिवानी	72
गुड़गांवा	143

हिसार	88
जींद	40
करनाल	75
कुरूक्षेत्र	40
महेन्द्रगढ़	49
रोहतक	61
सोनीपत	42
सिरसा	36
कुल	746

नोटः– उपरोक्त आंकड़ों में उन अधिकारियों के बारें मै सूचना नही है जो कि इस समय बाहर डैपूटे ान पर गये हुए है या स्वास्यि निदे ाालय में काम कर रहे है।

(बी) उपरोक्त (ए) में वर्णित डाक्टरेां में से वह डाक्टर जो कि 2 वर्श की सेवा पूर्ण चुके है। किन्तु जिन्हे अभी तक पक्का नही किया गयाहै उनकी संख्या 479 है। उनकों अभी तक पक्का न करने के निम्नलिखित करण हैः–

1. इन 479 डाक्टरों में से 36 डाक्टर तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं तथा उन्हें स्थाई किए जाने बारे विचार नहीं किया जाना है।

2. भोश सभी 443 डाक्टरों को स्थाई नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल 192 रिक्त स्थाई पद उपलब्ध हैं। स्थाईकरण रिक्त स्थाई पदों पर होता है न कि दो वर्श की सेवा पूर्ण करने पर।

3. डाक्टरों की नियुक्ति के बाद परिवीक्षाधीन अवधि (जो पहले सेवा में हैं उनके लिए एक वर्श तथा जो सीधी भर्ती द्वारा आये हे, उनके लिए दो वर्श) सफलतापूर्वक पूर्ण करनी होती है। पूर्व इसके कि उन्हें स्थाई किए जाने के लिए विचार किया जाये साधाराणतः कुछ समय लग जाता है क्योंकि वार्शिक गोपनीय रिपोर्ट जो कि इस प्रयोजन के लिए आव यक होती है, को प्राप्त करना तथा उनका निरीक्षण करना होता है। जिन 192 डाक्टरों ने सफलतापूर्वक परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण कर ली है तथा वरिश्ठता एवं सेवा रिकार्ड के आधार पर योग्य हैं उन्हें स्थाई किये जाने बारे कार्यवाही हो रही है तथा इस कार्यवाही को भीघ्राति ीघ्र अंतिम रूप दिया जायेगा।

Eye Specialist Doctor in the Civil Hospital

26. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state:-

(a) whether there is any post of eye specialist doctor in the Civil Hospital Narnaul; and

(b) if so, since when the post as referred to in part (a) above is vacant together with the time by which the afore said post is likely to be filled up?

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्रीमति डाक्टर कमला वर्मा):

(ए) हां जी, सिविल हस्पताल, नारनौल में आंखों के वि ोशज्ञ का एक पद है।

(बी) यह पद 7–8–77 से खाली पड़ा है। इस पर पर लगाया गया डाक्टर दिनांक 7–8–77 से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित हैं। इस पद को भीघ्र भर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अब स्वामी अग्निवे ा कृपया अपना काल अटैन ान नोटिस पढ़ें।

स्वामी अग्निव ा (पुंडरी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय मैं अपनी सरकार की ओर से एक आ वासन चाहूंगा। हरियाणा गजटीयर के अन्दर पिछले दिनों एक बहुत बड़ा सैकेन्डल का पर्दा फा ा हुआ। दे ा के तमाम अखबारों में इस चीज को प्रकाि ात किया है कि भिवानी जिले के गजटीयर के अन्दर, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है, तत्कालीन रखा मंत्री है श्री बंसी लाल की प्र ांसा में, उनकी प्र ास्ती में, स्तुति में बहुत ज्यादा बढ़ा–चढ़ा कर कहा गया

है जो केवल इतिहास के रिकार्ड करने के तरीके पर ही लाछन नहीं है बल्कि इतिहास को पूरी तरह से विकृत करने का प्रयास किया गया है। केन्द्र सरकार की ओर से जब स्पश्ट आदे ा किदया गया है कि जब इस प्रकार का कोई ीाी गजटीयर तैयार हो तो उसमें जीवित व्यक्ति का नाम सांकेतिक रूप में ही आना चाहिए वि ोश प्रस्तुती के रूप में नहीं आना चाहिए। वहां पर बंसी लाल के नाम का जहां पर जिकर किया गया है, मुनिलाल की किताब से निकाल कर उनकी चापलुसी के लिए, वहां पर यह बात डाली गई है। मुझे बड़ी हैरानी होताी है कि ये बातें कैसे गजटीयर में घुस गई। वहां पर यह लिखा हुआ है कि बड़ी लम्बी तपस्या के बाद भागीरथ में जब यह भाक्ति उत्पन्न हुई तो वह गंगा को पहाड़ से उतार कर ले आये लेकिन बंसी लाल का दर्जा उस भागीरथ से भी कहीं ज्यादा ऊंचा है। उनके बारें में कहा गया कि गंगा के पानी को उतार कर उन्होंने टिब्बों मे पहुंचाया और लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत ले आये। यह अलग बात मुझे दिखायी पड़ती है कि भागीरथ तो गंगा को उतार कर अमर हो गये और बंसी लाल जी खुद जो गंगा का पानी लाये थे उसमें बह गये लेकिन हमारी सरकार इस बारे मे क्या करने जा रही है जो इतिहास की विकृति उस गजटीयर में डाली गई है ?

करनाल के गजटीयर के अन्दर भी इसी प्रकार विक्ति डाली गई है। वहां पर बनारसी दास गुप्ता के नाम को बढ़ा–चढ़ा कर लिखा गया है। इस पर जब केन्द्रीय सरकार ने आपति की तो

बिक्री रोक दी गई लेकिन उसके बावजूद फिर बिक्र को चालू कर दिया गया। ये चीजें जो पिछली सराकर के तहत चल रही थी, क्या हमारी सराकर इस सारे गजटीयर को चेंज करने के लिए सक्रिय कदम उठाने जा रही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। कल भी यही सवाल उठा था और जीरो आवर मे ंस्वामी जी को वक्तव्य देने से मना किया था। मैंने चेयर से दरखास्त की थी कि यह तरीका असैम्बली के लिए ठीक नहीं है, आप अपनु हुक्म के बारे दुबारा विचार कीजिए। मैंने कहा था कि ऐसी बातों का जिकर किया जाना चाहिए। कल आपने जीरो ओवर के बारे में फैसला दे दिया था कि बिना नोटिस दिये, बिना रूल के कोई बात नहीं की जा सकती है। तो क्या आज आपने जीरो आवर को रिकोगनाइज करके, इन्ट्रोड्यूस करके दुबारा इजाजत दे दी है ताकि हम आइंदा के लिए सबक लें।

श्री अध्यक्ष: राव साहब, असल बात तो यह है कि स्वामी जी ने मेरे से लिख कर इजाजत मांगी है।

Rao Birender Singh: Under what Rule?

श्री अध्यक्ष: रूल भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें दो चीजें हैं। जीरो आवर मे कोई भी चीज स्पीकर की परमि ान से उठायी जा सकती है। जहां तक स्वामी अग्निवे ा जी का ताल्लुक है इन्होंने मेरे से परमि ान ले ली थी। दसूरे अगर कोई मैम्बर

प्वायंट उठाना चाहता है तो उसके बारे में उसको रूल बताना पड़ेगा कि किस रूल के तहत वह मामला रेज करना चाहता है।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, स्वामी जी भी कल जीरो आवर में इस मामले को उठाना चाहते थे परन्तु आपने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी थी।

श्री अध्यक्षः कल उन्होंने पहले परमि ान नहीं मांगी थी।

राव बीरेन्द्र सिंहः जीरो आवर में परमि ान .....

श्री अध्यक्षः पहले मैम्बर को बताना पड़ेगा कि मैं इस चीज पर बोलना चाहता हूं कल उन्होंने इस बात को कलियर नहीं किया था।

राव बीरेन्द्र सिंहः अब आपका यह आदे ा हो गया है कि हम जीरो आवर में कुछ मैन ान कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः स्पीकर की परमि ान से मामला रेज किया जा सकता है।

राव बीरेन्द्र सिंहः क्या परमि ान उसी वक्त नहीं दी जा सकती है ?

श्री अध्यक्षः अगर बहुत अरजैंट मामला है तो परमि ान उसी वक्त भी दी जा सकती है। स्वामी जी ने कुछ कहा है क्या सराकर इस बारे में कुछ कहना चाहती है ?

उद्योग मंत्री द्वारा ध्यानाकर्शण सूचना सं0 2 पर वक्तव्य

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन)ः स्पीकर साहब, आदरणीय स्वामी जी ने प्र न उठाया है कि उस समय के भाासक के बारे में भिवानी के गजटीयर में बड़ा तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है और करनाल जिले के गजटीयर में भी बड़ी गलत बयानी की गई है। मैं हाउस को इस बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इतिहास के विपरीत जो बात है, आंकड़ों के विपरीत जो बात है उसको ठीक करा देंगे।

मुख्य मंत्री द्वारा ध्यानाकर्शण सूचना नं. 1 पर वक्तब्य

श्री अध्यक्षः कल मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था कि वे आज काल–अटैन ान नोटिस नं. 1 का जवाब देंगे।

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल)ः स्पीकर साहब, जुलाई व अगस्त की लगातार बारि ा होने से जो ड्रेनेज का सिस्टम था वह नाकाफी साबित हुआ।

2. साहिबी नदी में एक लाख क्युसिक से ऊपर पानी गुजरा जो कि एक सौ वर्श का रिकार्ड है। इससे पहले 91000 क्युसिक पानी ज्यादा से ज्यादा गुजरा था।

3. साहिबी नदी का पानी देहली हो कर दरियाये जमना में निकलता है। वहां ढांसा बान्ध की वजह से काफी रूकावट रही है क्योंकि आगे नजफगढ़ ड्रेन में कैपेसिटी सिर्फ 3000 क्युसिक है जो कि नाकाफी है।

मेवात के इलाके का पानी उजीना ड्रेन की मार्फत राजस्थान में पहाड़ी कामा ड्रेन से गुजर कर यू.पी. में गोवर्द्धन ड्रेन से दरियाये जमना में निकलता है। राजस्थान बार्डर पर खोलका रेगूलेटर पर भी पानी काफी दिन तक पूरी तरह से नहीं निकल सका क्योंकि राजस्थान वाले ज्यादा नहीं निकालते थे। इसलिए अब मेवात के लिए 22 करोड़ रूपये की लागत से उजीना डाइव र्न ड्रेन की तामीर और उजीना ड्रेन की री–मोडलिंग का काम किया जाना है।

सन् 1977 के फ्लड से जानी व माली नुक्सानः–

मुआवजात जिन्हें नुक्सान हुआ	1794
आबादी जिन्हें नुक्सान हुआ	30 लाख
रकबा जिन्हें नुक्सान हुआ	30 लाख एकड़

फसल जिसे नुक्सान हुआ	17 लाख एकड़
मकानात कच्चे व पक्के	142000
फसल के नुक्सान का अन्दाजा	56 करोड़ रूपया
मकानात के नुक्सान का अन्दाजा	15 करोड़ रूपया
सड़कों के नुक्सान का अन्दाजा	7 करोड़ रूपया
सरकारी इमारतें व स्कूलों के नुक्सान का अन्दाजा	एक करोड़ रूपया
नहरों व ड्रेनों के नुक्सान का अन्दाजा	साढ़े सात करोड़
कुल नुक्सान	**साढ़े छियासी करोड़**

इसके अलावा ट्रांस्पोर्ट महकमें को भी एक करोड़ का नुक्सान हुआ है क्योंकि बसें बन्द रहीं। तिजारत को भी काफी नुक्सान हुआ, खरीफ की फसल खराब होने से मार्किट फीस सेल्ज टैक्स वगैरा में भी नुक्सान होगा।

फ्ल्ड रिलीफ के इन्तजामातः

फौरी इमदादः मुफ्त रा ान 400 ग्राम गेहूं व 100 ग्राम दाल फीकस के हिसाब से रोजाना दी जाती थी। जिनके घर गिर

गये थे और उनके पास रा ान नहीं बचा था, मेवात के इलाके में अभी भी कई गांवों में यह स्कीम जारी है।

हैलीकाप्टर से पक्का खाना और चने व गुडत्र उन गांवों में दिया गया जहां पहुंचना नामुमकिन था। फौज से मोटर बोट्स और जवान लिये गये ताकि गांवों को दवा और खुराक पहुंचायी जा सके। फ्लड रिलीफ के लिए कि तयां भी लगायी गयीं। सिरकियां बांटी गयी ताकि लोगों को भौल्टर मिल सकें। हर गांव में एक एच.ए.पी. का जवान तैनात किया गया मलेरिया और हैजा के बचाव और दूसरी दवाओं और पीने के पानी के क्लोरीने ान के लिए 60 लाख रूपया खर्च किया गया। जगह–जगह डाक्टर व पैरा–मैडीकल अमला तैनात किया गया। हर फ्लडजदा गांव में दूसरे या तीसरे दिन डाक्टर खुद जाकर मरीजों को देखते रहे।

मवे ियों के लिए, गलघोट, भीतला, पेट के कीड़े, भारह वगैरा बीमारियों से बचाने के लिए 50 लाख रूपया खर्च किया गया। हैंड पम्प और लैटरीनज के लिए साढ़े छः लाख रूपया खर्च यिका गया। सबसे जरूरी मसला इस वक्त रबी की फसल के लिए जमीन बरामद करना है और उसकी जुताई करवाना है। जहां टूटी ड्रेन और कट देकर पानी की निकासी की गयी वहां लो लाइंग इलाकों मे ंपम्प से पानी निकाला गया । पम्पिग पर करीब 2 करोड़ रूपया खर्च आयेगा। इस पम्पिग की मदद से करीब 5 लाख एकड़ रकबा रबी के लिए काबिले का त हो जायेगा जिससे कम से कम 25 करोड़ रूपये की फसल होगी। 2 हजार क्यूसिक

के पम्प काम कर रहे हैं। कुल 13 लाख रूपवये के पम्प हाल ही में खीदे गय या खरीदे जा रहे हैं। कुल 24 लाख एकड़ जमीन है जिसमें पानी जमा हुआ था उसमें से सिर्फ अढाई या तीन लाख एकड़ में अब पानी रह गया है दिसम्बर तक करीब एक लाख एकड़ रकबा रह जायेगा जहां पर का त नहीं हो सकेगी। लेकिन आज की जो इत्तलाह मिली है, उसके मुताबिक यह रकबा सिर्फ 75 हजार एकड़ ही रह जायेगा। जहां पर का त नहीं हो सकेगी। जुताई के लिए 2500 ट्रैक्टर हासिल किये जा रहे हैं। 50 ट्रैक्टर पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरे ान भी भेज रही है। डीजल के लिए तकावी दी जायेगी। लेट वैराइटी गेहूं और चने के बीज के लिए 55 लाख रूपये की तकावी दी गयी है। फर्टेलाइजर के लिए एक करोड़ की तकाबी दी गयी है। सी.एम. रिलीफ फन्ड में अब तक 80 लाख रूपया आ चुका है। इसमें साढ़े छः लाख रूपया पिछले साल से बकायसा आ रहा था वह भी भाामिल है यानी साढ़े 73 लाख रूपया 6 अगस्त से अब तक इसमें चन्दा आया है। इसके अलावा 20 हजार क्विंटल चारा यानी 5 लाख रूपये की मालीयत का और दस हजार क्विंटल गेहूं साढ़े 10 लाख रूपये की मालीयत का भी लोगों ने दिया है। इस तरह कै ा और काइन्ड में 6 अगस्त के बाद 89 लाख रूपया इस फन्ड में आया है। इसमें से 31 लाख रूपया नकद और चारा और गेहूं बाढ़जदा इलाकों में खर्च किया गया है और बाकी रूपया भी अभी बाढ़ के कामों में ही खर्च किया जायेगा। 1976–77 में कुल साल में सिर्फ सवा चौदह लाख रूपया इस फन्ड में आया था।

मुतफ रका इमदादः जिन इलाकों में 50 प्रति ात से ज्यादा नुक्सान है, वहां पर लैंड होल्डिंग टैक्स, आबियाना व तकाबी की वसूली सस्पैंड की गयी है। लैंड होल्डिंग टैक्स और आवियाने की माफी भी की जावेगी। मकानों की मुरम्मत के लिए ग्रान्ट और लोन देने पर भी गौर किया जा रहा है। भारत सरकार से इमदाद का अन्दाजा मालूम होने पर इस बारे में फैसला किया जायेगा। बैंकों से भी लोन के बारदे में बातचीत चल रही ळै। सबसे जरूरी काम बाढ़जदा इलाकों में ऐसे काम भ्रारू करने का है जिनसे लोगों को मजदूरी मिल सके और वह काम ऐसे हों जिनसे मुस्तिकल तौर पर इलाके को फायदा हो। ऐसे कामों में ड्रेन, बन्ध, सड़कों की मुरम्मत और उनको ऊंचा करना और कल्वर्ट बनाना, आबादी की हिफाजत के लिए रिंग बन्ध बनाना और पानी इक्ट्ठा करने के लिए गहरे तालाब, आबादी से सड़क तक ऊंचा पक्का रास्ता बनाना, इस तरह की स्कीमें बनायी गयी हैं। इन स्कीमों को पूरा करने के लिए हमने भारत सरकार से 11 करोड़ की ग्रांट और 38 करोड़ रूपये का लोन मांगा है। कुल हमने भारत सरकार से 18 करोड़ की ग्रांट और 56 करोड़ का कर्ज मांगा है। 12 अक्तूबर से 14 अक्तूबर तक भारत सरकार की एक टीम आई थी जो हमारे फ्लड वाले इलाकों में दौरा करके गयी है। अब भारत सरकार से इमदाद के लिए पे ाक ा की जा रही है। मेवात के इलाके में उजीना डाइव र्न ड्रेन की रिमौडलिंग पर 22 करोड़ रूपया का खर्चा आयेगा। इसके लिए यू.पी. राजस्थान और सैंट्रल वाटर कमी ान से बातचीत हो चुकी है और काम जल्दी ही भ्रारू किया

जायेगा। इस काम को दो साल मे पूरा करने की कोि ा ा की जायेगी ताकि मेवात के इलाके को बाढ़ से निजात मिल सके। इस साल हमारी सरकार तकावी, पानी की निकासी, दवाईयां, रा ान बगैरा के लिए करीब 6 करोड़ रूपया खर्च कर चुकी है। अभी मकानों की मुरम्मत के लिए कम से कम 8–10 करोड़ रूपये के लोन और ग्रान्ट भी देने पड़ेंगे। 1976–77 में हांलाकि नुक्सान इस साल से कुछ ही कम था लेकिन सरकार ने सिर्फ दो करोड़ रूपया खर्च किया। हमारी सरकार ड्रेनेज और फ्लड प्रोटैक ान को रिलीफ देकर सबसे पहले इन कामों को पूरा करेगी जिससे बाढ़ से पब्लिक को राहत मिले। सभी पोलिटिकल पार्टीज ने फ्लड रिलीफ के काम में सरकार को ताउन दिया। सरकार ने फ्लड एडवाइजरी कमेटी, जिसके चेयरमैन श्री हरद्वारी लाल जी हैं, 27 जुलाई को अप्वांयट की थी, जिसमें सर्व श्री सरदार खां, भाम ेर सिंह, लाल सिंह, गंगा राम, एम.एल.ए. भी मैम्बर हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट जब भी आयेगी, सरकार उसमें की गई सिफारि ाों पर पूरा गौर करेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है इसलिए इस कमेटी की मियाद बढ़ा दी गयी है। स्पीकर साहब, मैं एक खु ाखबरी और सुनाऊं कि कल भट्टा ऐसोसिए ान ने वायदा किया है कि 50 ट्रैक्टर वह रोहतक भेज देंगे (व्यवधान)। मैं राव साहब का म ाकूर हूं कि इन्होंने इस सिलसिले में वि ााल हरियाणा पार्टी की मीटिंग करके मुखालिफत नहीं की और मैं चौधरी हरद्वारी लाल का भी म ाकूर हूं कि उन्होंने इस काम में बहुत मदद की।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 5) बिल, 1977

Finance Minister (Ch. Satvir Singh Malik): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1977.

I also beg to move:-

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

Ch. Hardwari Lal: On a Point of Order. Mr. Deputy Speaker. I age notice of question of privilege and it was given in due time.

श्री उपाध्यक्षः वह बाद मे होगा।

Ch. Hardwari Lal: No, no. It cannnot be. It has always to be at a point of time.

श्री उपाध्यक्षः वह कल कंसीडर होंगा।

Ch. Hardwari Lal: What am I to understand? कल किस तरीके से कंसीडर होगा ?

श्री उपाध्यक्षः वह कल टेक अप होगा।

Ch. Hardwari Lal: Is the Chair wanting some time to consider it?

श्री उपाध्यक्षः अभी एग्जामिन हो रहा है, कल टेक अप होगा।

Ch. Hardwari Lal: Alright.

Ch. Satvir Singh Malik: Sir, this Bill has been brought forward in pursuance of articles 204(1) and 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation of the Consolidated Fund of the State of Haryana of th sums required to meet the supplementary grants made by the Legislative Assembly for expenditure for the financial year 1977-78.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

स्वामी आदित्यवे ा (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने हरियाणा विनियोग विधेयक आया है। मैं आपका ध्यान डिमानउ नम्बर 2 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें 18675.00 और 560.00 रूपए मांगे गए हैं इसको पढ़ने से पता लगता है कि सरकार को मुकदमेबाजी में हारने की वजह से यह रूपया देना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि मुकदमें में सरकार के हारने की वजह से प्रतिश्ठा कम होती है। मेरा विचार है कि सरकार को जा यह रूपया देना पड़ रहा है वह पिछली सरकार की गल्तियों के कारण देना पड़ रहा है। मेरा विचार है कि सरकार को जो यह रूपया देना पड़ रहा है वह पिछली सरकार की गल्तियों के कारण देना पड़ रहा है इसलिए पिछली सरकार के लोगों से इसे वसूल करना

चाहिए। दूसरी बात यह है कि आगे के लिए सरकार इस बात का ध्यान रखे कि कोई ऐसा काम न किया जाए, इस तरह का कोई कदम न उठाया जाए जिससे सरकार के मुकदमा हारने के बाद प्रतिश्ठा गिरे।

इसी प्रकार डिमान्ड नम्बर 7 में 510.00 रूपया मांगा यगा है। इसमें ीाी सरकार मुकदमें में हारी है और इस वजह से सरकार को 510.00 रूपया पुजारी को देना पड़ रहा है। मांग नम्बर आठ में 525875.00 रूपया मांगा गया है। यह भी मुआवजे के रूप में सरकार को देना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर यह नाजायत बोझा पड़ रहा है। अगर यह मुकदमेबाजी का कदम न उठाया जाता तो पांच छह लाख का बोझा सरकार पर न पड़ता। अब डिमान्ड नम्बर 18 को देखें तो उसमें 11100.00 रूपया सरकार को सांड के सम्बन्ध में मुआवजा देना पड़ रहा है। इस मुकदमें बाजी से जहां एक ओर सरकार की प्रतिश्ठा गिरती है वहां दूसरी ओर टाइम खराब होता है और कई बार ठीक से न्याय भी नहीं मिल पाता। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह मुकदमें का तरीका न अपनाकर आपस में समझौते अथवा आपस में बातचीत से मामले को हल करने का यत्न करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद 17265820.00 रूपया मांगा गया है। मेरी समझ मे यह नहीं आता कि पछिली सरकार जो कांग्रेसी सरकार थी उसने किस रूप में यह कर्जा लिया था, कहां लिया था। बिना छानबीन के जो यह सरकार रूपया देने जा रही

है इसका पूरी तरह स्पश्टीकरण होना चाहिए तभी यह सारी मांगे पास होनी चाहिए।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो ऐप्रोप्रिए ान बिल मंत्री जी ने हाउस के सामने पे ा किया हैं, इस सम्बन्ध में कल हाउस में भिन्न भिन्न मांगों पर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं मुनासिब समझता हूं कि इस बिल के माध्यम से अपनी कुछ बातें आपके द्वारा वित मंत्री के सामने रखूं। पहली बात जो मैं इस सम्बनध में कहना चाहता हूं वह यह है कि यह सप्लीमैंटरी ग्रान्ट से हमारी नई सरकार की पालिसी का एक अक्स होना चाहिए था। इस नई सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार हैं और चार महीनों से बनी है, को बताना चाहिए कि उसकी नीति क्या है। इस पार्टी ने मई तथा जून में जो वायदे जनता से किए थे, इस सप्लीमैन्टरी डिमान्ड्ज के द्वारा यह जनता को बताना चाहिए कि किस तरीके से यह पार्टी उन वायदों को पूरा करना चाहती है। डिप्टी स्पीकर साहब, ऐप्रोप्रिए ान बिल के द्वारा, इन मांगों के द्वारा उन वायदों के पूरा एि जाने को कोई नमूना, कोई संकेत आना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि इन मांगों के द्वारा और इस बिल के द्वारा बिल्कुल भी, जरा सा भी संकेत नहीं है। मेरे से पूर्व बोलने वाले साथी ने जो कुछ कहा है, जो उनके भाव है वे दुरूस्त नहीं हैं। इसमें सरकार के मुकदमें हारने का सवाल नहीं है। वे मुकदमें इस तरह हो जाते हैं कि जैसे एक मामूली किसान है, उसकी

जमीन एक्वायर कर ली जाती है। ऐक्वायर करने में जो ऐक्वीजी ान आफिसर होता है वह मुआवजे की रकम कम लगाता है और मालिक मुआवजे की रकम ज्यादा मांगता है क्योंकि कानून के अन्दर मार्किट रेट पर जमीन ऐक्वायर की जाती है और इस तरह मालिक कोर्ट में चला जाता है। इस प्रकार उन अपीलों में कहीं एक लाख रुपया सरकार को देना पड़ता है और कहीं बीस हजार रुपया देना पड़ता है। यह सरकार का कसूर नहीं होता यह तो चलता ही रहता है और जब कभी सप्लीमेन्टरी डिमान्डज आती हैं तो वह रुपया इन डिमान्ड्ज के द्वारा मांग लिया जाता है। लेकिन जिस चीज की तरफ मैं इ ाारा करने जा रहा हूं मिसाल के तौर पर अभी फ्लड रिलीफ का जिक्र आया। बड़ी खु ाी की बात है और मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं कि सरकार ने फ्लड रिलीफ के मामले में बहुत अच्छा काम किया है और इस सम्बन्ध में जब डिबेट होगी तो उस पर मैं अपने विचार रखूंगा लेकिन इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा अभी कहा गया कि पम्पिंग पर दो करोड़ रुपया खर्च किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पहले कांग्रेस सरकार थी उसने दो करोड़ रुपया बजट में प्रोवाइड नहीं किया था तो इस सरकार ने कहां से दो करोड़ रुपया खर्च कर दिया और अगर सरकार ने रुपया खर्च कर दिया तो हाउस के सामने दो करोड़ रुपया की डिमान्ड इस सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्ज में आनी चाहिए थी। आप कह सकते हैं कि यह डिमान्ड इस सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्ज में आनी चाहिए थी। आप कह सकते हैं कि यह डिमान्ड अगली बार आ जाएगी लेकिन डिप्टी स्पीकर

साहब, अगर यह दो करोड़ की डिमान्ड इस सप्लीमेन्री डिमान्ड्ज में आ जाती तो हाउस में सदस्यों को फ्लड रिलीफ पर बहस करने का मौका मिल जाता। सदस्यों की तरफ से कुछ अच्छे सुझाव आते जिससे सरकार को भी फायदा होता और फ्लड एरिया के लोगों को बहुत लाभ होता। इससे 11.00 बजे अगली बात जिस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या है। मेरे साथी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारे हरियाणा में पढ़े लिखे लोगों के लिये बरोजगारी की समस्या बड़ी भयानक समस्या है। हमारी सरकार ने पिछले चार महीनों से इस पर क्या विचार किया है, इस के परिणामस्वरूप क्या प्रोग्राम सरकार ने बनाये हैं, सरकार इस पर कितना खर्च करना चाहता है, इस बारे ऐसा कोई संकेत नहीं कि इस पर इतना रुपया खर्च किया जाएगा, इन मांगों में आना चाहिये था। हमारे उद्योग मन्त्री महोदय ने बताया कि हम दस्तकारी के लिये क्या कर रहे हैं, हम देहातों के अन्दर 110 सेन्टर कायम कर रहे हैं जिनमें पढ़े लिखे लोगों को लगाया जाएगा। तो डिप्टी स्पीकर साहब आप इससे सहमत होंगे कि यह जो 110 सेन्टर खोले जाएंगे उन पर अव य ही पैसा खर्च होगा। और डिप्टी स्पीकर रुपये का रिफलेक ान इन मांगों के अन्दर तो आना चाहिए था। मैं ज्यादा सख्त लफज़ तो इस्तेमाल करना नहीं चाहता केवल इतना ही कहूंगा कि ऐसा करना इस हाउस की बदनामी है। योजना बना लें किसी काम के लिये, उसका एलान भी कर दें, सारा प्रोग्राम फील्ड में भी चला जाए, लेकिन हाउस को कांफिडैंस

में न लिया जाए, यह ठीक बात नहीं है। मेरे ख्याल मयें ज़िला अधिकारियोंय को बुलाकर योजना बन चुकी है। उन योजनाओं को अमल में लाने के लिए अफसरों को भी लिखा जा चुका है। मेरा यह सुझाव है कि उस योजना पर खर्च किये जाने वाले रुपये का रिफलैक ान यहां पर अव य दिया जाना चाहिये था। इस पर सरकार को गौर करना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, इससे आगे मैं एप्रोप्रिए ान बिल के ऊपर केवल एक दो बातों का ही जिक्र करूंगा। हमारी सरकार को अगर ऊपर से कोई इ ाारा या कोई चिट्ठी आती है तो वह बिना उस पर विचार किये, बगैर सोचे समझे उस चिट्ठी पर अमल करने की कोि ा ा करती है। अगर किसी केन्द्र के कर्मचारी ने या केन्द्र सरकार ने यह लिख दिया कि आई० टी० आईज़० में जो एक ट्रेनी को दस रुपये का रा–मैटिरियल दिया जाता है उसको बढ़ाकर पच्चीस रुपये कर दिया जाए तो हरियाणा सरकार इसके लिये पाबन्द नहीं है, कोई यह पत्थर की लकीर नहीं हो जाता कि हरियाणा सरकार उस लिखे हुए पर अमल करें। एक बात का मुझे ज्ञान है। मैं पानीपत आई० टी० आई० में गया, वहां पर सारा स्टाफ था, प्रिसींपल था और दूसरे लोग भी थे, किसी ने मुझे ट्रेनीज के रा–मैटिरियल की मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उनसे कहा कि आप की कोई डिफिकलटी हो तो आप मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, भाायद आपके किसी काम में सुधार हो जाए।

तो उन्होंने मेरे सामने एक ही बात रखी कि हमारे यहां पानीपत में दो बड़े कारखाने लगाये गये हैं एक थर्मल प्लांट और दूसरा फर्टीलाईज़र का, उन में वैलडर्ज़ और इलेक्ट्री ानज़ की बहुत ही ज़रूरत है आप अगर करा सकें तो ऐसा करा दें कि इन सीटों के लिये हमारा जो दाखिला होता है वह पहले से डबल करा दें, न हम अलहिदा बिल्डिंग मांगते हैं, न ही अलहिदा म ाीनरी मांगते हैं, इमें इसके लिये केवल कुछ स्टाफ चाहिये। फिर मैंने कहा कि इस पर कितना रुपया खर्च होगा तो उन्होंने कहा कि केवल पचास हज़ार रुपये सालाना से यहां आई0 टी0 आई0 में डबल दाखिले का प्रबन्ध हो सकता है। मैंने उसी वक्त वहां पर बैठे ही उद्योग मन्त्री को चिट्ठी लिखी कि यह मामला है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं क्या त्रां पचास हज़ार रुपया तो क्या देना था, एडमि ान का मामला वहीं का वहीं रहा। इसके विपरीत डिप्टी स्पीकर साहब, आप सरकार से पूछें कि हरियाणा के किसी भी आई0 टी0 आई0 के प्रिसींपल ने, किसी कर्मचारी ने सरकार को यह नहीं लिखा होगा कि दस रुपये का जो रा–मैटिरियल आप दे रहे हैं उसको बढ़ाकर उसकी दर पच्चीस रुपये कर दी जाए फिर भी इन्होंने दस रूपये की बजाए पच्चीस रूपये कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि 16–17 लाख रुपये का एडी ानल खर्चा आ पड़ा जिसका हमारे खजाने पर भार पड़ा जो कि बिलकुल वेस्ट जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने इस पर रो ानी भी डाली थी। कई माननीय सदस्य तो इस रा ि ा को वजीफे की रा ि ा ही समझ बैठे थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह वजीफा नहीं हैं यह

तो काम करने कये लिए रा–मैटिरियल खरीदने के लिए एक विद्यार्थी को दी जाने वाली रा ि ा है। जैसे एक लड़का पहले दस रूपये की लकड़ी काम के लिए इस्तेमाल करता था अब वह पच्चीस रूपये खर्च कर सकेगा। जैसे एक कलास में बीस लड़के हों तो दस रूपये के हिसाब से उन पर पहले दो सौ रूपये महीने का खर्चा था अब पच्चीस रूपये के हिसाब से उन पर पांच सौ रुपये का खर्चा हो रहा है। इस तरह से यह कितनी वेस्टेज है जो कि हमारे खजाने के ऊपर एक भार है, यह नहीं पता कि इस रूपये को यह सरकार रिकवर कैसे करेगी, इसकी रिकवरी के बारे में सरकार का जवाब है, मैं उससे बिल्कुल सन्तुश्ट नहीं हूं। या तो यह सकरार बताए कि यह विभाग की तरफ से मांग है, प्रिसींपल की तरफ से मांग है जो कि यह ऐसा किया गया है तब तो मैं मानूं कि जो सरकार ने किया है ठीक है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अगली बात मैं खाद के बारें में कहना चाहता हूं सरकार चाहती है कि यह हाउस उन्हें खाद के लिये 1 करोड़ 27 लाख रुपयें की रा ि ा मन्जूर कर के दे दे। इन खादों को खरीदने के लिये सरकार की तरफ से कुछ रियायत मिलनी चाहिये जैसे अगर एक किसान दो सौ रुपये की खाद खरीदता है तो उसको बीस रुपये की रियायत मिलनी चाहिये और अगर दूसरी किस्म की खाद खरीदता है तो उसे दस रुपये की रियायत मिलनी चाहिये। अगर ऐसी रियायत किसान को मिले तो सरकार का सराहनीय कदम होगा लेकिन इतना ज्यादा रुपया की

मन्जूरी यह सरकार लेना चाहती है तो उसे यह बताना चाहिये कि पिछले साल इस डिमांड पर कितना खर्च हुआ। आखिर इस हाउस से एक करोड़ 27 लाख रुपये की रा ि ा यह सरकार मन्जूर करवाना चाहती है केवल इस आधार पर कि पिछले साल भी यह रूल चलाये गये थे, उनसे इतना लाभ हुआ, इसलिये इस साल भी हम यह करने जा रहे हैं जिसके लिये हमने यह रा ि ा की मांग की है। क्या यह सरकार नहीं जानती इस बात को कि रुपया किस प्रकार मांगा जाता है ? यहां पर एक और बिल हमारे सामने आ रहा है जिसके जरिये लैंड रैवेन्यू की तरमीम यह सरकार इस हाउस से करवाना चाहेगी। वह ऐसा है कि कुछ कम्पनियों को भोयर दिये गये थे और उनसे जो पैसा लेना था मिला नहीं इसलिये उस बिल के जरिये उस पैसे को ये लैंड रैवेन्यू के तौर पर वसूल करना चाहते हैं। सरकार यह नहीं देखती है कि कोआप्रेटिव सोसाइटियों के कर्मचारी, इंडस्ट्री डिपार्टमैंट के कर्मचारी तथा दूसरे कर्मचारी किस तरीके से लोंगों के रुपये से खिलवाड़ करते हैं। पब्लिक में इस तरह के बहुत से निकम्मे लोग हैं इनमें कुछ पालिटी ीयन्ज भी हो सकते हैं जिनमें एक मैं भी हो सकता हूं तो ये जितने निकम्मे आदमी हैं ये सरकारी कर्मचारियों के साथ मिल कर अम्बैजलमैंट करते हैं। सरकार इस 1 करोड़ 27 लाख रुपये को घपले में डालना चाहती है। जब तक यह सरकार वि वास न दिलाए कि यह उसका तरीका है और हमने पिछली सरकार के मुकाबिले में ये–ये सुधार किये हैं तब तक कोई फायदा नहीं है। पिछली सरकार ने तो धांधली मचाने में

रिकार्ड ही बीट कर दिया था लेकिन इस सरकार के बारे में तो भविश्य में पता लगेगा कि यह भी रिकार्ड बीट करती है या सुधार करती है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार जिसके लिये मैं भी कुछ कुर्बानी करने का क्लेम करता हूं उसने इन चार महीनों में क्या कदम उठाए हैं। क्या सरकार के नोटिस में यह बात नहीं है कि सो ाल वैल्फेयर का महकमा लोंगों को कर्जा और ग्रांट देता है ? अगर किसी हरिजन को वहां से एक हजार रुपया ग्रांट मिलती है तो उसके पल्ले मु कल से पांच सौ रुपए पड़ते हैं। इसी तरीके से कोआप्रेटिव सोसाइटियों के कर्जे हैं जमींदारों को ट्रैक्टर के लिये और पम्पिग सैट्स के लियें कै ा नहीं दिया जाता बल्कि कोई दुकान या डीलर मुकर्रर कर दिया जाता है कि फलां डीलर से खरीदो। तो अगर कोई म ाीन दो हजार की है तो डीलर उसे तीन हजार की देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह एक हजार रुपया कहां जाता है ? वह एक हजार रुपया आपके महकमे के कर्मचारी और डीलर मिल कर खाते हैं। भाायद कोई पोलिटि ियन भी खाता हो मैं नहीं जानताहि। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 1 करोड़ 27 लाख रुपया आप हमसे लेकर तकसीम करने जा रहे हैं उसकी क्या गारन्टी है कि वह ठीक तरीके से तकसीम होगा इसलिये इसके बारे में भी इसमें ज़िक्र आना चाहिये था। मैं इस पर और अधिक नहीं कहना चाहता। जब मिनिस्टर साहब अपने जवाब में इन चीजों का वि वास दिलाएंगे तो मैं इसका समर्थन जरूर करूंगा।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहब, सदन में तीन करोड़ 27 लाख रुपये का एप्रोप्रिए ान बिल प्रस्तुत हुआ है। सरकार सदन से इसके द्वारा खर्चे की स्वीकृति मांग रही है और सदन भली प्रकार से जानता है कि यह सरकार किन हालात के अन्दर बनी। इस सरकार को काम करते हुए अभी केवल तीन मास हुए हैं। कल डिमांडों पर भी काफी चर्चा हुई और आज भी सदन में इस विशय पर यह बात आई कि इस सरकार ने पिछले 3–4 महीनों में क्या किया। जब हम सरकार को करोड़ों रुपये के खर्च करने के लिये स्वीकृति देने के लिये सोच रहे हैं तो हमें सरकार किन कारणों से बरसरे इकतदार में आई और पता नहीं किन कारणों से भगवान का प्रकोप हरियाणा के ऊपर हुआ लेकिन मैं कहूंगा कि हरियाणा के ऊपर भगवान की ओर से तो जो प्रकोप हुआ सो हुआ लेकिन जो सब से बड़ा अन्याय और जुल्म हरियाणा के ऊपर हुआ वह पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा हुआ। उसने दुनिया भर के अन्दर यह ढिंढोरा पीटा था और इस हरियाणा के अन्दर भाासन करने वाले बंसीलाल यह कहा करता था कि हिन्दुस्तान की नहीं भाायद दुनिया के अन्दर इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी हरियाणा में हुई है। मैं इसके अन्दर ज्यादा न जाते हुए केवल एक ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस हरियाणा में पिछली सरकार द्वारा इतना भारी पैसा खर्च करने के बावजूद सैलाब आने से कितनी योजनाएं सफल

हुई हैं। मैं अगर वे फिगर्ज़ देने लगूं तो 1968 से लेकर 1977 तक अरबों रुपये का खर्चा हुआ है। जिस हरियाणा में बंसी लाल सरकार ने बड़े–बड़े बांध बांधने की बात कही थी उसी हरियाणा का आज 1/3 हिस्सा सैलाब के अन्दर डूबा हुआ है और 2/3 हिस्सा पानी के लिये सिसक रहा है। जो अरबों रुपये खर्च हुए वह हरियाणा के अन्दर खर्च नहीं हुए बल्कि वह उन लोगों की जेबों में गये हैं जो इन बातों का दावा करते थे। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले 3–4 महीनों में जनता सरकार ने कितने उल्लेखनीय काम किये हैं इसलिये वह इस बात की हकदार है कि उसने हरियाणा की प्रगति के लिये यह जो मांग रखी है उसकी स्वीकृति दी जाए। हमारी जो फ्लड रिलीफ कमेटी है, मैं एक बार उसकी मीटिंग में गया। जब डिस्क ान हो गई तो मैंने वहां अफसरौं से एक बात पूछी कि सैलाब को रोकने के लिए आप बांध बनाते हैं वह टैम्पोरेरी क्यों बनाते हो परमानेंट क्यों नहीं बनाते ? मुझे एक बांध के बारे में बताया गया कि उसके टैम्यपोरेरी बनाने पर 2 लाख 30 हजार रुपये खर्च आए हैं। मैंने पूछा कि अगर उसी को परमानैंट बांध बनाया जाता तो कितना खर्चा आता ? उन्होंने बताया कि 60–70 हजार रुपये और आ जाता। तो मैंने उनसे कहा कि पक्का क्यों नहीं बनाया गया ? तब उन्होंने कोई जवाब

नहीं दिया। इसका कारण यह है कि टैम्पोरेरी बांध बनाने से बार–बार पैसा उनकी जेब में आता है और परमानेंट बनाने से केवल एक बार ही पैसे मिलेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पिछली

सरकार की बातों में और ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये लिमिटिड डिमांडज़ आई हैं। बजट के समय खुल कर बातें करूंगा तब सारे फैक्टस हाउस के सामने आएंगे। लेकिन ऐसी हालत के अन्दर जब हरियाणा सरकार इस सैलाब के नुकसान में फंसी हुई है जिसकी वजह से लाखों लोग भिखारी हो गए हैं और कई गांवों में तो अब तक भी पानी खड़ा है उनकी हर तरह से मदद कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने थोड़े से समय में इतनी मु कलात के बावजूद इस सरकार ने कितने अच्छे काम किये हैं। मैं उनका उल्लेख करना यहां आव यक समझता हूं ताकि सदन इस एप्रोंप्रिए ान बिल पर अपने विचार ठीक प्रकार से रख सके। इसमें कोई भाक नहीं कि आज इस बात की बहुत चर्चा है। कुछ भाईयों ने कहा कि सरकार ने आते ही नए टैक्स लगाने भुरू कर रिए। इसके बारे में सदन मैं कहना चाहूंगा क्योंकि इसकी बैकग्राउंड का हमें पता होना चाहिए। जो टैक्स हमने लगाया है, इसकी क्या आव यकता है ? पिछली कांग्रेस सरकार ने पिछले बजट सै ान में जो बजट प्रस्तुत किया था उसके अन्दर नौ करोड़ रुपये का घाटा था। जो बजट पास किया था उसमें सरकार ने प्लानिंग कमी ान को यह आ वासन दिया था कि नौ करोड़ रुपये का जो घाटा है उसको अपने रिसोर्सिज़ से पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद प्लानिंग कमी ान बाकी रकम की स्वीकृति देगी। लेकिन सरकार ने इस वायदे को पूरा नहीं किया और इस वायदे को पूरा करने के लिए कोई स्टैप्स नहीं उठाए। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई। हमारे सामने यह समस्या

थी कि इस वायदे को कैसे पूरा किया जाए। हमने प्लानिंग कमी ान से सारे प्लान की स्वीकृति लेनी थी। कांग्रेस सरकार ने प्लानिंग कमी ान को जो कहा था, जो बात हमारे ऊपर लाद कर कांग्रेस सरकार गई थी, उसको पूरा करने के लिए, उस डैफिसिट को, उस गैप को पूरा करने के लिए यह टैक्स लगाना पड़ा। मैं इस बात को जानता हूं कि व्यापारी तबका, जिसने जनता पार्टी के लिए जी–जान से कार्य किया और जिसने हम लोगों को यहां तक पहुंचाया, उन्हें यह टैक्स अखरता होगा। लेकिन फिर भी सरकार को यह टैक्स लगाना जरुरी था इसके साथ साथ ही मैं सरकार से अनुरोध भी करूंगा कि हमें दूसरी स्टेटों को भी देखना चाहिए। जो टैक्स जल्दी के अन्दर लगाया है, यह लगाना आव यक था। हम केवल इसी चीज को नहीं बल्कि सरकार इस बात पर भी विचार करेगी और मुझे पूर्ण वि वास है कि विचार जरूर होगा कि हमारी स्टेट का जौ टैक्स–स्ट्रक्चर है, जिसको पुरानी कांग्रेस सरकार लगा कर गई है, उस पर पुनः विचार किया जाए और देखा जाए कि सेल्ज़ टैक्स या दूसरे जो टैक्स हमने लगाए हैं उनके लगने से कहीं आम ट्रेडर को नुकसान तो नहीं पहुंचता। दूसरी स्टेटों के अन्दर किस दर से टैक्स लगे हैं, इस सारी चीज को देखते हुए टैक्स स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे ताकि इनके अन्दर सं ाोधन कर सकें और जा आव यक टैक्स है उन को रखें, बजट को पूरा कर सकें और इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके अन्दर किसी तबके को असुविधा भी न हो। सरकार ने इस ओर स्टैप्स उठाए हैं। डैफिसिट बजट जो कांग्रेस सरकार छोड़

गई थी उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने कई स्टैप्स उठाए हैं। जो नयी बिल्डिंग्ज़ बननी थीं वे बननी बन्द की गई, टी0 ए0, डी0 ए0 के बारे में भी सरकार ने घोशणा की है कि इसको बन्द कर रहे हैं, यह बात आने समाचार पत्रों में पढ़ी होगी। ये स्टैप्स उठाए हैं ताकि हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठीक रूप से सुधारा जा सके। इसके बाद, पिछली सरकार द्वारा अन–एम्पलायमेंट पर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हरियाणा के अन्दर अन–एम्पलायमैंट बढ़ी है। रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में, पिछले सदन के अन्दर हम बार बार यह आवाज़ उठाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस सरकार ने आते ही अन–एम्पलायमैंट को दूर करने के लिए कदम उठाने भाुरू कर दिए। आप जानते हैं, हरियाणा की 70 प्रति ात आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है और यह आबादी देहातों के अन्दर रहती है। इमने सीलिंग एक्ट पास करके यह तय कर दिया कि एक जमींदार के पास जमीन कितनी चाहिए। इसके बाद परिवार को बढ़ते रहते हैं, जमीन उतनी रहती है। जमीन कोई रबड़ नहीं है जो बढ़ाई जा सके। परिवार बढ़ने से ही लोग बेरोजगार फिरते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता, सिवाये इसके कि वे भाहरों में रिक ाा चलाने के लिए आए। इसी लिए रूरल इंडस्ट्रीज की सरकार ने घोशणा की है कि चार व्यक्ति मिलकर एक योजना बनाएं जिसमें बैकवर्ड क्लासिज़ और हरिजन का ध्यान रखा जाए। इस योजना में एक हरिजन, एक किसान, एक हरिजन या एक बैकवर्ड क्लासिज़ का व्यक्ति होना चाहिए। एक देहात में काम करने वाला व्यापारी या

दुकानदार भी होना चाहिए। ये चार आदमी मिलकर एक यूनिट खोलेंगे और इस तरह के 110 यूनिट हरियाणा के अन्दर खोलने का निर्णय किया गया है। एक–एक यूनिट को एक–एक लाख रुपये का सरकार प्रबन्ध करेगी। दस हजार रुपया इन चार आदमियों को देने पडेंगे, बाकी बैंक से, सरकार सरकारी गारंटी पर, यूनिट को चलाने के लिए रुपया देगी। बैंक जो रुपया देगा उसके बदले में सरकार छह प्रति ात सूद बैंक को दिलवाया करेगी लेकिन अगर बैंक का सूद छह प्रति ात से फालतू हो, जैसे कि आज दस प्रति ातय या बारह प्रति ात है, वह फालतू सूद को सरकार दिया करेगी ताकि बेरोजगारी दूर हो और देहातों में इंडस्ट्रीज ले जाई जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : समय थोड़ा है आप जल्दी खत्म करें।

चौधरी राम लाल वधवा : इसके बाद एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए हमें बिजली की आव यकता है। हमारा टोटल प्लान 148 करोड़ रुपये का है जिसमें से 61 करोड़ रुपया पावर और इरीगे ान के लिए एलान किया है और पिछलें चार महीनों के अन्दर एग्रीकल्चर की बेहतरी के लिए 250 आगमेन्टे ान ट्यूबवैल्ज़, 400 डीप ट्यूबवैल्ज़ और 15 हजार प्राईवेट ट्यूबवैल्ज़ लगाए हैं। इस थोड़े से अर्से के अन्दर इतना काम करके किसान को राहती दी गई है ताकि किसान ठीक प्रकार से अपनी ज़मीन को पानी दे सके। पानीपत के थर्मल प्लांट के बारे में घोशणा हुई

है। यह काफी समय के बाद बनने वाला था लेकिन हमने इस पर इतनी तेजी से काम भुरू कर दिया है कि मार्च महीने के अन्दर ही इसको चालू करने का निर्णय किया है।

जहां तक सैलाब की बात है, इसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय तफसील के साथ बता रहे थे कि एक प्लान 11–12 करोड़ रुपये का है। एक योजना तैयार की है जिसको जल्दी ही चालू किया जाएगा। और इस योजना से सैलाब से निजात मिलेगी। सफाई देहातों के अन्दर कम होती है, इसके लिए एक योजना बनाई गई। आपने सुना होगा, प्रधान मन्त्री तावडू के अन्दर इस योजना का भुभारम्भ करके गए हैं। इस योजना के तहत एक–एक वर्कर, एक–एक हजार आदमियों के पीछे ट्रेंड किया जाएगा और वह देहातों में जाकर आम आदमी की दवा–दारू का ध्यान करेगा। हरियाणा में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने पच्चानवें करोड़ रुपया रखा है। जनता सरकार द्वारा वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने का प्रबन्ध किया जा रहा है और इम इस बात की आ ाा करते हैं कि सरकार 3800 गांवों को पीने के पानी की सुविधा देगी। इसके साथ ही साथ, डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने और भी बातें कहनी थी क्योंकि कुछ ऐसे हालात हैं जिनमें खुद को ही खुद का एहसास नहीं है .....

मुझे खुद को खुद का एकसास नहीं,

मैंने औरों से सुना है कि मैं परे ाान हूं।

मैं कुछ और तत्य भी आपके सामने रखना चाहता हूं परन्तु आपकी आज्ञा है कि समय कम है। अन्त में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता सरकार तेजी के साथ डिवैल्पमैंट के कार्य करने के लिए आगे बढ़ रही है और हमने सुधार करने का नि चय किया है। हम जानते हैं कि पिछली सरकार ताना ाही करती थी। जितनी जिला परिशदें थीं, उनको तोड़ दिया गया था, सरकार ने उनको बहाल करने का निर्णय किया है। पिछली सरकार ने म्यूनिसिपल एक्ट के अन्दर तरमीम की थी जिसके आधार एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए थे, लोक तन्त्र समाप्त कर दिया गया था। ऐक्ट में तरमीम करके लोकल बाडीज़ पर एडमिनिस्ट्रेटर थोप दिए गए थे। जेल में कैदियों की हालत को सुधारने के लिए भी सरकार ने समुचित कदम उठाए हैं। जो व्यक्ति किसी गलती के कारण जेलों में चले गये हैं, उनका जीवन सुधारने के लिये कदम उठाए, उनका जीवन बरबाद नहीं होना चाहिए। इनको कर्जा देने की स्कीम गवर्नमैंट ने बनाई है सरकार ने जेलों में सुधार करने के लिये एक कमी ान बनाया है जिसका नाम है – 'जेल रिफार्म कमी ान' ताकि वे व्यक्ति जब जेल के अन्दर से बाहर आएं तो क्रिमिकल बनकर न आए, सुधारवादी बनकर आएं। यह जो एप्रोप्रिए ान बिल है, इस पर और ज्यादा न कहते हुए, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हाउस इसको स्वीकृति

दे। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझ समय दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री भाम ोर सिंह (नरवाना) : डिप्टी स्पीकर साहब, आज जनता पार्टी सरकार की ओर से सदन के सामने पहली बार रूपये की मन्जूरी के लिये यह ऐप्रोप्रिए ान बिल आया है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह पहली बार मौका मिला है मैम्बरों को कि वे सरकार की जो नीति है, सरकार की जो पालिसी है, उसके बारे में कोई टीका–टिप्पणी कर सकें। ऐप्रोप्रिए ान बिल और कल जो डिमाडंज हाउस के सामने आई हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में यह कहना चाहूंगा कि जनता सरकार ने अपने चुनाव घोशणा पत्र में और उसके बाद पिछले 6 महीने के अर्से में जो मुख्तलिफ लीडरों के जबानी ब्यान के जरिए पौलिसियोयं के एलान किए हैं उसकी रो ानी में जनता सरकार ने एक तरह से यह पहली बार लोगों को कोई सुविधाएं या सहूलियत देने की चेश्टा की है। इनको देखते हुए तो इसे एक मायूसकुन ऐप्रोप्रिए ान बिल कह सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते थे कि जनता पार्टी सरकार ने लोगों से जो बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे उनको यह पूरा करेंगी ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। लेकिन निहायत दु:ख के साथ कहूंगा कि पिछले छह महीने में जबसे दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बनी है और हरियाणा में पिछली चार महीने से, जबसे यहां जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे ला एंड आर्डर की बात है चाहे वह रोजमर्रा की जिन्दगी में कीमतों

की बढ़ौतरी की बात है या चाहे वह हरिजनों और गरीब लोगों को प्रोटेक ान देने की बात है, हर फ्रन्ट के ऊपर जनता पार्टी की सरकार बड़ी भारी नाकामयाब रही है। उन सारे वायदों को पूरा करने में यह असमर्थ रही है जो इन्होंने लोगों से किए थे। ये हर बात के लिए एक बात कह कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार खजाने में कोई रुपया नहीं छोड़ गई है और कांग्रेस की सरकार ने सारी बात को खराब कर दिया है। उपाध्यक्ष महोंदय, मैं नहीं समझता कि जनता पार्टी की सरकार अपनी नालायकी, नाअहलीयत, अपनी इन–डिसिजन्ज को और इसका ऐडहोकिज्म पर चलने का जो तरीका है इसको कितनी देर कांग्रेस की ऐलीबाई (Alibi) में छुपाकर अपना वक्त निकालती रहेगी। बहरहाल, सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों की जो समस्याएं हैं चाहे वह समस्या फ्लड की है, चाहे वह रोजगार की है और चाहे वह ला एंड आर्डर की समस्या है जनता पार्टी की सरकार उनका हल नहीं कर सकी। यह लोगों की रक्षा के लिये अपनी नीति निर्धारित नहीं कर सकी, उन नीतियों का फैसला किसी तरह कर नहीं पा रही है जिनका फैसला इसको अब तक कर लेना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार की लोगों के फायदे के काम, लोगों की सो ाल और दूसरी डिवैल्पमैंट के काम करने से पहले यह जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रदे ा की कानूनी व्यवस्था को अच्छी तरह चला सके। लेकिन निहायत दुःख की बात है कि पिछले चार महीने के अन्दर हरियाणा के चार प्रमुख नगरों जैसे फरीदाबाद,

सोनीपत, रोहतक और दादरी में जिस तरीके से पुलिस की आंखों के सामने बड़े भारी पैमाने पर दुकानों को लूटा गया, भाहर के भीतर मोटरों को आग लगाई गई, सिनेमा घरों के भी ो तोड़े गए, लोगों की इज्जत और माल को बेरहमी से लूटा गया, कानूनी व्यवस्था खत्म हुई, इस प्रकार की कोई मिसाल पिछले तीस सालों में नहीं मिलती। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं, जबसे जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाली है उसके बाद से कत्ल, चोरी, डाके और लूटमार की वारदातें बढ़ गई हैं। आज कोई भी नागरिक अपने आप को सेफ और महफूज नहीं समझता। (विघ्न) आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे हरियाणा में इस बात का वातावरण मौजूद है कि आज हरियाणा का नागरिक अपने आपको महफूज नहीं समझता। आज अगर उसके ऊपर कोई हमला हो जाए, कोई नुकसान पहुंच जाए तो उसको कोई प्रोटैक ान मिलेगी इस बात की आज कोई गारंटी मौजूद नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी सरकार ने पिछले छह महीने में इस बात का बहुत बड़ा ढ़िंढ़ोरा पीटा कि दे ा के अन्दर रूल आफ ला, कानून की व्यवस्था स्थापित करेगी लेकिन मैं सदन के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रूल आफ ला का नाम लेकर कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उसकी मिसाल पहले कभी इस तरह से नहीं मिलती। बहुत बड़े भारी पैमाने पर विरोधी पार्टी, खास तोर पर कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लीडर थे, उनको झूठे मुकदमें बनाकर गिरफ्तार

किया गया। एक रोज के अन्दर 60—70 के करीब सरकारी अफसरों, सियासी विरोधियों और उनके सम्बन्धियों के मकानों के ऊपर छापे मारे गए लेकिन उपाध्यक्ष महोदय खु ाी की बात यह है कि किसी एक मकान से भी इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल बरामद नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर है कि सरकार का मं ाा, सरकार का मुद्दा अपने विरोधियों को बदनाम ओर डिमौरेलाइज करने का था। इस प्रकार की विंडिक्टिवनैस की पालिसी रूल आफ ला के खिलाफ है। इस सकरार की विंडिक्टिवनैस का एक उदाहरण उपाध्यक्ष महोदय मैं यह देना चाहूंगा कि मुकद्दमायय दर्ज कराने से पहले ही रेडियो, टेलिविजन और अखबारों के जरिए सारे वाक्यात की घोशणा करा दी जाती है जो कि मैं समझता हूं रूल आफ ला की बड़ी भारी वायले ान है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेताओं को हथकड़ी लगाई गई, उनका फोटो अखबारों में छपवाया गया जिसका मतलब यह था कि यह सारी विंडिक्टिवनैस की बात थी जो कि रूल आफ ला के बिल्कुल खिलाफ बात थी। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जरूरी बात हाउस में उठाना चाहूंगा। जनता पार्टी ने हरियाणा के अन्दर अपने विरोधियों के खिलाफ इस तरह के मुकद्दमें बनाए जिनका ताल्लुक वि ोश पालिटिकल पार्टी के फंड से है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र को चलाने के लिए यह बहुत गंभीर सवाल है। क्या कोई सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी के फंड के बारे में कोई हिसाब किताब मांग सकती है या नहीं ? मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार को इस पर विस्तर से विचार करना चाहिए। मैं आपके

माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय एक सवाल करना चाहूंगा। जनता पाटी की सरकार जो अभी चार महीने से बनी है इसके बहुत से मंत्री और बहुत से सदस्य हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लोगों से जनता से लाखों रुपया इकट्ठा किया है। क्या जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए तैयार है कि जो रुपया इकट्ठा किया गया है मंत्रियों द्वारा या दूसरों द्वारा उसकी पड़ताल करवाई जाए कि वह रुपया कहां खर्च हुआ या पाटी को दिया गया या अपनी जेबों में डाला गया ? अगर तैयार नहीं तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो मुकद्दमें इन्होंने अपने विरोधियों के विरूद्ध बनाए हैं वे रूल आफ ला के विरूद्ध हैं और वह रूल आफ ला का बड़ा भरी उल्लंघन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बाता कहना चाहता हूं और वह यह है कि हरियाणा के अन्दर पिछले चार महीने से, जब से यह जनता पार्टी की सरकारी बनी है, खास तौर पर हरिजन, गरीब बैकवर्ड क्लास के लोग और वीकर सैक ांज के लोग जो हैं उनसे 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जो उनको मकान, प्लाटस और जमीन आदि दी गई थी, वह वापिस छीनी जा रही है। मैं उदाहरण के तौर पर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे अपने हल्का नरवाना में घरौंदी और ढाबी दो गांव हैं जहां हरिजनों के लिए आवस बस्तियों को बनाने के लिए बैंकों सें कर्जा दिलाया गया सरकार की ओर से प्लाट दिए गये और वहां पर बस्तियां बननी भुरू हो गई लेकिन जनता सरकार

बनने के बाद उनके प्लीन्थ लैवल तक बनें हुए मकानों को रोक दिया गया। हरिजनों ने जो कर्जा लिया हुआ है उसका ब्याज उन गरीबों को देना पड़ेगा लेकिन उधर बस्तियां बनानी बन्द कर दी गई हैं।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके नोटिस में एक बात और लाना चाहता हूं। मेरे अपने हल्के में बीस साल से पीपलया गांव में हरिजन भाई नजूल लैन्ड को का त करते चले आ रहे थे लेकिन अब जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद हरिजनों से वह जमीन वापिस ले ली गई है। इस प्रकार एक नहीं सैंकड़ों मिसालें हैं।

पिछले दो राज़े से असैम्बली के बाहर रिपब्लिकन पार्टी के पांच आदमियों ने धरना दिया हुआ है। धरना जिस बात के बारे में है वह यह है कि फतेहाबाद की तहसील में तीन हरिजनों में से दो को पुलिस ने गोली से मार दिया और एक हरिजन को पुलिस के टाउट ने गोली मारी। इसी तरह से हरिजन लड़की को भी मार दिया। यह इ तहार यदि आप इजाज़त दें तो मैं सदन के पटल पर रख दूं। इस तरह से पांच आदमी असैम्बली के बाहर धरना दिए हुए बैठे हैं लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार की बातें जनता सरकार के आने के बाद हो रही हैं। हरिजनों और गरीबों पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। साथी ही साथ जनता पार्टी के लोगों ने एक ऐसा वातारवरण पैदा कर दिया है कि जब भी कोई हरिजन अपने हक

की बात करता है तो जवाब यह मिलता है कि अब कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है, अम तो जनता पार्टी का राज है। इस तरह से उनको थरैट किया जाता है। आज के दिन, जनता पाट्री की सरकार आने के प चात उनके सम्मान और इज्ज़त की कोई जगह नहीं है और इससे अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप समय का ध्यान रखें क्योंकि और मैम्बर साहिबान ने भी बोलना है।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : आप भी कुछ नम्बर लेना चाहते हैं।

श्री भाम ोंर सिंह : नम्बर तो चौधरी सतबीर सिंह जी ले लें, मुझे नम्बरों की अब आव यकता नहीं है। मैं तो आपकें माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले चार महीने से और छः महीने से जब से हरियाणा में और सैन्टर में जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के भाव आसमान को छू गये हैं। चाय, साबुन, सब्जी, दाल आदि सभी चीजों के भाव दिन प्रतिदिन ऊंचे होते जा रहे हैं। जो गरीब आदमी हैं, मध्यम वर्ग के आदमी उनका जीना ही मु कल हो गया हैं जनता पार्टी की सरकार इन भावों को रोकने में मुकम्म्ल तौर पर नाकामयाब रही है। मैं आपके द्वारा अर्ज़ करूंगा कि ऐसी पालिसी बनायी जाये जिससे कीमतें कम की जायें। उपाध्यक्ष

महोदय, इसी बात को लेकर पिछले महीने की 19 तारीख को आल इंडिया कांग्रेस पाटी् की ओर से सारे हिन्दुस्तान में जलूस निकाले गये। हरियाणा के हर कसबे में एन्टी प्राइस राइज़ के बारे जलूस निकाले गये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान उन बातों की ओंर भी दिलाना चाहता हूं जो इन्होंने अपने चुनाव घोशणा पत्र में लिखी थी लेकिन बाद में सरकार बनने के बाद उन पर नहीं चल रहे हैं। इन्होंने लिखा था कि सरकारी एडमिनिस्ट्रे ान के खर्च में कमी की जायेगी, सादा जीवन व्यतीत करेंगे। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है उसमें कोई आस्टेरिटी की बात नहीं है। जनता पार्टी के मिनिस्टर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं कि उनको इम्पोर्टिड कारें चाहिए (ाोर)

श्री लहरी सिंह महरा : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मैं आपके जरिए मैम्बर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास ऐसी कोई ि ाकायत आयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी वाइंड–अप करें।

श्री भाम ोर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं औस्टेरिटी पर बोल रहा हूं। उसका इस एप्रोप्रिए ान बिल से सीधा सम्बंध है। (विघ्न) मैं अभी एक ही मिनट में वाइंड–अप करता हूं।

श्री भांकर लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे भी बोलने के लिए टाईम मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको टाईम मिलेगा।

श्री भाम ोर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ये औस्टेरिटी के विशय में थोथी बात अपने घोशणा पत्र में लिखते रहे। उस पर अमल करने के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। छोटी–छोटी नौकरियों की भर्ती पर तो इस सरकार ने पाबन्दी लगा दी है। लोगों को रोज़गार देने के विशय में कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। जनता पार्टी के मंत्री, सरकारी कम्रचारी उसी तरह से आज करते हैं जिस तरह से पहले करते थे। इस पार्टी का भी सारा प्रोग्राम वैसे ही चलता है। उनका रहन सहन भी वैसा ही है। वहीं कोटियां हैं एयरकन्डी ानर्ज़ लगे हुए हैं किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं आया है।

एक और भी बात है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि आज के दिन हमारी ऐडमिनिस्ट्रे ान टौप हैवी है। प्रान्त में सबसे ज्यादा आई0 ए0 एस0 और एच0 सी0 एस0 आफिसर हैं जिनके लिए कोई भी काम नहीं है। हर जिले में जितने भी आफिसर हैं, हरेक के पास कारें हैं। हमारे यहां बे ाुमार कारपोरे ान और बोर्ड बने हुए हैं, जिनके अपने रैस्ट हाउसीज़ भी बने हुए हैं। जिनकी फरनि ंग पर लाखौं रुपया खर्च किया गया है। मैं तो आपके जरिये इस

सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो पहली सरकार ने गलतियां की थीं, इस सरकार ने तो उसमें सुधार का वायदा किया था लेकिन इन्होंने तो उसके उल्ट बात की है। इस सरकार ने बोर्डों में, कारपोरे ान्ज़ में, पोलिटिकल आदमियों को पोस्टें देनी भाुरू कर दी हैं। जब पहली सरकार ऐसा करती थी तो यही लोग उनके खिलाफ थे, उस पर अल्जाम लगाते थे लेकिन अम तो ये उस दौड़ में उसको मात करना चाहते हैं। ययह सरकार उसी प्रकार से पालिटिकल आदमियों के जरिए पोस्टों को फिल–अप करना चाहती है। मैंने कल भी जिक्र किया था कि इस किस्म के 6 बोर्ड और कारपोरे ानज़ मौजूद हैं जो एक ही किस्म का काम करते हैं लेकिन छः जगहों पर उनका खर्चा हो रहा है। अगर उन सभी कों इकट्ठा कर दिया जाये तो खर्चा बड़ी आसानी से कम किया जा सकता है और सरकार को बचत हो सकती है। इस प्रकार से जनता पार्टी के वजीरों ने भी सादा जीवन व्यतीत करने का वायदा किया था। इन लोगों ने श्री जय प्रका ा नारायण के बताये हुए रास्ते पर चलने का वायदा किया था और महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर इन लोगों ने भापथ ली थी कि हम सादगी से रहेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यह कौन सी सादगी से रहते हैं इससे अगली बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हें कि यह सरकार कोई भी फैसला चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, नहीं ले सकती है। इनके सारे ही फैसले टोटल इन–डिसीज़न और टोटल एडहोक पर होते हैं।

आजकल हमारे मुख्य मंत्री जी की सेहत ठीक नहीं है। इस बात का हमें बड़ा दु:ख है। हम चाहते हैं कि वे बहुत जल्दी सेहतयाब हों और इस प्रान्त के लोगों की सेवा करें। लेकिन इसके साथ–साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का पर्सनल स्टाफ है वह बिल्कुल ना–अहल है क्योंकि लोगों के काम नहीं होते हैं और उनको चक्कर ही लगाने पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई काम ठीक तरह से नहीं चलता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय अपने परिवार के आदमियों को या किसी प्राइवेट आदमी को अपने काम में मदद के लिए लगा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका ध्यान रूल 230 की ओर दिलाना चाहता हूं–

श्री भाम ोर सिंह : अभी खत्म करता हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार काम करना चाहती है तो उसको कलियर कट काम का डिविज़न करना चाहिए। सरकारी काम चुने हुए आदमियों के माध्यम से होना चाहिए। सरकारी कामों के लिये अगर प्राइवेट आदमी लगाये जायेंगे तो उससे एक्स्ट्रा कांस्टीच्यू ानल सैंटर आफ पावर को जो एलीगे ान यह लोग पहले लगाते रहे हैं, वह अपनी तरह एट्रैक्ट करेंगे। यह बात मैं नहीं कहता खुद जनता पार्टी के एम0 एल0 ए0 आकर कहते हैं जो मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं। मैं इसके साथ ही यहां

पर यह बात भी कहना चाहता हूं कि पिछले दो दिनों से हाउस चल रहा है, उसमें चाहे खुराब का मसला था, चाहे वह नये स्कूल बनाने का मसला था चाहे वह भाराब बन्दी का मसला था या चाहे और कोई भी पालिसी मैटर था, यह निहायत ही अफसोस की बात है कि यह हरियाणा सरकार किसी मसले पर भी कोई फैसला नहीं ले सकी। भाराब बन्दी के मसले पर जिसके बारे में यह जनता सरकार इतना भाोर मचा रही है, उससे आज तक कोई पालिसी डिसीज़न नहीं लिया गया। इनका पालिसी डिसीज़न यह है कि दिल्ली में मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यह फैसला हुआ है। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सरकार से कहना चाहता हूं कि इनकी जो इन–डिसीज़न की पालिसी है, इनकी जो हर बात को टालने की पालिसी है, इससे जनता बड़ी भरी बेचैन है और इससे उसका बड़ा भारी नुक्सान हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बात कहूंगा। हरियाणा सरकार जो अपने आपको गरीब लोगों की बड़ी हितैशी सरकारी बताती थी, उसने तीन महीने के अन्दर ही तीन–चार जो टैक्स लगाये हैं, उससे साफ जाहिर है कि सरकार का मन ाा क्या है, सरकार का करैक्टर क्या है, यह सरकार किन लोगों की बनी हुई है और इस सरकारी की नीति क्या है ? मैं अब आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं। दरअसल सरकार के अन्दर वह तत्व भी मौजूद है जो आर0 एस0 एस0 का है जो इनको डिसीज़न नहीं लेने देता। पुराने जनसंघ और आर0 एस0 एस0 के प्रतिक्रियावादी लोग हैं जो पब्लिक सैक्अर के खिलाफ हैं, पब्लिक डिस्ट्रिब्यू ान सिस्टम के खिलाफ हैं, सरकार

की जो प्रोग्रैसिव और सौ ालिज्म की नीतियां थीं, उनके खिलाफ हैं, वह आज इस सरकार के अन्दर जाकर सरकार को फेल करना चाहते हैं, उसे सेबोटेज करना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है कि वह सरकार को कोइ फैसला नहीं करने देते हैं। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हू।

श्री उपाध्यक्ष : अब श्री सन्त कंवर बोलेंगे।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी खुर ाीद अहमद पदासनी हुए)।

चौधरी संत कंवर: चेयरमैन साहब .....

श्री भांकर लाल : चेयरमैन साहब, मुझे कल भी बोलने के लिये टाईम नहीं मिला। इसलिये मुझे अब टाईम दिया जाये।

श्री सभापति : श्री भांकर लाल जी, आप बैठ जाइये।

श्री भांकर लाल : कल भी मुझे टाईम नहीं मिला। कल सारा दिन भी मुझे टाईम नहीं मिला मैं आप से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि आप तो कम से कम इन्साम करो।

श्री सभापति : भांकर लाल जी, आप कृपया बैठ जाइए।

श्री भांकर लाल : कल भी मैं तीन दफा बोलने के लिये खड़ा हुआ था लेकिन मुझे टाईम नहीं दिया गया। ..... (व्यवधान)

श्री सभापति : भांकर लाल जी, आपके इस रवैये से हाउस में डिस्पिलन कायम नहीं हो सकता अगर आप हाउस को चलने देना चाहते हैं तो आप बैठ जाइये।

श्री भांकर लाल : सभापति जी, मैं जनता पार्टी का एम0 एल0 ए0 हूं। क्या आप मुझे भी बोलने नहीं देंगे ? .....

श्री सभापति : भांकर लाल जी आप बगैर इजाजत के बोल रहे हैं। जो कुछ कहा जा रहा है वह सारा एक्सपंज कर दिया जायेगा। (व्यवधान) अगर आप बगैर इजाज़त बोलेंगे तो आपका कोई लफ्ज़ रिकार्ड पर नहीं आयेगा।

श्री भांकर लाल : मुझे समय तो दे दीजिये।

श्री सभापति : आप जिस तरह से समय मांग रहे हैं, यह समय मांगने का तरीका नहीं है।

श्री भांकर लाल : मैं तो हाथ जोड़ कर समय मांग रहा हूं।

श्री सभापति : देखिये, कोई मैम्बर जिद्द नहीं कर रहा जिस तरह से आप जिद्द कर रहे हैं ..... (व्यवधान) .... आप बैठ जाइये। प्रौपर वक्त आने पर कन्सीडर किया जायेगा, लेकिन इस तरह से नहीं। This is not the proper way to get time.

श्री भांकर लाल : कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था।

श्री सभा पति : सन्त कंवज जी।

चौधरी संत कंवर (हसगढ़) : चेयरमैन साहब, माननीय सदस्य ने जनता सरकार के ऊपर कई इल्जाम लगाये। उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। भाायद वे आज से 6 महीने पहले का भाासन था, उसको भूल गये। उन्होंने यह डैटा उठाकर नहीं देखा कि हरिजनों पर कितने अत्याचार कांग्रेस के समय में हुए। रिवासा काण्ड को भी वे भूल गये ..... (व्यवधान) .... इसका मतलब यह है कि आप उन सबको दबाना चाहते हैं। इन्दिरा जी ने जो एक बात कही है कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसी बात को लेकर तमाम कांग्रेस के जो सदस्य हैं, वे जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जनता पार्टी को तो इस बात का फख्र है कि उन्होंने अपनी सरकार बनने के बाद हरिजनों में और गैर हरिजनों में प्रेम पैदा किया है जो पहले कभी नहीं था। पिछले 30 साल के दौरान ऐसा प्रेम पहले कभी नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कही कारपोरे ान्ज़ की कि कितनी कारपोरे ान्ज़ हैं, जहां पर पोलिटीकल अप्वांयमैंट्स की जाती हैं। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि यह कारपोरे ान किस आदमी ने बनायी थी ? किसने पोलिटीकल अप्वांयमैंट्स भाुरू की थीं ? सारे का सारा जो यह काम किया था यह कांग्रेस सरकार ने ही किया था। एक बात उन्होंने मंत्रियों के खर्च के बारे में कही। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि हमारी जनता पार्टी की सरकार के जितने मंत्री हैं, उनके

खर्चे अगर आप उठाकर देख लें तो 30 साल तक, हरियाणा बनने के बाद इस टाईम तक जितना खर्चा कांग्रेस के मंत्रियों पर हुआ है उसकी तुलना में वह न के बराबर है। एक तो सबसे छोटा मंत्रिमंडल है और दूसरे सबसे कम खर्चा इस जनता के मंत्रि मंडल का है। मुख्य मंत्री के स्टाफ की बात उन्होंने कही। मुख्य मंत्री जी के स्टाफ में मिश्रा और मेहतानी तो हैं नहीं। अगर ये लोग उन्हीं को एफी ीयैन्ट मानते हैं तो उन लोगों के लिये तो भाायद जगह जेल में हो जो कि उनको इन्कवायरी के बाद मिलेगी। अगली बात उन्होंने कही आर0 एस0 एस0 की कि यह सरकार आर0 एस0 एस0 के इ ाारे पर चल रही है। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यह सरकार किसी के इ ाारे पर नहीं चलती। लेकिन आर0 एस0 एस0 का जो योगदान था वह भी उन्होंने भुला दिया। बाढ़ के समय में जबकि हरियाणा में इतनी ज्यादा बाढ़ आयी हुई थी, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों नें आम जनों को फायदा दिलाने के लिये कितना काम किया ? आर0 एस0 एस0 के लोगों ने दिन–रात एक करके जनता को मदद पहुंचायी। हर किस्म की मदद उन्होंने जनता तक पहुंचायी। मेरा कहने का मतलब यह है आर0 एस0 एस0 के लोगों ने जनता को उनकी मुसीबत के समय में पूरा योगदान दिया है। धन्यवाद।

श्री दीप चन्द भाटिया : सभापति जी, मैं फरीदाबाद के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप त ारीफ रखिये, अब मिनिस्टर साहब जवाब देंगे।

श्री दीप चन्द भाटिया : मैं उनकी बातों का जवाब भी देना चाहता हूं।

श्री सभापति : भाटिया साहब, यह तरीका नहीं है। आप त ारीफ रखिये।

चौधरी रिज़क राम : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मेरा निवेदन यह है कि यहां पर एप्रोप्रिए ान बिल पर डिस्क ान हो रही है और उसका स्कोप बड़ा सीमित होता है यहां पर तो डिस्क ान ऐसे चल रही है जेसे कि बजट पर जनरल डिस्क ान हो रही है जिस वजह से सदस्य साहेबान ज्यादा टाईम ले रहे हैं। अगर इन्हीं डिमान्डज़ तक महदूद रह कर हाउस की कार्यवाही चले तो इससे और ज्यादा मैम्बरान को टाईम मिल जायेगा। यह कोई जनरल डिस्क ान तो है नहीं कि हरेक बात पर टीका–टिप्पणी की जा सके। आप इस बात पर गौर फरमायेंगे।

श्री सभापति : आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। इसीलिये मैंनें अब मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिये काल–अपोन कर लिया है ..... (व्यवधान) .....।

12.00 बजे **सिंचाई एवं विद्युत मन्त्री** (श्री वीरेन्द्र सिंह) : चेयरमैन महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य चौधरी रिजक राम ने कहा कि यह जो बहस थी यह ऐप्रोप्रिए ान बिल पर होनी चाहिए

थी। परन्तु कांग्रेस पार्टी के नेता और हमारे माननीय सदस्य चौधरी भाम ोर सिंह ने इस मौके से फायदा उठाकर कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जिनका जवाब देना सरकारे के लिए बहुत जरूरी हो गया हैं चौधरी भाम ोर सिंह को मैं एक अर्से से जानता हूं। मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है और मैं समझता था कि ये निहायत संजीदा और जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी की बात कहेंगे। इन्होंने जो इस किसम की बात कही है उसके बारे में अन्दरूनी तौर पर ये भी समझ रहे हैं कि वे गलत कह रहें हैं लेकिन बाहरी तौर पर मजबूर हैं इसीलिए इस प्रकार की बात इनको कहनी पड़ी हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि जनता पार्टी हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है। तीन महीने इस सरकार को बने हुए हो गए हैं और उसके लिए उन्होंने फतवा दे दिया कि जनता पार्टी हर फ्रंट पर फेल हो गई है। इन्होंने कहा कि हर पार्टी का अपना–अपना फंड होता हैं ऐसा भी कहीं हुआ है प्रजातन्त्र के अन्दर कि किसी पार्टी के फंड के ऊपर छापा मारा गया हो। चेयरमैन साहब, किसी प्रजातन्त्र दे ा में ऐसा भी कहीं नहीं हुआ कि पार्टी के नाम से फंड इकट्ठा किया जाए और उसे लोग अपने घर में लेकर बैठ जाएं। अपनी ऐ ा और अय्या ाी के लिए बरतें। ऐसा करना जुर्म है और ऐसे मुजरिम को जनता पार्टी बर्दा त नहीं करेगी (तालियां) और ऐसे लोगौं के खिलाफ एक ान लिया जाएगा। अगली बात मेरे मोहतरिम दोस्त ने कही कि जनता पार्टी के मैम्बरों ने भी सदस्य, एम0 एल0 ए0 बनने के बाद, वजीर बनने के बाद धन बटोरा है। पिछले सै ान में भी इन्होंने ऐसी बात कही

थी और आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने इनसे कहा था कि कोई इंस्टान्स हो तो तुम दो अगर कोई बात होगी तो उसकी इन्क्वायरी की जाएगी। मेरा ख्याल है मेरे लायक दोस्त .....

श्री भाम ोर सिंह : चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री यह जो बात कह रहे हैं यह बिल्कुल गलत है। मुख्य मंत्री ने कोई ऐसी बात चैलेन्ज नहीं की थी और न उन्होंने यह कहा था कि अगर कोई इंस्टान्स दें तो सुनेंगे। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी।

श्री वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, बात यह है जहां तक मुझे याद है प्रोसिडिंग्ज पिछली देखी जा सकती हैं। उन्होंने कहा था और मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि कोई इंस्टांस दें और अगर यह साबित हो जाता है कि गलत तौर पर धन बटोरा है तो कार्यवाही की जाएगी और मैं उनको सरकार की ओर से वि वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे जनता पार्टी का नुमांइदा हो चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो भ्रश्ट आदमियों को जनता पार्टी की सरकार कभी माफ नहीं करने वाली है। अगली बात मेरे लायक दोस्त ने कही कि हरिजनों के साथ बड़ा अन्याय होने लगा है। चौधरी भाम ोर सिंह भूल गए आज से छह महीने पहले जब नसबन्दी भाुरू हुई तो अस्सी प्रति ात नसबन्दी पिछली कांग्रेस सरकार ने हरिजनों की थी (ोम)। चौधरी भाम ोर सिंह सुनार बीड़ वाले कांड को भूल गए जब चौधरी चांद राम को 27 हजार हरिजनों को दिल्ली की जेलों में ले जाना पड़ा। आज यह

हरिजनों के बड़े खैरखाह और हमदर्द बनने चले हैं। लेकिन क्ताएं भार्म लिहाज दुनिया से चली गई। चेयरमैन साहब, पिछले तीस साल यानी 1947 से जब से दे ा आजाद हुआ तब से कांग्रेस पार्टी दे ा पर राज करती रही और अफसोस की बात यह है कि आज से 20–25 दिन पहले ऐन्टी प्राइस रैली करने चले थे जैसे इस महंगाई की जिम्मेदार जनता पार्टी हो या जनता पार्टी की सरकार हो। कोई भार्म लिहाज नहीं है। एलानिया कहते हैं कि प्राईसिज ऊंची चली गई। इनको कौन ले गया ऊंची ? कोई भार्म नहीं है .....

चौधरी गंगा राम : आन ए प्वाइंट आर्डर, चेयरमैन साहब, मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि जनता पाट्री में अगर अब भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो धन लेता है, मालाएं लेता है तो उसके खिलाफ एक ान लिया जाएगा और माननीय मंत्री ने कहा कि इस बात को कोई इंस्टांस दें। मैं मन्त्री जी को एक इंस्टांस देना चाहता हूं क्योंकि यह टौपिक आया है (व्यवधान)

Mr. Chairman : It is not a point of order. It is an information which you can supply to the Hon. Minister privately.

चौधरी गंगा राम : मैं एक इंस्टांस देना चाहता हूं .....

Mr. Chairman : This is not a place to be used like this. Please take your sent (Interruption).

चौधरी गंगा राम : आप सुनिए तो सही .....

Mr. Chairman : Please take your seat. This is not a point of order.

चौधरी गंगा राम : आप मेरी बात तो सुनिए ––––– (ाोर) –

Mr. Chairman : It is not a point or order. Please take your seat.

श्री वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, मैं आपकी मारफत अर्ज कर रहा था कि माननीय सदस्य को बड़ा दर्द है महंगाई का और आगे इन्होंने फरमाया कि जनता पार्टी के लोगोंने ने अपने मैनिफैस्टों में वायदा किया था कि सादगी अपनाएंगे। आप माननीय सछसय की ड्रैस देख लें। पहनावा देख लें और हमारे किसी भी मन्त्री का पहनावा देख लें और मैं यह वि वास दिलाता हूं कि इस स्टैन्डर्ड, इस सादगी की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। चमक दमक की तरफ हमारा न कोइ रुझान है और न आगे रहेगा (व्यवधान)। अगली बात मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि मेरे माननीय भाई ने कहा कि बहुत बोर्ड जनता पार्टी ने बना दिए। ये बोर्ड इनकी क्रिए ान ही हैं और हमने उसके लिए भी जो उन्होंने कहा कि बोर्ड बनाए (व्यवधान) कहा तो यही थी लेकिन खैर अब यह कह रहे हैं कि मैंने यह सवाल किया था कि बोर्डों को तोड़ा नहीं है। चेयरमैन साहब इनके जो तीस साल के गुनाह हैं उनको हम अभी पढ़ भी नहीं पाए हैं। आहिस्ता–आहिस्ता जितने इनके गुनाह तीस साल के होंगे वे नोटिस में आएंगे और जिनसे

जनता दु:खी है उन पर जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से गौर फरमाएगी। अगली बात इन्होंने कही कि सी0 एम0 का स्टाफ बड़ा नाअहल है। चौधरी सन्त कंवर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया है और मैं समझता हूं कि ज्यादा कहने की आव यकता नहीं हैं महतानी और मिश्रा अब इस राज्य में नहीं हैं (व्यवधान) अगली बात इन्होंने कहीं कि सी0 एम0 के घर प्राईवेट आदमी ऐसे रहते हैं जो कि सरकारी काम काज में दखलअन्दाजी करते हैं। मेरा ख्याल है कि चौधरी भाम ोर सिंह कई बार मुख्य मंत्री के घर जा चुके हैं और मेरा यह भी ख्याल है और पक्का वि वास है (व्यवधान) और मुझे यह भी पता है कि बहुत दिनों से वे एक दूसरे को जानते हैं। चौधरी भाम ोर सिंह सी0 एम0 साहब के घर में रहने वाले हर व्यक्ति से भली प्रकार से वाकिफ हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मेर ख्याल में उस घर में नहीं है जो सरकारी कामकाज में दखलअन्दाजी करता हो। अगर कोई है तो जनता पार्टी के एम0 एल0 ए0 का क्यों बहाना करते हैं। यह खुद बताएं और मैं वि वास दिलाता हूं कि कोई भी जनता पार्टी का मैम्बर सरकारी कामकाज में दखलअन्दाजी नहीं करेगा। सरकारी कामकाज में दखलअन्दाजी सुरेन्द्र और संजय की चलती थी यहां पर किसी को दखलअन्दाजी नहीं चलती।

अगली बात मेरे भाई ने कही कि सो ालिज्म जो पहली सरकार लाना चाहती थी चूंकि इस जनता पार्टी में आर0 एस0 एस0 और जनसंघ के रिऐक ानरी लोग आ चुके हैं (व्यवधान)

इसलिए उनकी वजह से ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते। चेयरमैन साहब, जो पिछला सो ालिज्म था, गरीबी हटाओ का नारा था, उस सो ालिज्म में हम तो सिर्फ यह देख पाए और यही तजुर्बा जनता का है और इसलिए जनता ने उनको रिजैक्ट करके रख दिया है, वह सो ालिज्म जनता के लिए नहीं था ? धन बटोर कर अपने रि तेदारों, अपने पिट्ठुओं और दलालों में बांटने का वह सो ालिज्म था।

अन्त में मेरे भाई ने कहा कि यह सरकार इन–डिसिज़न की सरकार है।, भाराब बन्दी आज तक बन्द नहीं हुयी। भाराबनो ाी की पालिसी के बारे में कल हाउस में स्टेटमैंट दी गई थी कि जनता पार्टी का यह प्रोग्राम है कि चार साल के अन्दर अन्दर भाराब नो ाी बन्द कर दी जाएगी और इसस ज्यादा ये और क्या चाहते हैं। इतना बड़ा डिसीज़न, इतना बड़ा इनैंन ाल लास इस सरकार ने सहने का वचन लिया है। हम समाज को सुधारने के लिये, जनता को रिलीफ देने के लिये इतना बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं। अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि चौधरी भाम ोर सिंह जी ने स्वयं यहां कहा है कि इन बातों को यहां कहने को आत्मा नहीं मानती थी परन्तु हालात के मुताबिक कहनी पड़ीं। इन अलफाज़ के साथ मैं, चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

मास्टर ि ाव प्र ाद (अम्बाला भाहर) : आदरणीय चेयरमैन साहब, मेरे एक मोहतरिम साथी ने यहां पर कुछ बातें

जनता पार्टी के बारे में कहीं कि इस राज्य में काफी अत्याचार हुये हैं। भाायद मेरे मोहतरिम साथी वह 19 महीने का समय भूल गये हैं, भाायद वे मेरे उन हरिजन भाईयों को भूल गये जिनके आपरे ान इस पुरानी सरकार के अत्याचारों के कारण जबरदस्ती हुए जो कि अभी तक हस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं या अपने घरों में पड़े हुए सिसक रहे हैं। भाायद ये लोग भूल गये, कांग्रेस राज्य के उस लाठी चार्ज को जो लोगों पर की गई। भाायद ये भूल गये उस कांग्रेस राज्य में पीपली के गोली कांड को। जनता पार्टी के राज्य में अभी तक कोई अत्याचार नहीं हुआ, कहीं किसी का जबरदस्ती आप्रे ान नहीं किया। जनता पार्टी ने, चेयरमैन साहब, जितना जनता को रिलीफ दिया है उसको जनता ही जानती हैं जो आई0 ए0 एस0 आफिसर्ज़ हैं यहां उनके बारे में बताया गया, ये सारे आफिसर कांग्रेस राज के ही अप्वांयट किये हुये हैं। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जनता पार्टी के राज में आने के बाद उन्होंने अपने रवैये को, अपने काम करने के ढंग को बदल लिया है और काफी प्रोग्रैस की है। वे लोगों से एडजस्टमैंट कर के चल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और इससे लोगों को राहत मिल रही है। हमारे कुछ मोहतरिम साथियों को जनसंघ और आर0 एस0 एस0 के बारे में फोबिया हो गया है। जिस तरीके से इन्दिरा गांधी को रात को सोते, जागते, उठते बैठते, खाते पीते जनसंघ और आर0 एस0 एस0 दिखाई देता था भाायद मेरे साथी को भी उसी प्रकार रात को जागते, उठते बैठते, वहीं चीज़ दिखायी देती है, मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि उस

समय जनसंघ प्रतिक्रियावादी नहीं था जब 1967 में श्रीमान जी कांग्रेस की टिकट से कामयाब होकर राव साहब की वज़ारत में आये (विघ्न)

श्री भाम ोर सिंह : चेयरमैन साहब, मैं कांग्रेस टिकट से जीत कर नहीं आया था।

मास्टर ि िव प्र ाद : यह बात मैं गलत कह गया हूं। चौधरी साहब विरोधी पक्ष की सहायता से जीत कर आए थे। चेयरमैन साहब, उस समय भी राव साहब की वज़ारत के साथ जनसंघ था श्रीमान जी स्टेट मिनिस्टर बनकर आये तो क्या उस समय जनसंघ प्रतिक्रियावादी नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक आर0 एस0 एस0 का सवाल है। 1962 में जब भारत की चीन के साथ लड़ाई हुई थी उस समय आर0 एस0 एस0 के लोगों ने हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू का साथ दिया था और पंडित जी ने 26 जनवरी को परेड के अन्दर आर0 एस0 एस0 के लोगों को बुलाया था। इस बात को भाायद ये लोग भूल गये हैं। इसी तरह से 1965 की लड़ाई में जब आर0 एस0 एस0 के लोगों ने सहयोग दिया था तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर भाास्त्री ने उनको मान सम्मान दिया था और 26 जनवरी, के कार्यक्रम में आर0 एस0 एस0 वालों को वि ोश तौर पर निमन्त्रित किया था। भाायद वे इस बात को भी भूल गये हैं। फिर 1971 की लड़ाई में भी आर0 एस0 एस0 के लोगों ने सरकार का साथ दिया। क्या ये लोग इन सब कुर्बानियों को भूल गये हैं ?

आर0 एस0 एस0 सदा ही दे ा की सेवा के लिये आगे रहा है। लेकिन आर0 एस0 एस0 का फोबिया जिस तरह से इन्दिरा गांधी को था उसी तरीके से मेरे साथी को भी फोबिया हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इसका सम्बन्ध राजनीति से नहीं है लेकिन फिर भी मेरे साथियों को आर0 एस0 एस0 ही दिखायी देता है। जहां तक सो ालिज्म के लाने का सवाल है, या यह सवाल है कि प्रोग्रेसिव कामों में आर0 एस0 एस0 वाले या जनसंघ वाले रोड़ा अटकाते हैं, यह बात ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह कांग्रेस के लोग ही हमारे काम में रोड़ा अटकाते हैं। जो इस प्रकार के लोग हैं उनके बारे में मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार उन आफिसर्ज़ का ध्यान रखे जिनका सम्बन्ध अभी तक उन कांग्रेस के पुराने साथियों से है। इस बारे में हमारी सरकार छानबीन कर रही है ताकि इस प्रकार के लोगों के ऊपर जो कि हमारी सरकार की पालिसी के मुताबिक नहीं चल रहे हैं ध्यान रखा जाए। मैं अपने साथी को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो फोबिया उनके दिमाग में हैं उनको भी निकालें और जो दे ाभक्त हैं उनके बारे में इस प्रकार के विचार जो उनके दिमाग में हैं उनको भी निकाल दें। इन भाब्दों के साथ चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने का समया दिया।

श्रम तथा रोजगार मन्त्री (श्रीमती सुशमा स्वराज) : सभापति महोदय, आज हरियाणा विनियोग विधेयक पर बहस होते

वक्त और कल अनुपूरक मांगों पर चर्चा–परिचर्चा करते वक्त जनता पार्टी की नीतियों की काफी आलोचना की गई। हम इस आलोचना का तहेदिल से स्वागत करते ब ार्ते ये आलोचनाएं किन्हीं तथ्यों पर आधारित होतीं लेकिन निराधार आलोचना करना एक मजबूत विपक्ष को भाोभा नहीं देता। यह बात मैं आपकी मार्फत विपक्ष को कहना चाहूंगी कि विपक्ष के लोगों ने आज यहां बात करते वक्त यह बात कही कि जनता सरकार ने झूठे मुकद्दमें बनाए जिनका उदाहरण पिछले 30 साल में नहीं मिलता (विघ्न) उन्होंने यह कहा जनता पार्टी ने कुछ झूठे मुकद्दमें बनाए जिनका 30 साल में नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि विपक्ष की याददा त बहुत कमजोर है और हाल ही में घटा 19 महीनों का काला इतिहास उनके ज़हन से बहुत जल्द मिट गया हैं अच्छा होता कि का ा यह सारे का सारा इतिहास हिन्दुस्तान की तारीख़ से कट जाता ताकि आगे आनी वाली नसलें पुराने भाासकों, भूतपूर्व भाासकों को कलंकित करने से रुक जातीं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज केवल उन्हीं लोगों के कहने से हिन्दुस्तान की जनता उस इतिहास को भुलाएगी नहीं, उनके ज़हन से इतनी जल्'दी वह दाग समाप्त नहीं होगा। तो किस तरह से कार्य इन लोगों ने किए थे और आज ये कहते हैं कि झूठे मुकद्दमें बने हैं। मैं इनको बताना चाहती हूं कि हमने मुकद्दमें बनाने से ही वंचित कर दिया था (थम्पिग) तुम लोगों ने रातों रात अध्यादे ा जारी करके हमें अदालतों के दरवाजे खटखटाने से वंचित कर दिया था, हमने कम से कम आपका वह अधिकार तो नहीं रोका। जिन लोगों

ने न्यायपालिका को चन्द लोगों के हाथ की कठपुतली बना दिया था आज वही लोग उन्हीं न्यायालों के सामने जाकर अग्रिम जमानत की अर्जियां पे ा कर रहे हैं। हमें इस बात का गौरव है कि आज जनता पार्टी ने उस जुडि यरी को रैस्टोर किया है और उन्हीं जज़िज़ के द्वारा आज लोगों को अग्रिम जमानतें दी जा रही हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जनता पार्टी के एम0 एल0 एज़0 यह बात कहते हैं। मैं विपक्षी लोगों को यह बताना चाहूंगी कि जनता पार्टी के एम0 एल0 एज़0 यदि आलोचना करते हैं तो यही तो प्रजातन्त्र का सही रूप है यानी जन प्रतिनिधि का सरकार से जब अंकु ा उठ जाता है तो प्रजातन्त्र समाप्त हो जाता है। आज अगर जन प्रतिनिधियों का सरकार पर अंकु ा लगा हुआ है तो यह प्रजातन्त्र का सही रूप है। इसके अलावा कुछेक बातें जो कल कही गई थीं उनका भी जवाब मैं आज दे देना चाहूंगी। विपक्ष बैंचों पर बैठे हुए एक माननीय सदस्य ने लेबर असंतो ा का सवाल उठाया था। क्योंकि इसका सीधा संबंध मुझ से है इसलिये मैं जवाब देने के लिये हाजिर हुई हूं ताकि सरकारी की नीति स्पश्ट करके मैं अपने माननीय सदस्य की तसल्ली करवा सकूं। हरियाणा में मजदूरों की दुर्द ाा थी और उनके साथ अत्याचार हो रहा था इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इसकी पूरे तौर पर जिम्मेदारी पुरानी सरकार की है जिसने मजदूरों की आवाज को बिल्कुल दबा दिया था, मजदूरों का भाोशण करवाया जा रहा था और नाजायज दबाव डलवा कर, श्रमिक प्रतिनिधियों को खरीद कर, सरकारी अधिकारियों को खरीद कर और मन्त्रियों को खरीद

कर समझौते करवाए जाते थे। आज यदि लेबर अन–रैस्ट प्रान्त में है, आज यदि प्रान्त में श्रमिक असंतोश है तो वह असंतोश इस बात का सबूत है कि आज मजदूरों की दबी आवाज को खोल दिया गया है, आज मजदूरों के गले में पड़े उस फंदे को खोल दिया गया है। आज मजदूर सड़क पर आकर भी अपना अधिकार मांग सकते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगी कि जितने भी समझौते करवाए गए हैं अगर आप उन समझौतों को पढ़ कर देखें तो पाएंगे कि सभी समझौते मजदूरों के हक में करवाए गए हैं। हर एक समझौते में 15 रुपये से लेकर 35 रुपये तक की वृद्धि करवाई गई है। जितने मजदूरों के कानूनों को तोड़ा गया था, जिस तरह के समझौते आपात स्थिति में करवाए गए थे दवाब डाल कर उनको तोड़ कर नये समझौते करवाए गए हैं। जहां तक प्रान्त में श्रमिक असंतोश की बात है मैं उनके सामने फिग्गर्ज़ रख सकती हूं कि फरीदाबाद में मेरे द्वारा इस मंत्रालय का कार्यभर संभालने के बाद 33 हड़तालें हुई थीं और तीन महीनों के अन्दर 23 हड़तालों का समझौता करवाया जा चुका है केवल मात्र 10 हड़तालें जारी हैं। वह हड़तालें न हों और श्रमिक स्थिति की रिपोर्ट एक हफ्ते के बाद श्रम मन्त्री द्वारा मंगाई जाती थी उसको अब सप्ताह की बजाए रोज कर दिया गया है ताकि भााम को हर रोज हमें पता चल सके कि प्रान्त में किस जगह कौन सी स्ट्राइक की गई है ताकि भााम को हर रोज हमें पता चल सके कि प्रान्त में किस जगह कौन सी स्ट्राइक की गई है और इसके साथ साथ सभी ट्रेड यूनियनज़ के रिप्रजैटेटिवज़ को बुला कर यह हिदायत दे दी गई है कि स्ट्राइक

करने से पहले उन लोगों को नोटिस दे देना चाहिये किन्हीं एक्सैप ानल सरकमस्टांसिज़ को छोड़ कर जहां ऐसा नोटिस न दिया जा सके। यह इसलिये किया गया है ताकि उस नोटिस के दौरान ही स्ट्राइकर्ज की समस्या का समाधान करवा दिया जाए और स्ट्राइक करने की नौबत ही न आए। स्ट्राइक के नोटिस की भी नौबत न आए इसके लिये भी सरकार ने नीति निर्धारित की है कि हमारी जो विभागीय बैठक बुलाई जाती थी उसके बारे में यह फैसला कर दिया गया है कि साल के हर तीसरे महीने में बैठक बुलाई जाएगी और जो भी लक्ष्य क्षेत्रीय इन्स्पैक्टर, लेबर इन्स्पैक्टर या लेबर अफसर को दिये जाएंगे उनकी हर तीसरे महीने रिपोर्ट मांगी जाएगी कि उन्होंने उस लक्ष्य को पूरा किया है या नहीं। फैक्टरी इन्स्पैक्टर्ज़ की हर महीने मीटिंग बुलाने का प्रावधान कर दिया गया है और उनके लिये लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं। जब लेबर अन–रैस्ट होता है, उसमें कोई कार्य नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि सरकार ने ज़ो कानून बनाए हुए हैं उनकी इम्पलीमैंट ान नहीं हो रही है इसलिये कसिलिए ान म ानरी जा करके देखेगी, लेबर इन्स्पैक्टर चैक करेगा और फैक्टरी इन्स्पैक्टर चैक करेगा कि किन–किन कानूनों की उल्लंघना हो रही है लेकिन एक बात मैं बता देना चाहती हूं कि आज तक यदि श्रमिक असंतोश नहीं हुआ तो उसका कारण केवल मात्र यह था कि समझौते यदि होते भी थे तो समझौते खरीद जाते थे। आज मैं सदन के सामने यह घोशणा करती हूं कि अब जो समझौते हो रहे हैं चाहे इनमें कुछ देर हो रही हो उन समझौतो को नहीं

खरीदा जा रहा है ओर न बेचा जा रहा है बल्कि आज समझौते करवाए जा रहे हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि बहुत जल्द हम इस श्रमिक असंतोश पर काबू पा लेंगे और आगे से प्रान्त में श्रमिक असंतोश न हो और इस तरह की नौबत प्रान्त में कभी न आए इस तरफ भी पूरे–पूरे कदम उठाएंगे। धन्यवाद।

वित्त मंत्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : चेयरमैन साहब, जहां तक डिमांडज़ का ताल्लुक है उन पर तो मैंने कल काफी कुछ कह दिया था लेकिन दूसरे कुछ साथियों ने आज डिमांडज़ पर बोलने की बजाए और बातें कहनी भ्ारू कर दीं। दो तीन सवाल डिमांडज़ के बारे में भी हमारे कुछ साथियों ने उठाए हैं। जैसे हमारे स्वामी आदित्य वे ा जी ने कहा कि ये लोन वगैर न लिये जाने चाहिये थे। तो ये लोन तो सरकारें लेती रहती हैं ताकि डिवैल्पमैंट तथा प्लानिंग कमी ान की परमि ान ली जाती है। इसी तरह से यह जो लोन है यह ज्वांयट पंजाब के अन्दर लिया गया था। सन् 1966 में जब रिआग्रेनाइजे ान हुई तो यह लोन हमारे हिस्से में आया। पिछली कांग्रेस सरकार इसको पे नहीं कर सकी इसलिये अब जनता सरकार इसको पे करना चाहती है। (विघ्न) इसके बाद बाबू मूल चन्द जी ने कुछ वायदे याद दिलाये कि जो वायदे जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त किये थे उनको पूरा किया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी की जो नीति है वह कुछ हद तक इन मांगों से भी साफ हो जाती है। क्योंकि

जनता पार्टी ने इस कृशि प्रधान प्रदे ा के लिये इन मांगों में किसानों को सबसिडी देने के लिये एक करोड़ 27 लाख रुपये मांगा है। इससे यह स्पश्ट हो जाता है कि जो हमारी घोशणा थी कि जनता सरकार बनने के बाद राज्य में कृशि को प्राथमिकता दी जाएगी यह उसका सही रूप है। सभी सदस्यगण जानते हैं कि आज के युग के अन्दर खेती के लिये खाद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उपज बढ़ती है और प्रदे ा में खु ाहाली आती है। इसके बाद जो दूसरी डिमांडज़ हैं उन पर कल डा0 मंगल सैन जी ने काफी विस्तारपूर्वक बताया था। यह जनता पार्टी की सही नीति की मिसाल है कि ट्रेनिंग लेने वालों को प्र ि ाक्षण केन्द्रों में पहलें जहां रा–मैटिरियल के लिये 10 रुपये मिलते थे अब वह 25 रुपये कर दिये गये हैं। यह इसलिये किये हैं कि हम साथ साथ स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिये भी साधन जुटाना चाहते हैं। इसके बाद मैं जो बात कहूंगा उसे मैं एक महत्वपूर्ण घटना कहूंगा कि सौ मन चूहे खाकर बिल्ली हज को चलीं मेरे भाई (श्री भाम ेर सिंह की तरफ इ ाारा) अपने असली रूप में हाउस के अन्दर आए और कहा कि वीकर सैक ान की प्रोटैक ान नहीं हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब से हरियाणा में जनता सरकार बनी है उसके बाद अगर किसी वीकर सैक ान के ऊपर ज्यादती हुई है, या उसके हक के ऊपर या मान और सम्मान के ऊपर धक्का पहुंचा है, हमने एक ान न लिया हो। आज भी जितने अखबार हैं ये पूंजीपतियों के ही हैं अगर इन बातों में कोई सच्चाई होती तो ये बातें अखबारों में न आतीं। मेरे भाई वैसे ही पम्फलैट लिये फिरते

हैं पता नहीं कहां से छपवाया है। क्या मेरे भाई रिवासा कांड को भूल गए। कहां थे वे उस वक्त ? उस वक्त तो ये बंसी लाल के पैरों को हाथ लगाया करते थे। जब रिवासा और पीपली में इतने जुल्म हो रहे थे तब ये कहां गए थे ? उस टाइम उन घटनाओं को देखकर इन्हें भार्म नहीं आई ? जिस वक्त पीपली में गोली चली थी तो भाई भाम ोर सिंह कहां थे ? (विघ्न एवं भाोर)

श्री सुरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। चेयरमैन साहब पहले आप इनको सन लें (ाोर) यह क्या बता रहे हैं .....

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) : मैंने तेरे बाप को बता दिया था (ाोर)

श्री सुरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, रिवासा कांड के ऊपर एक कमी ान इन्कवायरी को बिठाया हुआ है और उस कमी ान के सामने कुछ ऐवीडैंस हो चुकी हैं। किन हालात के अन्दर यहां रिवासा का जिक्र आ रहा है और कैसे यह ऐवीडैंस लीड की गइ ? They must wait for the findings of the Commission. (Noise)

Mr. Chairman : Please take your seat.

राव बीरेन्द्र सिंह : आप कैसे समझे कि यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं है। अगर आप इस चीज को देख लेते कि सब–जुडिस मामला यहां पर नहीं उठाया जा सकता तो प्वांयट आफ आर्डर को समझने की जरूरत ही न पड़ती।

Mr. Chairman : There was no reference to the merits of the case. Only instance was mentioned.

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : पीपली और नगीना के अन्दर जो कांड हुए उस समय हरिजनों और दूसरे साथियों के साथ कितने जुल्म हुए लेकिन आज ये हरिजनों के प्रति मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उस वक्त कहां थे ये ? उन्होंने दस–दस साल मेहनत करके जो जमीनें बीजाई के काबिल बनाई थीं वहां से उनको धक्का दिया गया। ऐसे ऐसे इन्स्टांसिज हैं कि हरिजनों की औरतों के जेलों के अन्दर बच्चे हुए हैं (ोम भोम की आवाजें) और फिर ये जनता सरकार के ऊपर लांछन लगाते हैं। यह बात मुझे समझ नहीं आती कि जनता पार्टी पर लांछन क्यों लगाते हैं कि जनता पार्टी के राज में ला एंड आर्डर की सिचुए ान खराब है। चोरों के वास्ते कैसी प्रौटैक ान चाहिए। आपने धन कमाया है, आपको कैसे प्रोटैक्ट किया जाए। कहते हैं रूल आफ ला नहीं है, रूल आफ ला तो आपने उस दिन खत्म कर दिया था जब 26 जून 1975 को दे ा में एमरजैंसी लगाकर बेगुनाह लोगों को ज़ेल की सीखचों के अन्दर बन्द कर दिया गया था अदालत के दरवाज़े बंद किए गए थे। जनता पार्टी ही है जिसने अपना वायदी ही पूरा नहीं किया बल्कि तुम्हें अदालत तक जाने का हक दिया। अगर हम रूल आफ ला पर न चलते तो हमारे ऊपर कौन सी पाबन्दी थी, जिस दिन जनता ने हमें भाक्ति दी थी, हम तुम्हें जेल के अन्दर ठोक देते, अदालतों तक पहुंचने ही न देते। वह मीसा के माम पर कहलाने वाला कानून तुम्हारे ऊपर लागू कर देते। यह बात कहना

कि फण्ड्ज इकट्ठे किए गए ..... (श्री सुरेन्द्र सिंह की तरफ से विघ्न)

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, इनको भाराब पीने के केस में पकड़ लिया गया। (व्यवधान) .....

Mr. Chairman : Please take your seat. There should be no shouting. Do not disturb the proceeding of the House.

Shri Surrender Singh : On a point of Personal Explanation.

Mr. Chairman : There is not point on which you want to explain your personal conduct.

राव वीरेन्द्र सिंह : इन्होंने इन पर इल्जाम लगाया है .... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह : मैंने आज तक भाराब पी नहीं, अगर ये अपनी बात बताना चाहते हैं तो बता दें ..... (व्यवधान)

Mr. Chairman : Please do not discuss anything between youselves.

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : चेयरमैन साहब, जिस दिन जनता पार्टी के मन्त्रियों ने भापथ ली थी, उस वक्त यह कहा था कि हम 5 साल तक किसी से गले में रुपयों का हार नहीं डलवायेंगे। आप देख लें कि किसी मन्त्री ने अपने गले में हार नहीं डलवाया। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकारे के मन्त्रियों ने

बड़ी–बड़ी मालाएं डलवाई। कहा जाता था कि आज बंसी लाल जी पधार रहे ळें, आज कोई और पधार रहा है। माला के लिए लोगों के गेहूं के और चीने के कोटे बिकवा दिए जाते थें आज ये जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इन हालात के अन्दर जो इन्होंने इल्जाम लगाया है, यह वही बात है जैसे नौ सौ मन चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। ये हमारे ऊपर लांछन कैसे लगाते हैं ? मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक बच्चा अपने गुरू से पूछता है कि सबसे ज्यादा बे ार्म आदमी कौन है ? उसने कहा कि कांग्रेसी इस दे ा के अन्दर सब से ज्यादा बे ार्म हैं। आज हमने हाउस के अन्दर भी देखा है कि इनको भार्म नहीं है ..... (व्यवधान) ....

श्री भाम ोर सिंह : चेयरमैन साहब, इस लफज को वापस लिया जाए। He should be asked to withdraw these words.

Shri Shamsher Singh : This is unparliamentary and he should withdraw it.

Mr. Chairman : It is not.

श्री भाम ोर सिंह : यह तो अनपार्लियामेंटरी है।

Mr. Chairman : Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Chairman: Question is –

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Chairman : Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Chairman :Question is –

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be passed.

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़) : चेयरमैन साहब, जनता पार्टी की तरफ से, जमहूरियत को बचाने के लिए बड़े लम्बे लम्बे वायदे किए गए। जन तन्त्र को बचाने के लिए बड़े सब्जबाग दिखाये गये। यह राज तो जनता पार्टी के मैनिफैस्टो पर चलेगा। ये जनता में कह कर के आए हैं कि जनता के एम0 एल0 ए0 बगैर लोभ–लालच के काम करेंगे .....

चौधरी सन्त कंवर : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। ये बिल पर बहस कर रहे हैं या जनता पार्टी पर भाशण दे रहे हैं (व्यवधान)

Mr. Chairman : This is the final stage. You should now confine yourself strictly to the clauses of the Bill. The time for general discussion of the Bill is now over. Therefore, if you have to say anything it should be regarding the clauses of the Bill, and you should confine yourself to the provision of the Bill.

राव दलीप सिंह : हमें तो आपने बोलने का टाईम ही नहीं दिया है। आप इनको इतना टाईम दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं देते ? (व्यवधान) हम भी तो बोल सकते हैं।

Mr. Chairman :That was a different stage. Now it is not that stage. It is the final stage and you have to confine yourself strictly to the clauses of the Bill.

राव दलीप सिंह : मैं कह रहा था कि जमहूरियत को ये बचाने वाले हैं। जनता को वायदे देते हैं और चुन कर आने वाले ये लोग हाउस में बैठ कर वही काम कर रहे हैं जो एमरजैंसी में होते थे। जिन बातों को ये क्रिटिसाईज़ किया करते थे, जिस बंसी लाल को ये क्रिटिसाईज़ किया करते थे, उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। बोर्डों के चेयरमैन बना दिए गए .....

श्री सभापति : बिल की किसी क्लाज में भी कोई चेयरमैन नहीं बना ..... (व्यवधान) This is not relevant. I have told you that it is the final stage when you will have to confine strictly to the provision of the Bill.

राव दलीप सिंह : क्या हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगती। (व्यवधान) अगर आप हमें टाईम ही नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे ? (व्यवधान)

Mr. Chairman : I gave plenty of time to too many Members. It is not the time for the general discussion

राव दलीप सिंह : जो वायदा दिया था क्या उसे ये यहां बैठकर निभा रहे हैं ? बड़े लम्बे भाशण दिया करते थे कि बंसी लाल करप् ान करता है, एम0 एल0 ए0 को खरीदता है, इतना क्रिटिसाईज़ करते थे जिसकी कोई हद नहीं। डा0 मंगल सैन जी बोर्डों के चेयरमैन को क्रिटिसाईज़ किया करते थे कि फलां को चेयरमैन बना दिया और आज खुद बना रहे हैं। डा0 साहब से तो मुझे खास तौर पर ि ाकायत है, मुझे बड़ा अफसोस है कि वे खुद क्रिटिसाईज़ किया करते थे ....

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : मुझे आपसे बड़ी हमदर्दी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोल लें लेकिन इस बिल का गला न घोंटें। (हंसी)

राव दलीप सिंह : आपने फर्टिलाइजर के ऊपर सबसिडी दी है मैं इसका तहेदिल से स्वागत करता हूं लेकिन इस ऐप्रोप्रिए ान बिल के अन्दर, जैसा मूल चन्द जैन जी ने कहा, जनता सरकार जनता को जो वायदे देकर आई थी कि हम सत्ता में आने के बाद क्या क्या करेंगे उन बातों की कोई झलक नहीं आई है। इसमें कोई ऐसा स्टैप नहीं दिखाया जिससे यह पता लगता हो कि यह सरकार अनएम्पलायमैंट दूर करेगी, लेबर की वैलफेयर के काम करेगी, किसानों की भलाई के लिए काम करेगी।

इसमें कोई ऐसा ऐक्सपैंडिचर नहीं दिखाया गया है जिससे यह बात साबित हो सके कि यह सरकार किसानों की हमदर्द है, मजदूरों की हमदर्द है और बेरोजगारों की हमदर्द है। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैं दो मिनट के लिए आपसे माफी चाहूंगा। ये जो वायदे इन्होंने किए थे ये इन्हें पूरे करने चाहिए थे (विघ्न) चेयरमैन साहब, बेरोजगारी का मसला बड़ा अहम मसला है। इसलिए आपकी मारफत मैं यह कहूंगा कि इस तरफ सरकार अव य ध्यान दे। अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमारे यहां लेबर अनरैस्ट नहीं है लेकिन मैं कहता हूं कि यह बहुत है। (विघ्न) मुझे मालूम है कि कुछके फैक्टरीज यमें वर्कर्ज़ को 6 महीने से तन्खवाह नहीं मिली है। सरकार को चाहिए कि पूंजीपतियों से बातचीत करके उन वर्कर्ज़ को तनख्वाह दिलाए। (विघ्न) वह स्टूडैन्टस ने नहीं की थी। उनको पकड़ कर इन्होंने अन्दर कर दिया। इसी तरह ड्राइवर्ज और कंडक्टर्ज को भी उन्होंने अरैस्ट कर लिया। ये तो बड़े जोर से कहते हैं कि इन्होंने जमहूरियत का गला खोल दिया है, अब लोग आवाज लगा सकते हैं लेकिन गरीब मजदूरों को गिरफ्तार करके अन्दर दे दिया है। तो मैं यह कहूंगा कि इनका जम्हूतिरयत की बात करना महज ढकोसला है और वह ज्यादा देर चलने वाला नहीं हैं अगर आपने जम्हूरियत को बहाल किया है तो रैस्टरिस्ट्रिक ान ऐक्ट को लाना चाहिए थाा, मार्किट कमेटी के जिस तरह पहले इलैक ान होते रहे हैं उस तर से इलैक ान करवाने चाहिए थे। (विघ्न) आप अगर उन्हीं लाइन्ज पर

चलेंगे तब तो जम्हूरियत को रैस्टोर करने वाली बात कहीं नजर नहीं आती।

श्री सभापति : क्या फाइनैन्स मिनिस्टर साहब जवाब देना
चाहेंगे ?

चोधरी सतवीर सिंह : जी नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी बात कही ही नहीं जिसका मैं जवाब दूं। पहले ही मैं डिटेल्ड जवाब दे चुका हूं।

Mr. Chairman : Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 5) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा जरनल सेल्ज़ टैक्स (अमैडमैंट) बिल, 1977

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1977.

I also beg to move –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चेयरमैन साहब, विकास स्कीमों के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने हेतु और बाढ़ सहायता तथा बाढ़ सुरक्षा संकर्मों के कुछ खर्च को पूरा करने के लिए, हरियाणा साधारण विक्रय–कर अधिनियम, 1973, की धारा 16 के अधीन अधिभार की दर 1977 के हरियाणा साधारण विक्रय–कर (सं ाोधन) अध्यादे ा संख्या 10 को 31 अगस्त, 1977, को जारी करके 1–9–77 से 2 प्रति ात से बढ़ाकर 15 प्रति ात कर दी गई थी, क्योंकि उस समय हरियाणा विधान सभा का सत्र नहीं हो रहा था। अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस अध्यादे ा को अधिनियम में परिवर्तित कर दिया जाए। अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

Mr. Chairman : Motion moved –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

I have received notice of an amendment to this motion from Rao Dalip Singh. He may please move his amendment.

Rao Dalip Singh : Sir, I beg to move –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill. 1977, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1978.

Mr. Chairman : Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1977, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1978.

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़) : चेयरमैन साहब, यह जो बिल हमारे सामने है इसके जरिए पहले जो सेल्ज टैक्स पर दो परसैन्ट सरचार्ज लगाया जाता था उसे अब बढ़ाकर पन्द्रह परसैन्ट कर दिया है। चेयरमैन साहब, इसके बढ़ने से हमारे हरियाणा की जो इंडस्ट्रीज हैं और ट्रेड है इसको बड़ा भारी धक्का लगेगा। हमारे यमुनानगर, जगाधरी, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद के ट्रेड को यू0 पी0 के ट्रेड से कम्पीट करना पड़ता है। हमारे यहां अगर सेल्ज टैक्स ज्यादा होता है तो हमारी इंडस्ट्रीज यू0 पी0 के ट्रेड और दिल्ली के ट्रेड से कम्पीट नहीं कर पाती और हमारी कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस कंपीटि ान की वजह से यमुनानगर और फरीदाबाद से ि ाफ्ट हो गई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करता हूं कि इसमें इतनी जल्दी क्या है ? इसे इतना हरीडली पास करने की क्या बात है ? ऐसे भी तो इकोनौमी की जा सकती है ? यआप अपने ऐडमिनिस्ट्रे ान के अन्दर किफायत करें। अभी मैंने एक असैम्बली कवै चन किया था। उसके जवाब में बताया गया है कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज के लोन की रिकवरी चार सौ लाख रुपये दो साल से ऊपर के अर्से की ड्यू है लेकिन ये उसे रिकवर नहीं कर पाए। इसी तरह से दो करोड़ रुपये के करीब पांच साल से ड्यू हैं लेकिन ये उसे भी रिकवर नहीं कर

पाए। इन्हें चाहिए कि ये उसे रिकवर करें। (विघ्न) कब करेंगे ? कितनी ही सोसाइटीज में गबन हुआ है। ऐडमिनिस्ट्रे ान को टाईट करके उसको ये चैक कर सकते हैं। गवर्नमैंट में बजाय टैक्स बढ़ाने के औसटैरेटी मैयर्ज़ अडौप्ट करके आप सारे घाटे को पूरा कर सकते हैं। यह तो जनता पार्टी का मैनिफैस्टो थाप कि यह सेल्ज टैक्स को खत्म करेगी। फरीदाबाद और रोहतक में तो डाक्टर मंगल सैन जी ने भाशण भी दिया था लेकिन दूसरे ही दिन दूसरे मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि डाक्टर साहब का स्टेटमैंट कुछ ऐसा वैसा है। इससे तो यह लगता है कि इनकी आपस में अनबन है। इनको चाहिए कि ये मिलकर बातें करें ताकि जनता में इनका कुछ इमेज कायम हो। (विघ्न)

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : आप हमारी इमेज की चिन्ता न करें।

राव दलीप सिंह : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आपकी स्कीम क्या है ? हम आपसे अच्छा ऐडमिनिस्ट्रे ान चाहते हैं। जनता आपसे अच्छा काम चाहती है। आप लोग अपने वायदों पर कायम रहें। लेकिन अफसोस है कि सब्ज वायदे दिखाकर दो महीने में ही वे हवा के अन्दर फैंक दिए। ऐसा करके डाक्टर साहब, आप जनता से वि वासघात करेंगे। इसलिए चेयरमैन साहब, मैं चाहूंगा कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजें और इस पर पब्लिक ओपिनियन लें।

Mr. Chairman : Question is-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1977, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 1978.

The motion was lost.

Mr. Chairman : Question is-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

(At this stage while voice votes were being taken Shri Mool Chan Jain rose on a point of order).

श्री मूल चन्द जेन : आन ए प्वांएट आर्डर, चेयरमैन साहब मैं इस बिल की कंसिड्र ान की स्टेज पर बोलना चाहता हूं। आप सदस्यों की तरफ देखते ही नहीं। मैं कितनी दे से खड़ा हुआ हूं।

Mr. Chairman : Now the motion has been put.

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए) (विघ्न एवं भाोर)

बहिर्गमन

श्री भांकर लाल : चेयरमैन साहब, चूंकि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं वाक–आउट करता हूं। (विघ्न एवं भाोर)

(इस समय श्री भांकर लाल जी सदन से बाहर चले गए)

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैन्डमैंट) बिल, 1977

(पुनरारम्भ)

Mr. Chairman : Question is-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Now the House will take up the Bill clause by clause.

(At this stage several members rose to speak)

Mr. Chairman : Now the motion has been carried.

बहिर्गमन

श्री भाम ोर सिंह : चेयरमैन साहब, क्योंकि मैम्बरों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम वाक–आउट करते हैं।

(इस समय सर्वश्री भाम ोर सिंह, दलीप सिंह, जगज़ीत सिंह पोहलू, सुरेन्द्र सिंह, नारायण सिंह, इन्द्रजीत सिंह और बीरेन्द्र सिंह सयदन से बाहर चले गए)

दि हरियाणा जनरल सैल्ज़ टैक्स (अमैंडमैंट) बिल 1977

(पुनरारम्भ)

Mr. Chairman : Now the House will take up the Bill clause by clause.

श्री मूल चन्द जैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस हाउस की कार्यवाही आप किस तरीके से चलाना चाहते हैं ? आप अपनी नजर कागजों के अन्दर लगा रखें, हाउस के मैम्बरों की तरफ न देखें, मैम्बर बोलना चाहते हैं, उसका क्या इलाज है ?

श्री सभापति : जब आप खड़े होंगे, आपको टाईम जरूर मिलेगा।

श्री मूल चन्द जैन : क्या आप यकीन नहीं करते कि मैं खड़ा हूं ? यह सारा हाउस देख रहा कि मैं खड़ा हूं।

Mr. Chairman : You should have risen at the proper time. Now the motion has been carried. Please resume your seat. If you rise at an improper time, What can I do ?

श्री मूल चन्द जैन : मैं बिल्कुल प्रौपर टाईम पर खड़ा हुआ हूं लेकिन आपने देखा ही नहीं। (विघ्न) अगर किसी बिल की जनरल डिसक ान पर हम भाग नहीं ले सकते तो हमारा फायदा क्या है इस हाउस में आने का ? यह बिल्कुल गलत बात है। आप देखते ही नहीं।

Mr. Chairman : There is to be a third reading and at that stage you will be accommodated.

श्री मूल चन्द जैन : मैं जनरल डिसक ान पर बोलना चाहता था और उस वक्त भी मैं खड़ा हुआ था।

श्री सभापति : वह समय निकल चुका है। If you want an opportunity, you will always be given. But for that you have to rise at the apporiate time.

श्री मूल चन्द जैन : यह आप कैसी गलत बात कर रहे हैं ?

Mr. Chairman : I could not catch you. Now the Bill will be taken up clause by clause.

Chaudhri Rizaq Ram : Before the Chairman takes up the Bill clause by clause, he may kindly hear the Members. The Chairman has adopted totally a novel method of dealing with the Bills. There was a regular motion from Mr. Dalip Singh. Immediately after the conclusion of his speech, you just put that motion which was lost. Thereafter you put the consideration motion of the Bill to the vote of the House. No opportunity was given to the other Members to speak.

Mr. Chairman : Nobody demanded it.

Chaudhri Rizaq Ram : You did not allow anybody to speak. You are by-passing all the rules of business of the House. That is not the way. If there is a whip from the party that nobody should speak, that may be a different matter. But for the Chairman to unsurp all the rights of the members is not proper. I would submit that so many Members stood up in their seats to speak but the Chairman did not cast a glance

towards them and did not allow them to speak. Now it is wrong for the Chairman to say that nobody stood up at the proper time. (Interruptions)

Mr. Chairman : I could not see anybody, otherwise I would have permitted him to speak.

Chaudhri Rizaq Ram : Proper opportunity should be given to the Members to participate in the discussion. This practice is being adopted with regard to other matters also and when the Members are eager to speak, the Chairman that arbitrary method should not be adopted in the House and proceedings in the House should be conducted in a democratic manner and in accordance with the Rules of Procedure of the House. With all apologies I would submit that the Chair should be considerate towards the Members. I can see that the Chair may be in haste to cover up the time but due opportunities should not be denied to the Members. That is not proper. (Interruptions)

Mr. Chairman : Opportunities can be provided whenever there is any. There are still two more opportunities i.e. clause by clause consideration and the third reading of the Bill.

Chaudhary Rizaq Ram : Why not at the stage of consideration of the Bill ?

Mr. Chairman : That stage is over now.

Chaudhari Rizaq Ram : Why the Rules are being by-passed ? That is not proper.

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : चेयरमैन साहब, इस मामले पर मैं सबमि ान करना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र चौधरी रिज़क राम जी ने कुछ भावावे ा में यह बात फरमायी है कि चेयरमैन साहब आर्बिट्रेरिली डील कर रहे हैं और उनका यह नौवल मैथेड है। चेयरमैन के लिए इन भाब्दों का प्रयोग करना बहुत ज्यादा है। यह बात ठीक है कि चेयरमैन साहब आई कैच न कर सके हों। लेकिन मैं आपको पार्टी की ओर से यह आ वासन देना चाहता हूं कि कोई विहप जारी नहीं हुआ है कि इस बिल पर न बोलने दिया जाये। थर्ड स्टेज पर बोल लें। हम गौर से उनकी बात सुनेंगे।

चौधरी रिज़क राम : चेयरमैन साहब, कितना ही टाईम बढ़ा दें लेकिन इस तरह से हाउस की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। जिन बातों के बारे में हम पहले यह ि ाकायत करते रहे हैं कि हाउस की प्रोसिडिंग्ज आर्बिट्रेरी चलती हैं, वही ढंग अब भी अपनाया जाये तो ठीक नहीं। हमें कोई बोलने का भौक नहीं है। अगर पार्टी लीडर यह कहें कि न बोला जाये और बाहर बैठने के लिए कहे तो हम बाहर बैठन के लिए तैयार हैं लेकिन प्रोसिज़र को वायलेट करना, रूल्ज को वायलेट करना, ठीक नहीं है। डाक्टर मंगल सैन जी इस बात की सफाई दें कि ठीक कार्यवाही चल रही है। यह ठीक नहीं। कल तक वे इस बात के लिए लड़ते रहे कि यह तरीका गलत है। आज अगर वे इस बात को डिफैन्ड करें तो मुझे इस बात के लिए भार्म आती है।

डाक्टर मंगल सैन : उनको भार्म नहीं आनी चाहिए। मैंने तो यह कहा है कि कोई आर्बिट्रेरी तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। आपको अगली स्टेज़ पर बोलने का मौका मिल जायेगा। अभी कौन सा बिल पास हो गया है ?

Mr. Chairman : At the third stage of the Bill also everybody can speak.

Chaudhari Rizaq Ram : The rules are being flagrantly violated. (Interruptions)

Mr. Chairman : No rules are being violated. You will get enough time at the next opportunity.

चौधरी भजन लाल : चेयरमैन साहब, यह तो आपको मानना पड़ेगा कि जब मैम्बर बोलने के लिए खड़े हों तो उनको टाईम मिलना चाहिए। (विघ्न)

साथी अयोध्या प्र ाद : यह तरीका बिल्कुल गलत है कि मैम्बरौं को बोलने नहीं दिया जाता है। यह तो ताना ाही का तरीका है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Chairman : There are many hon. Members who still wish to speak. I would like to have the sense of the House if the time of the sitting should be extended.

(Voices : The sitting may be extended by one hour)

Mr. Chairman : Alright. The sitting is extended by one hour slo that every body could partidipation in the discussion.

श्री मूल चन्द जैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चेयरमैन साहब, आपने एक तजवीज़ हाउस के सामने रखी कि हाउस का टाईम ऐक्सटेन्ड किया जाये लेकिन उस तजवीज़ के बारे में आपसे खुद ही निर्णय ले लिया कि टाईम बढ़ा दिया जाये। मैं उस तजवीज़ की मुखलफत करने के लिए खड़ा हुआ था कि हाउस का टाईम ऐक्सटैन्ड किया जाये या नहीं।

Mr. Chairman : Now the sitting has been extended after hearing the Members and taking the sense of the House.

श्री मूल चन्द जैन : यही तो मेरी ि ाकायत है कि आप हाउस के मैम्बरों की बात ही नहीं सुनते हैं। चन्द दोस्तों ने कह दिया कि टाईम एक्सटैन्ड कर दो, आपने सिटिंग एक्सटैन्ड कर दी। कुछ दूसरे ऐसे भी मैम्बर हैं जो यह चाहते हैं कि एक्सटैन्ड नहीं करनी चाहिए। उनकी बात भी तो सुननी चाहिए।

Mr. Chairman : Now it has beeln extended. You come up with an agrument when the thing is over. Please resume your seat now.

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैन्डमैंट) बिल, 1977 (पुनरारम्भ)

Clause 2

Mr. Chairman : Question is-

That clase 2 stand part of the Bill.

Shri Mool Chand Jain : I want to speak on clause 2.

Mr. Chairman : Alright.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : चेयरमैन साहब, इस बिल की क्लाज़ दो के द्वारा हमारी सरकार यह चाहती है कि बिक्री टैक्स कानून के अन्दर जो धारा 16 है, और जिस धारा 13.00 बजे द्वारा इस समय सरकार को यह अधिकार है कि वह बिक्री टैक्स के ऊपर दो परसैंट सरचार्ज वसूल करे, उस सरचार्ज को दो फीसदी से बढ़ा कर 15 फीसदी किया जाए। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो तजवीज है कि इस सरचार्ज को दो परसैंट से बढ़ाकर 15 परसैंट कर दिया जाये। इससे हमारे हरियाणा का बहुत नुक्सान होने वाला है। यह क्यों नुक्सान होने वाला है ? यह इसलिए होने वाला है कि आपको पता ही है कि हमारा हरियाणा चारों तरफ से दूसरी स्टेट्स से घिरा हुआ है। एक तरफ हमारे हरियाणा के पंजाब और दूसरी तरफ राजस्थान है, तीसरी तरफ यू0 पी0 है और दिल्ली तो हरियाणा के तीनों तरफ ही है और बीच में हरियाणा है, ऐसी हालत में जब तक हरियाणा सरकार हमें यह यकीन न दिलाये कि इस सरकार की टैक्से ान की पालिसी जो है और खास तौर पर बिक्री टैक्स की जो पालिसी है, वह पड़ौसी राज्यों की सरकारों में बिक्री टैक्स के जो रेट्स हैं

और हमारी सरकार के जो बिक्री टैक्स के रेट्स हैं, वह एक जैसे हैं कि नहीं। अगर आप एक रेट्स नहीं रहने देंगे तो नतीजा क्या होगा कि हरियाणा का जो बिज़नैस है, जो हरियाणा के लोगों का व्यापार है, वह पड़ौसी राज्यों की मंडियों में चला जायेगा, या पड़ौसी बाजारों में चला जायेगा। इससे हरियाणा के व्यापारियों को भी बहुत अधिक धक्का पहुंचेगा और इसका नतीजा यह होगा कि आज सरकार जो उम्मीद करती है कि इससे विकास के काम में सरकार को रुपया मिलेगा, वह चीज़ बिल्कुल गलत साबित होगी। मैं इस बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने कुछ मंडियों का जिक्र किया। आप देखेंगे कि हरियाणा का कन्ज़यूमर फिर हरियाणा से माल क्यों लेगा वह दिल्ली से क्यों नहीं लेगा, वह पंजाब से क्यों लेगा, वह यू0 पी0 से क्यों नहीं लेगा ? आप देखें यमुनानगर और जगाधरी के नज़दीक यू0 पी0 लगती है। सोनीपत के नजदीक नरेला की, दिल्ली की मण्डी है, डबवाली के साथ पंजाब का इलाका पड़ता है और इधर अम्बाला के साथ राजपुरा जो कि पंजाब में है, पड़ता है। नरवाना के साथ भी पंजाब का इलाका पड़ता है। न पंजाब में 15 प्रति ात सरचार्ज है और न ही यू0 पी में 15 प्रति ात सरचार्ज है और न ही दिल्ली में सरचार्ज 15 प्रति ात है। मैं आपके द्वारा एक मिसाल देकर सरकार को यह समझाना चाहता हूं कि आप किस किस्म के मेयर्ज़ ला रहे हैं, आप किस तरीके से हरियाणा में टैक्स लगाकर विकास के काम करना चाहते हैं। किस तरीके से उन पर टैक्स लगाकर आप उनको नुक्सान पहुंचा रहे

हैं। इसके नतीजे के तौर पर बाकी जनता पर फर्क पड़ेगा। मान लो एक 40,000 रुपये का फोर व्हीलर आता है। उस पर अब 7 प्रति ात बिक्री टैक्स लगता है। ज़रा मेरी कोई भाई मदद करे कि उस पर कितना सेल्ज़ टैक्स लगा ..... (व्यवधान) .....

Mr. Chairman : Mr. Pohloo is the most appropriate person to advise you in this matter.

श्री मूल चन्द जैन : 2800 रुपये उसके ऊपर बिक्री टैक्स लगेगा। अब उस 2800 रुपये के बिक्री टैक्स पर 2 प्रति ात की बजाय 15 प्रति ात सरचार्ज होगा जो 56 की बजाए चार सौ बीस रुपया तब आ जायेगा।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : 100 रुपये के ऊपर सिर्फ 91 पैसे का ही फर्क पड़ता है।

Mr. Chairman : No bickering on accounts please. (Interruptions)

श्री मूल चन्द जैन : तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर तो हमारे मंत्री साहब उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह से एक वकील अदालत में जवाब देता है तब तो बात ठीक है लेकिन इन्होंने तो यह समझ रखा है कि यह अदालत तो है नहीं कि जवाब जरूर ही देना पड़ेगा। तो मैं यह चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय इस सब बातों का जवाब दें। अगर वह दलीलें उठ रही हैं, उसी तरह से वे भी दलीलों से जवाब दें। मैंने एक मिसाल देकर दलील दी है। आप फोर व्हीलर ले लीजिये या रैफ्रीजरेटर ही ले

लीजिये। जिनको यह लेने होंगे वे हमारी स्टेट से खरीदेगा ही क्यों जबकि पड़ौसी राज्यों में उसे 100, 200, 500 या 1000 रुपया कम पर मिल सकेगा। मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं कि एक कन्ज़यूमर ऐसा सामान सोनीपत से क्यों खरीदेगा ? वह पंजाब की पड़ोसी मंडियों से खरीदेगा। वह जगाधरी या यमुनानगर से न खरीद कर वह सहारनपुर से खरीदेगा। मैं आपकी मारफत सरकार को यह कहना चाहता हूं कि मुझे तकलीफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम सब के सब यह चाहते हैं कि ब्लैक–मार्किट खत्म हो। काला बाजार खत्म हो, आज जो यह सरचार्ज 2 प्रति ात से बढ़ाकर 15 प्रति ात किया जा रहा है इससे आप कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि दिल्ली एक बहुत भारी सैंटर है। दिल्ली से उचलती माल आज भी करोड़ों रुपये का हरियाणा में आ रहा है। वह उचलती माल क्या होता है ? दिल्ली से हरियाणा में माल किसी न किसी तरह से आ जाता है उसमें बिक्री कर के महकमे के आदमी भी मिले होते हैं। न उस माल का किताबों में इन्दराज़ होता है और न उसको कहीं दूसरी जगह अकाउन्ट फार किया जाता है। उसको सीधा बेच दिया जाता है। उसके ऊपर सेल्ज़ टैक्स भी बच जाता है और इन्कम टैक्स भी बच जाता है। आज भी इस किस्म की ब्लैक मार्किटिंग हो रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि दर्जा दोअम यानी दो नम्बर का रुपया बे ुमार तादाद में हो रहा है।

श्री लक्ष्मन सिंह : तीन नम्बर का भी रुपया है।

श्री मूल चन्द जैन : तीन नम्बर के रुपये के बारे में तो आपको भाायद ज्यादा पता होगा। प्र न यह है कि इस सरचार्ज को बढ़ाने का नतीजा क्या होगा ? सरचार्ज 15 प्रति ात तक बढ़ाने का नतीजा यह होगा कि जो उचलती माल हरियाणा में आता है, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी। जो औनैस्ट व्यापारी है वह औनैस्ट ही रहना चाहता है। वह व्यापारी औनैस्ट रहने के लिए आज इस चंडीगढ़ में हज़ारों की तादाद में यहां पर डैपुटे ान लेकर आये हैं। वे सरकार को मिलना चाहते हैं। वे आज यहां आये हुए हैं। तो सरकार उनको औनैस्ट रहने देने के लिए वे जो कहते हैं, वे जो आल्टरनेटिव तरीके बताते हैं, उनको अपनायें। ऐसी चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिये जिससे कि काला बाजारी बढ़े। हमारे हरियाणा प्रान्त में वही सैल्ज़ टैक्स के रेट्स रहने चाहिये जो कि दूसरी स्टैट्स में हैं। आज आप उस वायदे को भूल गये हैं जो जनता पार्टी ने अपने चुनाव मैनीफैस्टों में किये थे। उसने अपने चुनाव मैनीफैस्टो में यह साफ लिखा है, आप पढ़कर देखें कि हम बिक्री कर को खत्म करेंगे। ..... बिक्री टैक्स को खत्म करने के लिए क्यों कहा था ? जनता पार्टी के नेताओं को अपनी–अपनी स्टेट में यह होता है। बिक्री टैक्स को खत्म करेंगे तो काला धन खत्म होगा। आप किसी बात को सोचते नहीं हैं। आपने कह दिया कि रुपयाय चाहिए और कहा कि दो प्रति ात से पन्द्रह प्रति ात कर दो लेकिन आपने यह नहीं सोचा

कि इसका हमारी इकौनोमी पर क्या असर पड़ेगा। आप किसी को बताएं नहीं कि हम पन्द्रह प्रति ात करने जा रहे हैं, पार्टी को कांफीडैंस में न लें तो कैसे काम चलेगा। इसका स्टेट की इकौनोमी पर घातक असर पड़ेगा। बिजनैस कम्युनिटी को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। सरकार को इस मामले में फिर सोचना चाहिए। मेरा सरकारे से यह कहना है कि इस बिल को यहां पर स्थगित करे, इसको सस्पेंड करे। इससे काला बाजारी बढ़ेगी। सोनीपत, डबवाली, बोर्डर की जितनी मंडियां हैं तथा चारों तरफ का जितना व्यपार है उसको बड़ा भारी नुक्सान होगा। अगर हमारे वित्त मन्त्री अपनी नाक से ज्यादा दूर नहीं देखते और हरियाणा का व्यापारी ज्यादा दूर देख सकता है तो हरियाणायय के व्यापारी की बात सुनकर आप इसको दो प्रति ात से पन्द्र प्रति ात न करें। यह पन्द्र प्रति ात करना बिल्कुल गलत बात है। इस बिल को आगे स्टडी करना चाहिए और अच्छी तरह विचार करने के बाद फिर हाउस में लाना चाहिए। जब तक इस पर दुबारा विचार हो उस वक्त तक इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

चौधरी संत कंवर (हसनगढ़) : चेयरमैन साहब, जेन साहब ने एक बात कही कि यह सरकार बिजनैस कम्युनिटी के साथ ज्यादती कर रही है। भाायद जैन साहब, यह बात भूल गए कि हरियाणा में जो बाढ़ आई है इससे कम से कम मेरे इलाके में पचास–साठ गांव ऐसे हैं जहां के लोगों के मवे ाी बह गए, मकान गिर गए, अनाज का बहुत नुक्सान हुआ है। लोगों को दस–दस

मील दूर झोंपड़ियों में ले जाया जा रहा है। लोगों का अनाज पानी में बह गया। अगर उन लोगों की सहायता नहीं की जाती तो वे लोग क्र ा होते हैं। व्यापारियों पर अगर थोड़ा टैक्स लगा दिया तो इस टैक्स से वे क्र ा नहीं होते। चेयरमैन साहब, मैं इस बिल के साथ सहमत हूं और मैं ही नहीं बल्कि सारा सदन इससे सहमत है। यह टैक्स में जो बढ़ौतरी की गई है यह समझदारी का कदम है और जनता को बचाने के लिए यह कदम लिया गया है। जैन साहब का यह कहना कि व्यापारियोयं को क्र ा किया जा रहा है यह ठीक नहीं है। मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करता हूं।

चौधरी रिज़क राम (राई) : चेयरमैन साहब, इस बिल की ब्लाज दो पर बहस जारी है। जहां तक इस टैक्स का सम्बन्ध है, मैं न तो इस बात पर जाना चाहता हूं कि फ्लड के कारण जो नुक्सान हुआ है उसको पूरा करने के लिए यह टैक्स लगाया जा रहा है। अगर कोई सदस्य यह दलील रखे कि जो यह टैक्स लगाया जा रहा है इससे सारा नुक्सान पूरा हो जाएगा, सारी रिहैबलीटै ान हो जाएगी। यह ठीक बात नहीं है। मैं एक बात संजीदगी से नहीं बल्कि मजाकिया तौर पर कहना चाहता हूं कि फ्लड दे ा में भी आए और हरियाणा प्रान्त में भी आए। यहां कुछ हमने भी मांग की थी और मुख्य मंत्री ने अपने पद को सम्भालने के बाद यह वायदा जनता में दिया था कि जनता सरकार जनता को पानी और स्वच्छ प्र ाासन देगी। पानी मांगने वाली

बात जो थी वह कबूल हुई। यह देखने में आया और उससे काफी नुक्सान हुआ लेकिन यह कहना कि हरियाणा में आए साल फ्लड आते हैं और उनका प्रबन्ध करना हमारी जिम्मेदारी है। आगे और भी केलेमीटीज आ सकती है। मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी सरकार बगैर टैक्स के नहीं चल सकती। उसकी आमदनी का जरिया टैक्स है। लेकिन सिद्धान्त रूप से चेयरमैन साहब, एक बात देखनी पड़ती है कि टैक्स खास तौर से सेल्ज टैक्स लगाया जाता है तो केवल सेल्ज टैक्स ही नहीं कोई भी टैक्स हो उससे कीमतों पर फर्क पड़ता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो दो प्रति ात से पन्द्रह प्रति ात की बढ़ौतरी की गई है वह जितनी दिखाई दे रही है उतनी बढ़ौतरी नहीं है। लेकिन इतनी बढ़ौतरी भी हानिकारक हो सकती है। जब भाराब जैसी चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ता और अगर आम आदमी की जरूरत की चीजों पर टैक्स लगाया जाता है तो यह लाजमी तौर पर बात है, यह नैचुरल प्रोसैस है कि अगर एक चीज पर टैक्स लगाया जाता है तो दूसरी चीजों की कीमत बढ़ जाती है। आज सबसे ज्यादा महंगाई का मामला है। अगर इस टैक्स के लगाने से महंगाई को बढ़ावा मिलता है तो यह नहीं लगाना चाहिए। सरकार को भाराब जैसी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। महंगाई हमारे सामने भयंकर रूप में है। इसको हमें कम करना है। यह बात बहुत लोगों को पता है कि अगर हैवी रेट आफ टैक्स है तो उसमें इवेजन ज्यादा होगा और यही कारण था कि पिछली सरकार ने अपने बजट में टैक्स रेट घटाया था और हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी

बजट में टैक्स का रेट घटाया है। उनकी दलील है कि जितना ज्यादा हैवी टैक्स होगा उतना ही ज्यादा इवेजन होगा। उस इवेजन को रोकने के लिए टैक्स का दर कम रखना पड़ेगा। अगर हमारी सरकार रेट आफ टैक्स को बढ़ाती है तो इवेजन ज्यादा होगा मैं ज्यादा टाईम नहीं लूंगा। एक बात कहकर खत्म कर दूंगा। सब को पता है कि दिल्ली की आबादी हरियाणा से कम है और दिल्ली में जो रेट आफ टैक्स है वह भी हरियाणा से कम है, और हर चीज में कम है। उन्होंने टैक्स की दर कम करके आज दिल्ली को कामर्शियल लाइन्ज का सेन्टर बना दिया है। आज दिल्ली सारे दे ा की तिजारत का सेन्टर हो गया है महज इसलिए कि वहां टैक्स कम हैं और पड़ौसी राज्योयं में टैक्स की भारह ज्यादा हैं। इसलिए सारी तिजारत दिल्ली में हो गई हैं। आपको याद होगा कि जब अनाज पर कोई पाबन्दी नहीं थी तो डबवाली का अनाज दिल्ली तक पहुंचता था। चार साढ़े चार रुपए क्विंटल का किराया देना पड़ता है और दिल्ली में जहां सेल्ज टैक्स बहुत कम है डबवाली का अनाज दिल्ली में जाकर बिकता हैं इसी तरह से सारे रोहतक का अनाज भी दिल्ली में जाकर बिकता है। इसी तरह से सारे रोहतक का अनाज भी दिल्ली जाकर बिकता है। इसी सम्बन्ध में कई बार मीटिंग्ज और कांफ्रेंसिज़ भी हुई कि आस पास की स्टेंट्स के सैल्ज़ टैक्स कीर तरह टैक्स की भारह एक जैसी होनी चाहिये पर उन मीटिंगौं का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब व्यापारियों को बड़ा फर्क पड़ेगा। एक तरफ तो आप अन–एम्पलायमेन्ट को दूर करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ

मुझे डर है कि व्यापारियोयं का व्यापार ठप्प होने की वजह से कहीं और अन–एम्पलायमैंट न बढ़ जाए। चेयरमैन साहब, मैं एक बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जहां सेल्ज टैक्स की दर ज्यादा होगी वहां इसका इवेजन भी ज्यादा होगा जिसकी मिसाल हम दिल्ली की ले सकते हैं। दिल्ली में सेल्ज़ टैक्स की दर कम है। और उसकी आमदन हमारे हरियाणा से ज्यादा है। इसकी वजह यही है कि हरियाणा में सेल्ज टैक्स की दर ज्यादा है और यहां पर इस टैक्स की इवेजन होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब भी सरकार कोई इस तरह का टैक्स लगाये तो उसे सरे पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिये जिससे न तो सरकार को नुकसान हो और न लोगों को नुक्सान हो। मुझे इस बारे में मिसाल याद आ गई है कि एक आदमी ने एक खान को अपने यहां नौकर रखा और उसके लिये यह भार्त रखी कि उसको हर काम में जी हजूर करना होगा। एक दफा वह लकड़ियां काटने गया। जब वह अपने हिसाब से लकड़ियों को उठाने लगा और उसके ऊपर और लकड़िया लाद दी गई तो उसने कहा कि भाई इतना बोझा क्यों लाद रहे हो, जी–हजूर तो मैंने कहना ही है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमने जी–हजूर तो कहना ही है लेकिन इतना टैक्स क्यों लाद रहे हो। इन भाब्दों के साथ मैं सरकार से फिर निवेदन करता हूं कि इस बिल की क्लाज़ दो पर वह फिर विचार कर ले।

श्री सभापति : मैं सभी आनरेबल मैम्बर साहिबान को रिकवैस्ट करूंगा कि जो भी मैम्बर बोलना चाहें, वे समय का ध्यान रखते हुए बोलें क्योंकि बहुत से मैम्बर अभी बोलने वाले बाकी हैं।

श्री लछमन सिंह : चेयरमैन साहब, पहले उन मैम्बरों को समय दिया जाना चाहिये जिनको इस बारे में अच्छी जानकारी है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू (पाई) : चेयरमैन साहब, यह जो बिल यहां पर लाया गया है, मैं इसकी पुरज़ोर मुखालिफित करता हूं क्योंकि पहले ही हरियाणा के अन्दर बहुत महंगाई है और यह जो सेल्ज़ टैक्स बढ़ाया जा रहा है यह दुकानदार पर नहीं पड़ता है बल्कि सीधा ही खरीददार पर पड़ता है। जिस वक्त कोई भी आदमी कोई चीज़ खरीदता है तो उसकी कीमत के साथ–साथ सेल्ज़ टैक्सी भी लिखा जाता है और सारे का सारा पैसा कन्ज्यूमर से ही लिया जाता है। यह जो सेल्ज़ टैक्स है यह इंडायरेक्टली परचेज़र के ऊपर ही है जो कि नहीं लगना चाहिये इससे हरियाणा के अन्दर महंगाई बढ़ेगी।

दूसरी बात, चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब किसान गन्ना मिल में ले जाता है तो उस वक्त भूगर मिलें जो सेल्ज़ टैक्स होता है वह किसानों के पैसे से ही काटते हैं जबकि यह टैक्स उनको खुद पे करना चाहिये। इस तरह से यह सारा भार गरीब किसानों पर ही पड़ता है। मेरी सरकार से दरखास्त है कि सरकार इस ओर ध्यान दे। जैसे कि हरियाणा में

है कि जो खरीददार है वह व्यापारी को टैंक्स पे करता है लेकिन भाूबर मिलों में इसके बिल्कुल उल्ट है कि किसान जब अपना गन्ना बेचता है तो खुद सेल्ज़ टैक्स उसकी कीमत में से काटा जात है ऐसा नहीं होना चाहिये। इसके लिये कम से कम एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिये। यह मेरा सकरार को सुझाव है।

चेयरमैन साहब, जनता पार्टी ने अपने मैनीफैस्टो में यह लिखा है कि हम बिक्री टैक्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे लेकिन अब सरकार अपने वायदों से मुकर रही है। कल भी डाक्टर मंगल सैन जी ने अपनी स्टेटमैंट में कहा था कि हम सेल्ज़ टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। डाक्टर मंगलसैन जी मेरे बड़े परम मित्र हैं। हम इकट्ठे जेल में रहे हैं। मुझे उनसे पूर्ण आ ाा है कि इस इस सेल्ज़ टैकस को नहीं लगने देंगे। अगर सरकार इसको बढ़ाती है तो उनके अपने मैनीफैस्टो के अनुसार यह गलत बात होगी क्योंकि उन्होंने अनने मैनीफैस्टों के अन्दर यह कहा है कि हम बिक्री टैक्स इस हरियाणा के अन्दर बिल्कुल खत्म कर देंगे।

चेयरमैन साहब, मेरे कुछ भाईयों ने यहां कहा कि यह जो बिक्री कर लगाया जा रहा है इससे जमा रा ि ा को फ्लड रिलीफ के कामों में प्रयोग किया जाएगा। मैं पहले भी यह कह चुका हूं कि हरियाणा के अन्दर पहले ही बहुत महंगाई है लोग बुरी तरह से पिसे पड़े हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय भी यहां बैठे हैं। मैं अपनी सरकार से यह रिकवैस्ट करूंगा कि अगर उन्हें फ्लड रिलीफ के लिये पैसा चाहिये तो इसके लिए हम उनके साथ

हैं, हम डोने ान इकट्ठा करके देंगे, पैसा दिलवाएंगे, हर सेवा के लिये तैयार हैं लेकिन इस गलत तरीके से पैसा न इकट्ठा करें जिससे लोगों को तकलीफ हो। फ्लड रिलीफ के लिये और बहुत से तरीके पैसा इकट्ठा करने के हैं। इन भाब्दों के साथ मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि वे अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करें ताकि लोगों को इससे राहत मिल सके। इसके साथ साथ मैं चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि अपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री मूल चन्द मंगला (पलवल) : चेयरमैन साहब, यहां पर सेल्ज़ टैक्स बढ़ाने के बारे में जो चर्चा चल रही है उसके बारे में मेरे कई भाईयों ने यह समझा है कि यह सेल्ज़ टैक्स का सारा बोझा दुकानदार पर पडेत्रगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि दुकानदार पर उसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा। उसका बोझा तो सारा का सारा खरीददार पर ही पड़ेगा क्योंकि दुकानदार जब कोई चीज बेचता है तो उसकी रसीद काटता है और चीज़ की कीमत के साथ सेल्ज़ टैक्स जमा कर देता है जिससे वह सारा बोझा खरीददार पर ही पड़ जाता है। इसलिये सरकार को कोई तजवीज़ सोचनी चाहिये कि जिससे बोझा खरीददार पर न पड़े। लोग तो आगे ही महंगाई के कारण पिसे जा रहे हैं। लोगों को इससे बड़ी मु कल पड़ेगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी नेबर स्टेट में हर जगह पर 5 परसेन्ट टैक्स है जबकि हमारे हरियाणा के अन्दर पहले ही इससे ज्यादा टैक्स है और अब इसे

और बढ़ाया जा रहा है जों कि कुल मिलाकर लगभग 14 परसेन्ट के करीब जा पड़ता है। जो इतना भारी टैक्स है वह खरीददार की बरदा त से बाहर है। इससे स्टेट को कोई खास फायदा नहीं होगा और न ही व्यापारी तथा कंज्यूमर को ही कोई फायदा होगा। इससे आगे चेयरमैन साहब, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो बदनाम व्यापारी हैं वह यह कोि ा ा करेंगे कि वे बगैर बिल के माल बेचें और ऐसा होने से पूरे के पूरे टैक्स की चोरी होगी जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं होगा। मैंने देखा है कि साथ की स्टेट्स में टैक्स कम लगते हैं और उनका माल ज्यादा बिकता है और उसके मुकाबले में हमारी स्टेट में टैंक्स ज्यादा है इसलिये यहां पर माल कम बिकेगा जिसके कारण आमदन कम होगी। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि इस टैक्स को न लगाया जाए तो अच्छा होगा। दूसरी बात ययह है कि इससे व्यापारी वर्ग को परे ाानी होती है और विभाग के अफसरौं को भी परे ाानी होती है। लेकिन एक बात है कि इससे सरकारी आदमियों की खिदमत बहुत होती है। एक जो चपरासी है जब वह किसी दुकान पर जाता है तो उसकी भी बहुत खिदमत होती है। इसकी वजह यह है कि और स्टेटो में तो यह टैक्स तकरीबन 5 प्रति ात है और यहां पर 14 प्रति ात होने लग रहा है जिस कारण बेईमानी भी होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस टैक्स की दर एक जैसी ही होनी चाहिये इससे जनता को भी फायदा होगा ओर सरकार को भी फायदा होगा। जैसे इस बिल के जरिये टैक्स बढ़ाने की कोि ा ा की जा रही है इससे हरियाणा

की आमदनी में गिरावट आएगी। मैं व्यापारी मंडल का प्रैजीडैंट हूं और उसके नाते मुझे इस बात का अनुभव है। अगर आमदनी घटेगी तो व्यापारियों को भी तकलीफ होगी और स्टेट को भी तकलीफ होगी। इसलिये चेयरमैन साहब मैं प्रार्थना करूंगा कि इस टैक्स में बढ़ौतरी न की जाए। इसके साथ साथ जो हमारी पार्टी ने जनता के साथ वायदे किये हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। अगर जनता को यह धोखा हो गया कि सरकार पहले ही ऐसा काम कर रही है तो आगे वह क्या सोचेगी ? हमारा जो बाढ़ की वजह से नुक्सान हुआ है उसको पूरा करने के लिये मैं व्यापारी वर्ग की तरफ से कहता हूं कि हमारी पार्टी व्यापारियों के पास जाए तथा और जगह जाए। हम उस नुकसान को पूरा करेंगे। लेकिन इस तरह से अगर कोई टैक्स एक साले के लिये या दो साल के लिये लगाया जाता है तो यह गलत है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल की ब्लाज़ दो को अगर पास न किया जाए तो अच्छा है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी हरि चन्द हुडा (किलोई) : चेयरमैन साहब, व्यापारियों को टैक्स की ि ाकायत है, ठीक है, किसानों को भाव की ि ाकायत है, ठीक है, मजदूरों को कीमतों की ि ाकायत है ठीक है। इस गवर्नमैंट को आए हुए अढ़ाई तीन महीने हुए हैं और पिछली जाने वाली गवर्नमैंट ने यहां का वातावरण इतना खराब कर दिया था जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि इसको कैसे ठीक

करें। जहां तक किसान का ताल्लुक है मैं चाहता हूं कि किसान को भी सल्ज़ टैक्स में भाामिल कर लिया जाये क्योंकि अगर उसकी आर्थिक पोजी ान कमज़ोर होती है तो उसे साहूकार (बैंक) खा जाते हैं और अगर उसकी पैदावार बढ़ जाती है तो उसको भाव खा जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इनकी पैदावार को भी दूसरी बाजार की चीजों के साथ मिला दिया जाए। इस तरह अगर बाजार की आम चीज़ें गिरती हैं तो किसान की भी गिर जाएंगी और वो बढ़ती हैं तो किसान की भी बढ़ जाएंगी। इस तरह से किसान सेल्ज टैक्स में भाामिल हो जाएगा। जहां तक मजदूरों को मजदूरी के बारे में ि ाकायत है उनके बारे में यह सोचता हूं कि जितने भी कोटे और परमिट हैं ये उनको बांट दिये जाएं। जैसे पैट्रोल पम्प है अगर हम इसे किसी हरिजन, छोटे किसान या छोटे दुकानदार को दे दें तो उससे दो मसले हल होंगे। एक तो उनसे सेल्ज टैक्स भी ले सकेंगे और कास्टीज़म भी खत्म होगी क्योंकि हरिजन पैट्रोल पम्प पर काम करेगा उसे कोई बाबू जी कहेगा, कोई लाला जी कहेगा और कोई चौधरी जी कहेगा, तो इससे कास्टीज़म खत्म हो जाती है और सेल्ज़ टैक्स के ऐतराज का सवाल खत्म हो जाता है क्योंकि इस तरह सभी पर सेल्ज टैक्स लग जाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो तीन प्वायंट मैंने रखे हैं अगर इन पर गौर किया जाए तो तीन साल के अन्दर हरियाणा में सेल्ज़ टैक्स की ि ाकायत नहीं रहेगी, भाव की ि ाकायत नहीं रहेगी और कास्टीज़म भी एक हद तक खत्म हो जाएगा क्योंकि इन सबकी आर्थि द ाा बराबर हो जाएगी।

साथी अयोध्या प्र ाद (नारनौल) : चेयरमैन साहब, जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान सेल्ज़ टैक्स को हटाने की बात कही थी लेकिन आज वह 15 प्रति ात किया जा रहा है चूंकि यह जनता पार्टी के घोशणा पत्र के विरूद्ध है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : चेयरमैन साहब, मैं सदन के सारे सदस्यों को इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री चौधरी देवी लाल जी की सरकार मन से कोई टैक्स लगा कर खु ा नहीं है लेकिन हमें हालात ऐसे मिले। हमें लोगों की भलाई और खु ाहाली के लिये मजबूर होकर यह छोटे टैक्स लगाने पड़े हैं। मैं, जो हमारी वित्तीय स्थिति है उसके बारे में पहले भी कई बार सदन में बता चुका हूं और आज फिर सारे सदन को अच्छी तरह से बताता हूं। 1977–78 के बजट के अन्दर 17.10 करोड रुपये का घाटा दिखागया गया था और बजट से पहले 5.58 करोड़ रुपये का घाटा था लेकिन ए0 जी0 की रिपोर्ट आने के बाद टोटल घाटा 29.20 करोड़ रुपये का है। जो पिछली भ्रश्ट गवर्नमैंट गई है जब उसने देखा कि उसे अब सत्ता नहीं मिल सकती है तो वह जाती–जाती कई टैक्स माफ कर गई। उससे भी सरकार को 5.60 करोड़ रुपये का घाटा पड़ा। इसके अलावा पहले गेहूं के ऊपर सरकार को बोनस मिला करता था लेकिन इस बार गवर्नमैंट आफ इंडिया ने वह बोनस नहीं दिया। इसकी वजह से भी तीन करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस तरह

यह घाटा हरियाणा में 40 करोड़ के करीब है और जिस दिन जनता गवर्नमैंट आई थी उस दिन हमें घाटे का बजट मिला था। इमने मुख्य मन्त्री जी के निर्दे ाों पर चल कर इस घाटे को पूरा करने के लिए पूरी भाक्ति से प्रयत्न किया, सरकार ने कंस्ट्रक्टिव मैयर अडौप्ट किए और यह टैक्स बढ़ाया है जिस पर डिस्क ान चल रही है। इस तरह से इस घाटे के बजट को पूरा करने के लिए हमने निर्णय लिया। जो भ्रश्ट कांग्रेसी साथियों से सेल्ज़ टैक्स की या दूसरी किस्म की रिकवरी पैंडिंग थी उसको इकट्ठा किया। आज हरियाणा में इतने टैक्स हैं लेकिन फिर भी हरियाणा ओवर ड्राफ्ट नहीं है। पंजाब स्टेट ओवर ड्राफ्ट से भी बढ़ी है। इसके साथ ही साथ सदन को इस बात की खु ाी होगी कि घाटे को पूरा करने के लिए जो हमने ऐफर्ट्स की हैं, इन ऐफर्ट्स पर एम0 एमज़0 की कांन्फ्रेंस में सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने कहा कि हम आपकी ऐफर्ट्स से खु ा हैं और हरियाणा गवर्नमैंट अपनी ऐनुवल प्लान के साथ आगे बढ़े। दूसरी स्टेट्स की ऐनुवल प्लान पर कट लगाया गया है क्योंकि उन्होंने घाटे को पूरा करने के लिए ऐफर्ट्स नहीं कीं। इसके अलावा, आप जातने हैं कि फ्लड का कितना प्रकोप रहा। सारे सदस्य जानते हैं कि फ्लड से पीडित्रत लोगों को सहायता मिलनी चाहिए। इसीलिए यह टैक्स लगाया है और भाायद इनको इस टैक्स से डर लगता है क्योंकि जिन्होंने किसाने को रोते हुए नहीं देखा, बच्चों को तबाह होते हुए नहीं देखा, अनाज की तबाही नहीं देखी, किसान के परिवार को दरखतों और छत्तों पर बैठे हुए नहीं देखा। वे कहते हैं कि

व्यापारियों को नुक्सान होगा। हमें व्यापारियों को तंग करने में खु ाी नहीं थी लेकिन पुरानी सरकार प्रदे ा में ऐसी हालत छोड़ गई थी जिसको सम्भालने के लिये जनता पार्टी की सरकार को मजबूर होकर टैक्स लगाने पड़े। श्री मूल चन्द जैन ने यह कहा कि इस टैक्स से ट्रेड के अन्दर नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि इससे कोई नुक्सान नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जरूरियात की चीजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। मेरे पास सेल्ज़ एक्ट है, इसके अन्दर दो तरह की आइटमौं पर टैक्स लगे हैं। भाडयुल्ड (बी) के अन्दर वे आर्टिकल्ज़ आती हैं जो आम आदमी के रोजाना इस्तेमाल होने की चीजें हैं, इन पर टैक्स नहीं लगता, जैसे वैजिटेबल के ऊपर नहीं पड़ता। बहुत कम चीजें हैं जिन पर पड़ता है।

List of tax free goods at Schedule 'B' includes-

1.	Vegetables, but not including red chillies, dry or otherwise	Except when sold in tins, bottles or cartons.
2.	Shakkar Kandi	
3.	Sugar Cane	
4.	Milk	Except condensed & dried milk.
5.	Meat, Fish and eggs	Except when sold in tins, bottles or

		cartoons.
6.	Fresh fruits	
7.	Common salt	Except when sold in sealed containers.
8.	Flower	
9.	Pan	
10.	Books	
11.	Periodicals	
12.	Exercise and drawing books	
13.	Writinhg slates and slate pencils	
14.	Writing Chalks and crayons	
15.	Foot-rules of the type usually used in schools	
16.	All varities of cotton, woollen or silken textiles incdluding rayon, artificial silk or nylon whether manufactured by handloom or powerloom or otherwise but not including silk fabrics, carpets, druggets, woollen durries and cotton floor durries.	On which additional excise duty in lieu of sales tax is levied.

17.	All varieties of textiles covered by item 14 (now item 16) of which kntting and embroidery work has been done.	

There are several other such commonly used articles given in this schedule.

इनके अलावा जो डिक्लेयर्ड चीजें हैं, जो सैन्ट्रल गवर्नमैंट के सैक ान 14 के तहत हैं such as coal, cotton, cotton fabrics, cotton yarn, Hides and skins, Iron & steel, Jute, Oil-seeds, Rayon or artificial silk fabrics, sugar, tobacco, woollen fabrics, Cereals and pulses, crude oil इन पर टैक्स की छूट है और इन पर टैक्स नहीं लगता टैक्स लगजूरियस चीजों पर लगता है like refrigerators, air-conditioners. आम आदमी, गरीब आदमी जो हरियाणा में बसते हैं उन 99 परसैंट आदमियों पर इसका असर नहीं पड़ता। सरकार को इस टैक्स से 2 करोड़ का फायदा होता है। यह कहना कि ट्रेड चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि सौ रुपये की चीज़ के ऊपर 7 रुपये टैक्स है और 2 रुपए सरचार्ज है। यानि 100 रुपये की चीज की कीमत 107.14 पैसे बैठती थी और हमारे हिसाब से 108.05 पैसे बैठती है। सिर्फ 91 पैसे बढ़े हैं। जिस प्रदे ा में फ्लड का मुकाबला करना हो, जमींदारों को फर्टिलाइजर देनी हो, बिली का इन्तजाम करना हो, सड़कें बनानी हों, पीने का पानी देना हो, स्कूलों को अप–ग्रेड करना हो, मैं इनसे पूछता हूं कि हमारे पास इन कामों के लिये कहां से पैसा आएगा ? जनता पार्टी ने जो

वायदे किये थे उनको बिना पैसे से कैसे पूरा कर सकेंगे। और हरियाणा को खु ाहाल कैसे कर सकेंगे। अगर टैक्स न लगाते तो और क्या करते ? यह टैक्स तो नौमिनल है, इसका रोजमर्रा की चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो भ्रम में डालने वाली बात है कि महंगाई हो जाएगी या इससे ट्रैड खत्म हो जाएगा। एक बात मैं और कहूंगा, ब्लैक मार्किटिंग की। मैं सरकार की तरफ से सदन को वि वास दिलाता हूं कि ब्लैक मार्किटिंग नहीं होगी। ब्लैक मार्किटिंग उस समय होती थी जब ब्लैक मार्किटिंग करवाई जाती थी, जब कि सरकार खुद भ्रश्ट थी और ब्लैक मार्किटिंग करके खुद अपना पेट भरती थी। अगर किसी माननीय सदस्यगण के पास ऐसी कोई मिसाल हो कि कोई आदमी ब्लैक मार्किट करता है तो मैं आपको वि वास दिलाता हूं कि हम उसको बख ोंगे नहीं हमारे नोटिस में ला दें। जो टैक्स इवेज़न हुआ करता था इसका सरकार पूरा इन्तजाम करेगी और हम कोि ा ा करेंगे कि हमारे टैक्स का एक पैसा भी कोई इवेजन न कर सके। हमारी सरकार इस चीज़ को रोकेगी। हरियाणा सरकार ब्लैक मार्किटिंग और भ्रश्टाचार नहीं करेगी। चौधरी रिज़क राम जी ने कहा कि दिल्ली के अन्दर टैक्स चले जाएंगे क्योंकि दिल्ली का टैक्स कम है।

चौधरी पीर चन्द : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि आम इस्तेमाल करने वाली चीज़ों पर

इस टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खाद पर यह सरचार्ज होगा या नहीं ?

Mr. Chairman : This is no point of order. The Hon. Minister may please continue with his speech.

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : दिल्ली वाले भी कोि ा ा कर रहे हैं, उनकी भी इन्टैन ान है कि सेलज़ टैक्स बढ़ाया जाए, पंजाब वाले भी चाहते हैं कि सेल्ज़ टैक्स बढ़ाया जाए। हर सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि टैक्स बढ़यााया जाए। इसके साथ ही साथ कुछ भाईयों ने कहा कि जनता पार्टी के मैनिफैस्टों में यह लिखा था, ठीक लिखा था लेकिन जिस स्टेट को 60 प्रति ात रुपया टैक्सौं से आता हो उस सरकार के लिए सेल्ज़ गवर्नमैंट इसकी पूर्ति करे, हमें ग्रांट दे दे तो जो टैक्स वाली बात है, जिस रे ाो से यह बढ़ रहा है इस पर हरियाणा सरकार सोचगी।

Mr. Chairman **:** Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

That motion was carrid.

Clause 3

Mr. Chairman : Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Chairman : Question is-

That claus 1 stand part of the Bill.

That motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Chairman : Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Chairman :Quesion is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to move-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be passed.

Mr. Chairman : Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be passed.

मास्टर ि ाव प्र ाद (अम्बाला भाहर) : आदरणीय चेयरमैन साहब, आपके द्वारा मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना

चाहता हूं कि यह जो सरचार्ज बढ़ाया जा रहा है इससे हम अपने उस वायदे को पूरा नहीं कर पाएंगे जो हमने लोगों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ, मजदूरों के साथ और छोटे तबके के लोगों के साथ किया था कि हम आपको राहत दिलाएंगे। सेल्ज़ टैक्स सरचार्ज को, जब बड़े दुकानदार छोटे दुकानदार को सामान देंगे तो उसके ऊपर सेल्ज़ टैक्स जो लगा हुआ है वह भी लेंगे और जो सरचार्ज बढ़ा है वह भी लेंगे लेकिन छोटे दुकानदार जब ग्राहक को सामान देंगे तो ग्राहक, कितने ही रुपये की चीज क्यों न ले, जब सेल्ज़ टैक्स देना पड़ता है तो फर्क महसूस करता है और जब उसे लगा हुआ सेल्ज़ टैक्स और सरचार्ज नहीं लेगा तो इससे उन्हें बहुत भारी नुक्सान उठाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे बड़ी परे ाानी होगी। चेयरमैन साहब, छोटे दुकानदार को आधा परसैन्ट, एक परसैन्ट, दो परसैन्ट, चार परसैन्ट, छः परसैन्ट, सात परसैन्ट और दस परसैन्ट सबका अलग अलग हिसाब किताब रखना पड़ता है और इस हिसाब किताब रखने में वह पागल हो जाता है। जब यह टैक्स लग जाएगा तो उसे और भी मु कल पैदा होगी। होता क्या है ? इसके कारण भ्रश्टाचार, और बेईमानी बढ़ती है और नौकर ाही का बोलबाला होता है। चेयरमैन साहब, जैसा मैंने पहले कहा हमने दे ा के लोगों से वायदा किया था कि हम सेल्ज़ टैक्स को समाप्त करेंगे और टैक्सिज़ का जो ढांचा है उसके अन्दर कुछ ढील देंगे। इसलिए हमें उस वायदे पर कायम रहना चाहिए और आमदनी के और साधन ढूंढने चाहिए। मेरे से पूर्व वक्ता ने भी एक बात बताई

थी और वह यह थी कि हजारों की तादाद में दिल्ली से ट्रक आते हैं। (विघन) बैरियर के ऊपर उन्हें रोक लिया जाता है। लेकिन वे करते क्या हैं यह देखने वाली बात है। जिनके ऊपर थोड़े टैक्स का माल होता है उन्हें तो वे अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए रोक लेते हैं लेकिन जिनके ऊपर ज्यादा टैक्स का माल होात है उन्हें वे जाने देते हैं क्योंकि उनके साथ उनका कमी ान बंधा हुआ होता है। अब आप हिसाब लगाएं कि अगर इस तरह दिन के 20, 30 या 40 ट्रक बिना टैक्स दिये निकल गए तो हरियाणा गवर्नमैंट को कितना नुकसान होगा ? इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

चेयरमैन साहब, इस टैक्स के लगने से यहां के ट्रेड और ज्यादा नुकसान होगा। मैं तो उस जिले से आता हूं जो बिल्कुल पंजाब के साथ लगा हुआ है। मेरे यहां से आधा मील या एक मील के फासले से पंजाब भाुरू हो जाता है। अभी पिछले दिनों हमारे यहां के कुछ व्यापारियों ने हरियाणा में अपना काम काज बंद करके राजपुरा और लालडू आदि में इसलिए व्यापार भाुरू कर दिया कि हरियाणा में जो राहत उन्हें मिलनी चाहिए थी वह उन्हें नहीं मिली।

चेयरमैन साहब, टैक्स की चोरी का एक केस उदाहरण के तौर पर सदन के सामने रखना चाहता हूं। अम्बाला छावनी में दो ढाबे हैं जैसे डीलक्स ढाबा और पूर्णसिंह का ढाबा। चार्जिज़ तो वे करते हैं रैस्टोरैंट और होटल वाले और सेल्ज़ भी उनकी

हजारों रुपये की होती है। लेकिन क्योंकि बाहर ढाबा लिखा हुआ है इसलिए उन पर सेल्ज टैक्स नहीं लगता। लेकिन इसके बरक्स एक रेहड़ी वाले पर जो इन्कम टैक्स आफिस के बार खड़ा होकर केवल छोले और भटूरे बेचता है सिर्फ टैक्स ही नहीं लगाया। बल्कि पिछले चार साल के हिसाब किताब के लिए नोटिस भी दे दिया क्योंकि रेहड़ी के ऊपर केवल रावलपिंडी रिफ्रै ामैंट लिखा हुआ था। हो सकता है कि उसने किसी इनकम टैक्स वाले से छोले भटूरे के पैसे चार्ज कर लिए हों। अब आप अन्दाज़ा लगा लीजिए कि इस टैक्स की वजह से गरीब लागों को कितनी दिक्कत होती है। वे सरकारी कर्मचारियों के अधीन रहते हैं यदि उनका हलवा मांडा चलता रहेगा तो भाायद टैक्स से बच पाएंगे वरना गरीब आदमी के ऊपर जिसकी मु कल से 30–40 रुपये की सेल हो उस पर टैक्स लग जाएगा और जो हजारों रुपये रोज़ की सेल करते हैं केवल ढाबा भाब्द लिखने की वजह से सूखे निकल जाएंगे।

चेयरमैन साहब, भाायद हालात से मजबूर होकर यह टैक्स लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री जी ने अभी बताया भी है कि इस टैक्स से खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर खास फर्क पड़ने वाला नहीं है तो हरियाणा के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्यों न इसमें यह बात लिख दी जाए कि सेल्ज़ टैक्स को घटाने का जो वायदा हमने किया था उसे हम हरियाणा के अन्दर प्रकृति का

प्रकोप होने के कारण लोगों को जो मुसीबत का सामान करना पड़ रहा है उनको राहत देने की वजह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं और सेल्ज़ टैक्स को एक साल के लिए या कुछ समय के लिए रखना चाहते हैं।

चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान एक दो और बातों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। सुना जा रहा है कि भाायद नमक के ऊपर भी टैक्स लगने वाला है। सुना है कि किसी हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि पैकिंग चाहे किसी भी प्रकार की है चाहे किसी कागज़ की थैली में है या प्लास्टिक की थैली में है उस पर टैक्स लग सकता है। चेयरमैन साहब, चूंकि महात्मा गांधी के असूलों पर हमारी सरकार चल रही है इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर ऐसी बात है तो सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे कि पैकिंग के आधार पर टैक्स नहीं लगाया जाए इससे जनता में और रोश बढ़ेगा। बल्कि जो टैक्स लगे हुए हैं उनकी वसूली ठीक तरह से की जाए। जो करप्ट अफसर हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जहां लीकेज हो रही है, जहां माल बिना सेल्ज़ टैक्स लिए आ रहा है उधर ज्यादा ध्यान दे। अगर सरकार ऐसा करेगी तो मैं समझता हूं कि सरचार्ज लगाने से जो आमदनी होगी उससे कई गुणा ज्यादा आमदनी उधर से हो सकती है और इस सारी आमदनी को सरकार उन इलाकों में जहां प्रकृति के प्रकोप के कारण हरियाणा के बंधुओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है, खर्च

कर सकती है। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री लछमन सिंह (कालका) : चेयरमैन साहब, बहुत सारे दोस्तें ने सेल्ज़ टैक्स के मुतालिक अपने–अपने ख्यालात का इज़हार किया है। यह बहुत लम्बी दास्तान है। अंग्रेज के राज में जब चार आने सैंकड़ा सेल्ज़ टैक्स लगाा था तो 90 दिन तक मार्किट बंद रही थी। उस समय हम यह समझते थे कि यह जो टैक्स वसूल किया जाता है यह हमारी बरबादी और हमारी तबाही पर खर्च किया जाएगा। उसके बाद दे ा आजाद हुआ। सेल्ज़ टैक्स की भारह बढ़ कर कहीं से कहीं पहुंच गई। सरकार ने लोगों को बताया कि टैक्स जो वसूल किया जाता है वह उनकी बहबूदी और भलाई कये लिए वसूल किया जाता है। लोगों को तसल्ली हुई और उस टैक्स को उन्होंनें बरदा त किया। अभी कई दोस्तें ने मुख्तलिफ भारह का टैक्स बताया है। मैं नहीं जानता फाईनैंन्स मिनिस्टर साहब ने इन्कवायरी नहीं की या क्या बात है। हिमाचल में यह टैक्स दस परसैन्ट है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापति : सरदार साहब आप एक मिनट के लिए अपनी सीट लीजिए। बहुत से मैम्बर साहिबान बोलना चाहते हैं लेकिन टाईम बहुत थोड़ा रह गया है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि अगर हाउस की सैन्स हो तो टाईम कुछ और बढ़ा दिया जाए।

मुख्यमंत्री (चौधरी देवी लाल) : चेयरमैन साहब, हाउस एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री सभापति : मैं एक घंटे के लिए हाउस को ऐक्सटैन्ड करता हूं।

दि हरियाणा जनरल सेल्ज़ टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1977

(पुनरारम्भ)

श्री लछमन सिंह : चेयरमैन साहब, हिमाचल प्रदे ा में बहुत सारी चीजों पर सेल्ज टैक्स दस परसैन्ट है लेकिन एक स्टेज पर है। यू0 पी0 के अन्दर 13 परसैन्ट है लेकिन एक स्टेज पर है। हमारे हरियाणा में सात परसैन्ट है। मिनिस्टर साहब ने 91 पैसे का फर्क बताया है। कैलकुले ान में तो फर्क नहीं है लेकिन व्यापारी कहां तकलीफ महसूस करता है ? पन्द्र परसैन्ट बढ़ने से नहीं। वह महसूस करता है कि उसे हिसाब किताब रखने में दिक्कत आती है। अगर इसे (सेल्ज़ टैक्स) से आधा परसैन्ट या एक परसैन्ट बढ़ा देते तो भाायद तकलीफ नहीं आती।

चेयरमैन साहब, जहां तक सवाल इस बात का है कि इससे व्यापार में फर्क आएगा, बतौर व्यापारी के मुझे पता है कि हमारे दे ा में सेल्ज टैक्स यदि बंद हो जाए तो पचास परसैन्ट दुकानें आज बंद हो जाएंगी। दुकानें महज चलती ही सेल्ज़ टैक्स की वजह से हैं। जैन साहब ने कहा कि इससे नम्बर दो का काम

बढ़ेगा। लेकिन मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि नम्बर दो का ही नम्बर तीन का काम भी बढ़ेगा। लोग नम्बर दो के पैसे के बारे में तो जानते हैं लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नम्बर तीन का पैसा भी है। बहुत सारे लोग भाायद जानते भी हों। यह क्या पैसा है ? मान लो मेर पास किताब के अन्दर बाकी है लेकिन नोट नहीं है, आपके पास नोट हैं लेकिन बाकी नहीं है। मैं बाकी आपके नाम लिख दूंगा और नोट ले लूंगा जब आपके पास बाकी होगी तो डाइव र्न हो जाएगी। इस तरह से ब्लैक मनी वाइट मनी बन जाएगा। यह सब सेल्ज़ टैक्स की वजह से होता है।

14.00 बजे

चेयरमैन साहब, आज यह भी कहा जाता है कि जनता सरकार ने लोगों से वायदा किया था। बिल्कुल ठीक है लेकिन यह बात सैन्टर के तहत है। जब तक सैन्टर की सरकार यह फैसला नहीं करती कि सेल्ज़ टैक्स हटाना है या काटना है और उसके ऐवज में कौन सा टैक्स लगाना है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को मालूम होगा कि गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से एक सरकूलर जारी किया गया है जिसमें इन्ड्स्ट्रीयलिस्ट और बड़े बड़े कारखानेंदारों की राय मांगी गई है कि सेल्ज़ टैक्स की जगह एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाय तो आप लोगों को कौन सी चीज ठीक रहेगी। इस बारे में भारत सरकार जो भी फैसला करगी, उस पर हर स्टेट को अमल करना पड़ेगा। सरकार इस पोजी ान में नहीं कि सेल्ज टैक्स को

हटा कर और टैक्स लगा दें। लोग सेल्ज़ टैक्स देने के आदि हो चुके हैं। इसका खर्च धीरे धीरे देने से महसूस नहीं होता है। वह आसानी से दिया जा सकता है। एक तरफ तो यहां हाउस में बड़े जोर भाोर से मांग की जाती है कि प्रोहिबि ान हो और दूसरी और आप ये कहते हैं कि कोई भी टैक्स न लगाया जाये। बाढ़ पीड़ितों के बारे में किसी ने सुझाव नहीं दिया कि उनके लिए कहां से पैसा आयेगा ? अभी अभी यहां मिनिस्टर साहब ने पढ़ कर सुनाया है कि फलां फलां चीजों पर जो नैसैस्टी आफ लाईफ है, टैक्स नहीं लगेगा। उन चीजों पर टैक्स लगेगा जैसे कूलर है, एयरकन्डी ानर्ज़ हैं यानि जो चीजें अमीर आदमी खरीदते हैं उन पर टैक्स लगेगा। लेकिन मिनिस्टर साहब इस सरचार्ज को 15 परसैन्ट की बजाए अगर एक परसैन्ट बढ़ाते तो और भी अच्छा रहता। आमदनी भी उतनी ही हो जाती जितनी 15 परसैन्ट से होगी। 15 परसैन्ट बढ़ने का तो प्रोपेगन्डा बहुत ज्यादा होता है। अनपढ़ आदमी भी समझता है कि 15 परसैन्ट सेल्ज टैकस बढ़ा दिया है। एक परसैन्ट सेल्ज टैक्स बढ़ाने से भी आदमी उतनी ही बढ़ सकती है। कई जगहों पर तो सेल्ज टैक्स 15 परसैन्ट है। पाकिस्तान में 15 परसैन्ट है लेकिन वह एक स्टेज पर देना पड़ता है। यूरोप के अन्दर 15 से 20 परसैन्ट तक सेल्ज टैक्स है। वहां पर भी एक ही स्टेज पर लगता है लेकिन हमारे यहां मल्टीपल सिस्टम है। यू0 पी0 के अन्दर भी 13 परसैन्ट है लेकिन वहां पर भी एक स्टेज पर है। एक स्टेज पर होने की वजह से पता नहीं चलता है। हिमाचल के अन्दर 10 परसैन्ट है, यह भी एक स्टेज पर

है, वहां पर भी पता नहीं चलता है। दुकानदानों से मेरा सम्बन्ध पड़ता है, हम उनको समझा देते हैं कि यह टैम्परेरी मेयर्ज़ है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) अगर भारत सरकार यह फैसला कर दे कि सेल्ज टैक्स की जगह एक्साइज ड्यूटी लगाई जाये तो तमाम का तमाम सेल्ज टैक्स खत्म हो जायेगा। इस टैक्स के बढ़ने से कोई चिन्ता की बात नहीं है। यह कहना कि हरियाणा का बिजनैस या मंडियां उजड़ जायेंगी, यह गलत बात है। कोई खास उजड़ नहीं सकती हैं। जगाधरी के बारे में भी यहां बात की गई। वहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमाचल वालों ने पौंटा साहब में अपनी टिम्बर मार्किट खोली है। हम भी बोर्डर पर अपनी मार्किट खोल सकते हैं। अगर हरियाणा यू0पी से माल लेता है तो उसके 13 परसैन्ट सेल्ज टैक्स देना पड़ता है। हिमाचल अपने बार्डर एरियाज़ में डिवैल्पमैन्ट कर रहा है। पंजाब के अन्दर भी जितनी सरहदें हैं वहां पर डिवैल्पमैन्ट की जा रही है। हिमाचल ने कालका के पास परवाणू इन्स्ट्रीयल एस्टेट बनायी है। अभी पिछले दिनों हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब दौरा करके गये हैं और एक इन्डस्ट्री का उद्घाटन करके गये हैं। हर स्टेट के अन्दर जो भी बार्डर एरियाज है वहां पर मंडियां बनानी भ्रुरू कर दी हैं। अगर हरियाणा सरकार सेल्ज टैक्स व्यापारियों से लेगी तो मंडियां नहीं उजड़ सकतीं। इसलिये हमारे जितने भी बार्डर एरियाज़ हैं, बार्डर के टाउन हैं उनकी डिवैल्पमैन्ट की ओर ध्यान दें। मैं तो इस बिल को इसलिये भी सपोर्ट कर रहा हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कालका के लिये पीने के पानी का प्रबन्ध किया

है। कालका में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। वहां के लोग पानी के लिये तड़फा करते थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने 28 लाख रुपया पानी की स्कीम के लिये मंजूर कर दिया है। ऐसे अच्छे काम के लिये टैक्स वसूल कर लिया जाये तो मैं समझता हूं कोई गलत बात नहीं हैं जनता भी इस टैक्स से नाराज नहीं होगी। जनता के खून–पसीने की कमायी अच्छे कामों में लगायी जानी चाहिए। पिछली सरकार की तरह से लूट नहीं मचायी जानी चाहिए। यूथ कांग्रेस ने लाखों रुपया इकट्ठा करके भिवानी के बैंकों में जमा करा दिया। अगर सरकार ऐसे कामों के लिए, जहां फ्लड का सवाल है कितना ही पैसा ले तो जनता खु ाी से देती है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में पढ़ कर सुनाया कि जनता सरकार ने फ्लड ज़दा लोगों के लिए कितना काम किया है। चीफ मिनिस्टर साहब की सेहज इज़ाज़त न देने पर ाी हर चार–पांच दिन के बाद दौरे पर जाते रहे। हमारे जतना पार्टी के एम0एल0ए0 और दूसरे कार्यकर्ता भी उन एरियाज में जाते रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि इससे ज्यादा कुर्बानी भी करनी पड़े तो हमें इस टैक्स के देने मैं एतराज नहीं होगा। बिना कोई वज़ह के मुखालफत करते चले जायें, यह उचित नहीं है। आज के दिन जिन भाइयों के पास मकान नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं, चाय तक पीने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने जानवरों की परवरि ा नहीं कर सकते हैं ऐसे फ्लडज़दा लोंगों के लिए कितना ही टैक्स देना पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। नेक काम के लिए जनता हर बोझे को बरदा त करने के लिए तैयार है लेकिन मैं जनता पार्टी के लोगों

को वारनिंग देना चाहता हूं कि अगर इस पैसे को नाजायज तौर पर खर्च किया गया तो जनता माफ नहीं करेगी। हमारे आद र्ा सही होने चाहिएं और हमें सही ढंग से काम करना चाहिए। मैं मिनिस्टर साहब को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर इस टैक्स को एक परसैन्ट बढ़ा दिया जाता तो व्यापारियों के मन में जितनी गलत बातैं आयी हैं ये नहीं आती। हरेक के दिमाग में यह बात है कि 15 परसैन्ट बढ़ा दिया। अगर इसको छः या सात परसैन्ट कर दिया जाता तो कोई बात नहीं थी। यह तो कैलकुले ान की बात है, साइकलोजीकल असर पड़ता है। अगर कोई आदमी एक चीज़ पांच छः रुपये में खरीदता है, उसका भाव एकदम बढ़ जाये और अखबारों में यह आ जाये कि 25 परसैन्ट भाव बढ़ गया है तो बड़ा भाोर होगा। टैक्स तो पहले भी लगता था लेकिन अखबारों में वह बात नहीं आती थी। लेकिन आज के दिन अखबार स्वतन्त्र हैं। अगर अखबार में यह आ जाये कि पागल कुत्ते को काट लिया तो बड़ा भाोर मचता है। अखबार वाले तो यह चाहते हैं कि किस तरह से लोगौं की दिलचस्पी बढ़े। पचास आदमी जनता पार्टी की एक चीज़ को स्पोर्ट करते हैं मगर एक आदमी मुखालिफत करता है तो मुखालिफत करने वाले उस आदमी की बात तो अखबार में आ जाती है लेकिन पचास आदमियौं की बात नहीं आती है। आज के जमाने में यह धारणा बनी हुई है। तो डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा सरकार को अपना सुझाव देना चाहता हूं कि वैसे तो यह ठीक है टैक्स लगाने से पहले सोचना चाहिए लेकिन जब सरकार यह कहती है कि फ्लड इफैक्टिक लोगों पर यह पैसा खर्च

किया जायेगा, उनकी बेहतरी पर खर्च किया जायेगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी राज में चार आने टैक्स लगता था तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी। जब से हमारा अपना राज आया है कितने ही टैक्स लग रहे हैं हम 70 परसैन्ट तक टैक्स देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। बड़ी खु ाी के साथ दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त नहीं दिये। आज हमारी अपनी सरकार है बखु ाी टैक्स ले सकती है। मैं आपके जरिए इतना जरूर अर्ज़ करूंगा कि अगर वह 15 परसैन्ट सरचार्ज की बजाए एक परसैन्ट बढ़ा दिया होता तो बहुत सारे जो मेरे दोस्तों को दिक्कत हो रही है, जिनका दुकानदारों से बहुत ताल्लुक है उनकी काफी हद तक परे ाानी दूर हो सकती थी।

ठाकुर बीर सिंह (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस मसले पर काफी से ज्यादा बहस हो चुकी है। कुछ हमारे साथियों ने हमारे इस टैक्स का विरोध किया है। मैं यह समझता हूं कि दिल से वे यह समझते हैं कि यह टैक्स जायज़ तरीके से लगाया जा रहा है। वह तो सिर्फ बहस की वजह से बहस करना चाहते हैं। उनके सामने सारे हालात जाहिर हैं कि जिस वक्त यह भाई राज छोड़ कर गये थे, उस वक्त खजाने को पूरी तरह से खाली कर गये थे। डिवैल्पमैन्ट के लिये हमारे पास खजाने में कोई पैसा नहीं छोड़ कर गये थे। यह हालात उनको भी पूरी तरह से पता है और आपको भी पता है। जो टैक्स पिछली सरकार ने लगाये थे, उन टैक्सों में सरकार ने कोई गुंजाइ ा ही नहीं छोड़ी थी कि

उनको बढ़ाया जा सके या किन्हीं दूसरी चीजौं पर हम कोई टैक्स लगा सकें। आप लैंड रैवेन्यू की बात को ही ले लीजिये। जहां यह पहले एक आने या दो आने था उस लगान को बीस गुना या तीस गुना बढ़ा दिया गया। बाकी आईटम्ज़ को भी अगर आप देखें तो आपको यह पता चलेगा कि कोई आईटम भी ऐसी नज़र नहीं आती कि जिस पर उन्होंने टैक्स न लगाया हो और जो जनता सरकारे के लिये छोड़ी हो। मेरे लायक दोस्त यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बगैर टैक्सों के लगाये सरकार का काम नहीं चल सकता। इस सरकार ने काम चलाने के लिए कहतज़दा इलाकों को बचाने के लिये पैसा खर्च किया है और फ्लड अफैक्टिड एरियाज़ के लिये पैसे की जरूरत है। इस सरकार ने 2 प्रति ात की बजाय 15 प्रति ात ही तो सरचार्ज करने की प्रोपोज़ल रखी है जो कि एक मामूली सी प्रोपोज़ल है और वह भी इसलिये जरूरी है कि सरकारी खजाना खाली है और सरकार को पैसे की सख्त जरूरत है। अब सोचने की बात यह है कि किन आईटम्ज़ से फौरी तौर पर टैक्स आ सकता था। एक तो हमने कल ही एन्टरटेनमैंट टैक्स पास किया है और दूसरा टैक्स हमारे सामने है जो कि सेल्ज़ टैक्स का है। यह दोनों ही किस्म के टैक्स ऐसे टैक्स हैं जो कम्फर्ट और लईयर पर टैक्स हैं। यह आम आदमी की रोज़ाना की जिन्दगी में कोई रुकावट नहीं डालते बल्कि ऐसे टैक्स हैं जिनसे राज़ाना काफी आमदनी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह दोनों ही इस किस्म के टैक्स हैं जिससे किसी आदमी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि इससे जो आमदनी होगी

वह सरकार के सामने जो डिवैल्पमैंट के काम मौजूद हैं, उनमें लगायी जा सकती है। मेरे लायक दोस्तों ने इस टैक्स को अपोज़ करने की बजाये ज्यादा जोर इस बात पर दिया है कि टैक्स की चोरी हाती है, पूरा टैक्स मिलता नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि टैक्स पूरा वसूल होना चाहिए। मैं भी यह महसूस करता हूं कि जितना टैक्स होता है उसका सिर्फ 25 प्रति ात ही टैक्स के रूप में वसूल होता है और 75 प्रति ात टैक्स की चोरी होती है। उस टैक्स की चोरी को रोकने के लिये मैं अपनी सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस किस्म के साधन जुटाये जायें कि जो व्यापारी लोग ब्लैक का पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि मूल चन्द जी ने भी कहा कि दो नम्बर का रुपया और तीन नम्बर का रुपया भी है, जो इसी टैक्स के न देने की वजह से पैदा होता है, वह न होने पाये। मैं चाहता हूं कि सरकार इस टैक्स को ही नहीं बल्कि सब टैक्सों को पूरी तरह से वसूल करने के लिये पूरे साधन जुटाये। उन्होंने यह सुजै ान दी कि लगाये हुए टैक्सों को पूरी तरह से वसूल करने के बाद भी सारी स्टेट का काम चलाया जा सकता है। भाायद हमारी यह सरकार इस काम में कामयाब हो। अगर यह सरकार इसमें कामयाब हो गयी तो जो 15 प्रति ात तक सरचार्ज बढ़ाया गया है इसमें भी कमी की जा सकती है और दूसरे टैक्सों में भी कमी की जा सकती है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि फिलहाल इस टैक्स को लगाकर स्टेट के रैवेन्यू में बढ़ावा किया जाये। एक दूसरी बात भी यहां पर कही गयी और जिस पर ज्यादा जोर दिया गया। हमारे अपोज़ी ान के बैंन्चिज़

की तरफ से भी और हमारी पार्टी के कुछ सदस्यगणों ने भी यह बात कही। वह बात यह कही कि जनता पार्टी ने अपने मैनीफैस्टों में यह रखा था कि वह सेल्ज़ टैक्स को समाप्त कर देगी। जनता पार्टी अपने उस वायदे से मुनकर नहीं हुई है। जनता पार्टी को अब भी अपना मैनीफैस्टों याद है उसको वह भूली नहीं है। जो वायदा उसने किया है, उसे पूरा करने के लिय वह वचनबद्ध है। हमारी पैंट्रल गवर्नमैंट के सामने यह सेल्ज़ टैक्स का मसला है और हमारी सैंट्रल गवर्नमैंट उस पर बाकायदा सोच विचार कर रही है। हमारी जो जनता पार्टी के सैंटर में लीडर हैं, मेरी भी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने मुझे यह बतलाया कि यह मसला इनता आसान नहीं है कि इसे एकदम से हल कर दिया जा सके। इस मसले को हल करने के लिए हर स्टेट की राय की जरूरत है। उनसे राय लेकर, उनसे रैजोलु ान की ताईद करवा कर, फिर इस मसले को हल किया जा सकता है। हमारी सैंट्रल सरकार ने वह प्रोपोज़ल स्टेट गवर्नमैंट्स को भेजी हुई है। ज्यों ही वह प्रोपोज़ल कामयाब हो जायेगी, इस सेल्ज़ टैक्स का मसला भी हल हो जायेगा। यह जो हमारे यहां टैक्स बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रोपोज़ल आयी है, इसमें कोई भी ऐसी–वैसी किसम की बात नहीं है। यह जो हम 15 प्रति ात सरचार्ज बढ़ाने चले हैं, यह कोई परमानैन्टली तो नहीं करने चले हैं। जब यह सेल्ज़ टैक्स ही खत्म हो जायेगा तो उसके साथ ही आटोमैटीकली सरचार्ज भी खत्म हो जायेगा। यह नहीं हो सकता कि सेल्ज़ टैक्स तो खत्म हो जाये और उस पर लगा हुआ सरचार्ज खड़ा रहे। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि

यह मसला सैंट्रल गवर्नमैंट के ज़ेरे गौर है और हमारी पार्टी पूरी तरह से इस बात की कोि ा ा कर रही है कि जो जनता से वायदा किया गया है, वह पूरा किया जाये। ज्यों ही इस चीज़ में सरकार कामयाब हो जायेगी और सारी फार्मेलिटिज़ पूरी कर लेगी, त्योयं ही सरचार्ज भी खत्म हो जायेगा। एक दूसरी बात सेल्ज़ टैक्स की चोरी रोकने के लिए लछमन सिंह जी ने भी कही कि टैक्स जो है वह एट सोर्स लगाया जाये। यानी जहां पर प्रोडक ान होती है, वहां से जब माल निकले तो उसकी कीमत के साथ सेल्ज़ टैक्स भी लग जाना चाहिए। इससे टैक्स इवेज़न भी नहीं होगा और स्टेट को भी ज्यादा आमदनी होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह दोनों तीनों मसले आज हमारी सैंट्रल गवर्नमैंट के ध्यान में हैं। मैं अपने लायक दोस्तों को यह बताना चाहूंगा कि हमारी जनता पार्टी की सरकार जो है, वह अपने मैनीफैस्टों में किये गये सब वायदे पूरे करेगी, उनको पूरा करने के लिये दिलो–जान से पूरी कोि ा ा कर रही है। जिस तरह से उसने दूसरे वायदे पूरे किये हैं, उसी तरह से यह वायदा भी पूरा करने की कोि ा ा करेगी। सबसे पहला मसला लोगौं की आजादी का था। आज से पहले गवर्नमैंट थी, उसने लोगों के बोलने तक के हक को छीन लिया था। लोगों की जुबान पर ताले लगे हुए थे। लेकिन हमने लोगों को बोलने की खुली आजादी दी है। यही वजह है कि आप आज देखते हैं कि लोग दिल खोल कर बहस में यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। उनको खुली छुट्टी है और वह जो मन में आता है, वह कहते हैं। उनको इस बात का ख्याल नहीं

आया कि जो गवर्नमैंट ने वायदे किये थे, वे उसने पूरे करने भुरू कर दिये हैं और तीन महीने में सरकारे ने जितना कुछ किया है, उतना कुछ तो आपकी कांग्रेस सरकार 30 साल में भी नहीं कर पायी। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि यह तो एक मामूली सी ऐडी ान है। यह जो एडी ान की जा रही है, इसका आम आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि यह सब लैइयर और कम्फर्ट की चीज़े हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। यह कहते हैं कि यह जनता पार्टी की सरकार जो अपने आपको सो ालिस्ट सरकार कहती है कि यह टैक्स लगा रही है, यह बिल्कुल जायज़ है और ठीक है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : कई आनरेबल मैम्बर्ज़ बोलना चाहते हैं। इसलिये मैं बोलने वाले मैम्बर साहिबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे दो मिनट से ज्यादा न लें।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू) :डिप्टी स्पीकर साहब, आज सेल्ज़ टैक्स के ऊपर चर्चा चल रही है। मैं समझता हूं कि झगड़ा इस बात का नहीं है कि ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। बल्कि झगड़ा इस बात का है कि पूंजीपति पहले जो टैक्स की चोरी करता था, जो आम आदमी की लूट खसूट करता था वह अब नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आज की सरकार गरीबों की भलाई के लिए, जो लोग बाढ़ के कारण बरबाद हो गए हैं उनकी भलाई के लिए काम करने जा रही है, उसमें वे लोग रूकावट पैदा करना

चाहते हैं। जो वर्ग गरीबों का हमदर्द बनता है, और जो वर्ग इस टैक्स का विरोध करता है यह वर्ग उस वक्त कहां चला गया था जिस वक्त पिछले अर्से में किसान पर चार गुणा से बीस गुणा यानी पांच सौ परसैन्ट टैक्स लगाया गया था। क्या उस वक्त इस वर्ग को यह नजर नहीं आया ? आज थोड़ा सा टैक्स अगर लगाया जा रहा है तो वे लोग धरना की भाक्ल में, जलूस की भाक्ल में एक तूफान मचा रहे हैं। बात यह है कि इस वर्ग को ज्यादा बात करनी आती हैं। इसके पास अखयबार हैं, प्रचार के बहुत से साधन हैं इसलिए उनके द्वारा ये अपनी आवाज़ को ज्यादा ज़ोर से उठा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान एक कृशि प्रधान दे ा है .....

श्री मूल चन्द मंगला : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्य : आपको पता है जिस दिन किसान के ऊपर पांच सौ परसेन्ट टैक्स लगा था उस दिन कोई आवाज़ उसके खिलाफ नहीं उठाई गई थी। मेरी तो सरकार से दरखास्त है कि इस टैक्स को 15 परसेन्ट की बजाय 25 परसेन्ट कर देना चाहिए। इससे कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने इस बिल के बारे में जो वर्णन दिया है मैं उससे

सहमत हूं। हमारे प्रान्त की सरकार को फ्लड की वजह से जो बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है उसको हल करने के लिए यह टैक्स लगाया जा रहा है और साथ ही यह कहा जा रहा है कि इससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर सरकार अपनी टैक्स कलैक ान म ाीनरी को ठीक कर दे तो जो आमदनी होनी है उससे कई गुणा ज्यादा आमदनी हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सरकारी कर्मचारियों ने जनता सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसी तज़बीज़ सरकार के सामने रखी है जिनसे सरकार को तो लाभ न हो लेकिन सरकार बदनाम हो जाए। ऐसी ही एक ऐग्ज़ाम्पल है जो मैं सदन में रखना चाहता हूं। आपको पता होगा कि पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है और वहां पर 15 करोड़ रुपए का वूलन यार्न एक साल में तैयार होता है। उससे फिर कम्बल तैयार किये जाते हैं। उस वूलन यार्न में से कम से कम दस करोड़ का यार्न मिर्जापुर (यू0पी0) में जाता है और वहां कालीन तैयार किए जाते हैं और करोड़ों रुपया फारेन ऐक्सचेन्ज की भाक्ल में मुल्क में आता है लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने जिसका यह मकसद होता था कि ट्रेड वालों को परे ाान किया जाए, हैरास किया जाए जिससे ट्रेड वाले उनको नाजायज़ पैसा देकर उनकी जेबें भरें। उपाध्यक्ष महोदय, यह यार्न की एक गुच्छी है जो तीन सौ मीटर की है। इससे कालीन और कम्बल तैयार होते हैं लेकिन महकमें वाले इसको स्पन यार्न नहीं मान रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण देना चाहता हूं। वे इसको स्पन यार्न

करार नहीं दे रहे हैं। यू0पी0 के अन्दर कालीन बनाने की एक फैक्टरी है उसने टैक्स बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और उसके वकील ने कालीन के एक टुकड़े से रे ा निकालकर कोर्ट में दिखाने भाुरू कर दिए .....

श्री उपाध्यक्ष: आप बिल पर बोलें।

श्री फतेह चन्द विज : उपाध्यक्ष महोदय, इस इन्डस्ट्री को 15 करोड़ का फायदा होता है और अब ये ट्रेड आधे से ज्यादा राजस्थान में ट्रांसफर हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिल पर बोलें (व्यवधान) अब आप बैठ जाइए।

श्री फतेह चन्द बिज : मैं इसको वित्त मन्त्री को दे रहा हूं। वह ये देख लें कि यह धागा है ......

श्री उपाध्यक्ष : अब आप खत्म करिए। आप बैठ जाइए।

स्वामी अग्निवे ा (पुंडरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से बिल पर हम लोगों ने जरुरत से ज्यादा समय बहस पर खर्च कर दिया है लेकिन मैं समझता हूं कि इस छोटी सी बात पर बेकार में समय जाया नहीं करना चाहिए। सेल्ज टैक्स के ऊपर जिस बात का भाोर मचा हुआ है वास्तव में वह टैक्स नहीं है बल्कि टैक्स पर लगा सरचार्ज है। सरचार्ज में कुछ वृद्धि हुई है टैक्स में कुछ नहीं बढ़ाया जा रहा है। सेल्ज़ टैक्स तो सात

प्रति ात था वह वैसे ही है। सरचार्ज जो पहले सात प्रति ात पर चौदह पैसे देना पड़ता था वह अब चौदह की बजाए 91 पैसे ज्यादा देना पड़ेगा। बहुत थोड़ी सी वृद्धि हुई है और वह भी सारी चीजों पर नहीं। आम आदमी के प्रयोग की चीजों पर यह बढ़ौतरी नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं कि यदि व्यापारी वर्ग को कुछ गलतफहमी है तो हम सब मिलकर उनकी गलतफहमी को दूर करें। यह टैक्स उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा। और यह उपभोक्ता वह है जो रैफ्रीजरेटर इस्तेमाल करता है, कूलर इस्तेमाली करता है और दूसरी बहुत सी वस्तुएं जो अमीर लोग प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे लोगों पर कुछ ज्यादा सरचार्ज लग गया तो कोई मायने नहीं रखता। मैं चौधरी सतवीर सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह टैक्स ठीक लगाया है। बल्कि अमीरों पर तो और भी टैक्स लगना चाहिए। पूंजीपतियों को पता होना चाहिए कि जनता की सरकार आने के बाद अब माहौल बदल गया है। लेकिन यहां पर बहुत मामूली सी सरचार्ज की वृद्धि पर, सारी चीजों को समझने के बाद भी और हमारे वित्त मन्त्री जी के स्पश्टीकरण के बाद बहस की कोई गुंजाइ ा नहीं रहती। मैं समझता हूं कि सदन एक स्वर से इस बिल को पारित करे और इस सरचार्ज के बारे में बाज़ार में अगर कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए (व्यवधान)

चौधरी गंगा राम (गोहाना) : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे आज अच्छी तरह से वह नज़ारा याद है जब हम फ्लड अफैक्टिड

एरियाज़ में जाते थे और ट्रकों में लोगों को भर कर गांव के गांव खाली करवा रहे थे। लोग गांव से बाहर निकल रहे थे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हरियाणा में तबाही आई है, हरियाणा के देहात फ्लड के कारण बरबाद हो गए हैं। मैं अपनी इस सरकार को और मुख्य मंत्री साहब का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों को बचाने के लिए, देहात को बचाने के लिए आज के ******* व्यापारी पर थोड़ा बहुत टैक्स लगाया है। मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं.....

श्री मूल चन्द जैन : आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहब क्या ******* व्यापारी कहना पार्लियामैंटरी प्रैक्टिस में जायज़ है ? यह रिकार्ड से ऐक्सपंज होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको विदड्रा कर लें।

चौधरी गंगा राम : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अफसोस करता हूं कि जो वर्ग आज तक लूटता रहा है उसको अगर मैं ******* भी न कहूं और क्या कहूं ? मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि लोग यह चाहते हैं कि देहात और किसान की बहबूदी के लिए कोई पैसा खज़ाने के अन्दर न आए। मुझे यह अच्छी तरह से पता है और हम जब मंडियों में जाते थे तो यह आवाज़ सुनते थे कि हम इस टैक्स के खिलाफ आन्दोलन करेंगे और कुछ व्यक्ति जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझको अच्छी तरह से याद है, उनको उकसाना चाहते थे।

Mr. Deputy Speaker : I expunge the remarks (lutera) from the proceedings of the House.

चौधरी गंगा राम : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह दावे के साथ सकता हूं कि आज का जो किसान है, वह आज जाग चुका है, वह आज अपने आपको बरबाद होते नहीं देख सकता। आज किसासन को किसी तरह से भी लूटने की कोि ा ा की गई तो उसको बरदा त नहीं किया जाएगा। मैं आज हैरान हूं कि यह जो टैक्स है सरकार तो लगाती है व्यापारी के ऊपर और व्यापारी अपने ऊपर न रख कर उल्टा हमारे से, खरीददार से वही टैक्स का पैसा लूटने की कोि ा ा करता है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी राह निकाले जिससे वह टैक्स व्यापारी लोग हम लोगौं से इंडायरैक्ट वसूल न कर पाए। इसके साथ–साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे हरियाणा का गरीब किसान जिस चीज़ को इस्तेमाल करता है उसके ऊपर यह सेल्ज़ टैक्स न लगाया जाए।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सारे दे ा के अन्दर हमारे व्यापारियों पर जब टैक्स लगाया जाता है तो वे बाज़ार में आकर अपनी मनमाने भाव से चीज़े बेचते हैं और किसान बेचारा जब मण्डी में अपनी चीज़ को लाता है तो उसकी चीज़ पर टैक्स लगाकर व्यापारी उसे बुरी तरह से लूटते हैं जो कि बहुत बुरी बात है। इसलिये मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि इन टैक्सों से गरीब किसानों को तो राहत

मिलनी चाहिए और जो व्यापारी है, जो लूट का पैसा बटोरता है उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने चाहिये और वह सारा चोरी का पैसा उससे वसूल करना चाहिये। जो बड़े–बड़े व्यापारी टैक्स की चोरी करते हैं उनको जेलों में ठोंस देना चाहिये। इन भाब्दों के साथ मैं डिप्टी स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

वित्त मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बिल के ऊपर काफी बहस हो चुकी हैं अभी मेरे भाई सरदार लछमन सिंह जी ने कहा कि यह जो सरचार्ज 2 से 15 परसैन्ट बढ़ाया जा रहा है यह गलत बात हैं एक परसैन्ट टैक्स ही बढ़ा देते, 7 से 8 परसैन्ट कर देते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कर देते तो सरकार की आमदनी ज्यादा होती। लेकिन इसमें फर्क है, टैक्स की इवेजन हो सकती है लेकिन सरचार्ज तो टैक्स के ऊपर है इसलिए उसकी इवेजन नहीं हो सकती। यहां जो टैक्स देता है उसको सरचार्ज जरूर देना पड़ेगा। अब जो कुछ किया गया है, उससे व्यापारी को इवेजन करने का मौका नहीं मिलेगा (विघ्न)

श्री लछमन सिंह : मेरा मतलब यह था कि टैक्स जब लगेगा तो उस पर सरचार्ज भी होगा। अगर कोई टैक्स की इवेजन करता है तो सरचार्ज कहां से मिलेगा ? क्योंकि सरचार्ज तो टैक्स पर ही लगेगा। अच्छा होता यदि सरकार 7 से 8 यानी एक परसैन्ट बढ़ा देती। इससे लोगों को भी कोई खास फर्क न पड़ता।

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा अमैन्डमैंट) बिल 1977

Finace Ministeer (Chaudhri Satvir Singh Malik) : Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill 1977.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Duputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा): डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल अभी अभी हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने मूव किया है, इसके द्वारा सरकार, धारा 3 जो कि इस वक्त पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस एक्ट में मौजूद है और जिसके अन्तर्गत 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये मार्किट फी ली जाती है, उसको अब बढ़ाकर 3 रुपये करने जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में अपनी सरकार से कहना चाहूंगा कि इस का सीधा असर व्यापारियों पर न

पड़ कर, ट्रेड पर हमारे फारमर्ज़ पर और हमारे देहात पर पड़ेगा। इसलिये इसको 2 परसेन्ट से 3 परसेन्ट करते वक्त सरकार को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिये कि ऐसा करने से टैक्स का असर व्यापारियों की बजाय परचेज़र पर न पड़े (विघ्न)। मेरे कुछ भाईयों का विचार है कि इस टैक्स का असर जो है वह व्यापारियों पर पड़ता है। यह उनकी गल्तफहमी है। इसका असर व्यापारी पर नहीं पड़ता। चेयरमैन साहब, सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिये क्योंकि ऐसा टैक्स लगने से व्यापार कम होगा और व्यापार साथ वाले पड़ौसी सूबों में चला जाएगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरके, किसी हद तक, इस फीस का किसान पर भी असर पड़ता है। फर्ज़ कीजिये कोई किसान गुड़ बेचने के लिए मण्डी में ले जाता है और व्यापारी को पता है कि इस पर इतनी मार्किट फीस लगती है तो वह किसान का गुड़ खरीदते वक्त पहले ही उतने पैसे कम करके खरीदता है इसलिएये किसान पर भी इस टैक्स का असर प्ड़ता है। दूसरी चीज यह है कि आप यह टैक्स फ्लड रिलीफ के लिये लगा रहे हैं लेकिन क्या आपने एग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्किटस की धारा 28 की तरफ भी ध्यान दिया है ? उसमें यह प्रोवीजन है कि मार्किट फीस द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा। वह केवल मण्डियों के विकास, सड़कों और गोदामों इत्यादि पर ही खर्च होगा। उसे सरकार दूसरी मद में इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस पैसे को दूसरे कामों के लिए

किस रूल के तहत खर्च करना चाहती है ? यह धारा 28 सिर्फ इसी मद के अन्दर ही खर्च करने की इजाजत देती है। अगर हम उस दायरे से बाहर जाएंगे तो हाई कोर्ट .....

चौधरी राम कि ान: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से सदन का टाईम वेस्ट करने से क्या फायदा है ? बाबू जी इतना समय ले रहे हैं कौन सा आसमान टूट कर पड़ रहा है ? यह जो 15 मिनट रहते हैं इस तरह से तो यह भी जैन साहब ही ले लेंगे। मेरा निवेदन है कि टाइम बांट दिया जाए कि हर सदस्य इतना–इतना टाइम बोलेगा। अगर यही सारा टाइम ले जाएंगे तो और सदस्य बोलने से वंचित रह जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मूल चन्द जैन : जैन साहब, सबसे ज्यादा समय आपने लिया है।

श्री मूल चन्द जैन : अगर मैंने ज्यादा समय लिया है तो मैंने कोई इर–रैलेवैंट बात नहीं कही है। आप रूल 89 पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा है कि–

"At any time after a question has proposed any membere many move

"That the question be now put" and unless it appears to the Speakser that the motion is an abuse of these Rules or an infringement of the right of reasonable debate ..... "

यह कह कर कि मैं दो मिनट में खत्म कर दूं आप मुझ पर पाबन्दी लगा रहे हैं। आप मेरे राइट को खत्म कर रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि रूल्ज के बाहर जाने की न आपको इजाजत है और न मेरे को। अगर आप इस पर वजिद होंगे तो मेरे लिये बैठने के सिवा कोई चारा न होगा लेकिन अगर मैं बिल के दायरे से बाहर बोलूं तब तो आप मना कर सकते हैं (विघ्न) अगर आप इस प्रार से जल्दबाजी में काम करना चाहते हैं तो पहले मामले को पार्टी में डिस्कस करना चाहिय जहां पर उनको अच्छे सुझाव मिल सकते हैं कि किस तरह के टैक्स लगाने चाहियें और किस तरीके से करों की चोरी को रोका जा सकता है। आप सदस्यों को वि वास में तो लीजिए, आप पार्टी की मीटिंग तो बुलाइये। अब मैं इन बातों को छोड़ कर अपने प्वांयट पर आता हूं कि धारा 28 में ———

चौधरी रिज़क राम : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में रूल्ज़ आफ प्रोसीजर भी हैं लेकिन सभी सदस्यों को पता होगा कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि जो बिजनैस आज के एजेंडे पर है

वह आज खत्म होगा तो अगर थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री मूल चन्द जैन : मुझे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिकमैंडे ान का पता नहीं था। इस कमेटी की रिपोर्ट हाउस में आती है और अगर वह हाउस में पढ़ी जाती तो मैं कुदरती तौर पर अपने प्वायंटस ब्रीफ करता। मैं यह कह रहा था कि टैक्स और फीस में फर्क है। फीस तो जिस काम के लिये ली जाती है उसी काम पर खर्च की जाती है लेकिन टैक्स को सरकार जहां उचित समझे खर्च कर सकती है अगर आप किसी कालेज के लिये फंड लें फीस के रूप में और उसको कहीं और खर्च कर दें तो ऐसे मामले में हाई कोर्ट में रिट हो सकती है। ऐसे केसिज हुए भी हैं। मैं सम्भालखा हल्के को रिप्रजैन्ट करता हूं वहां से मार्किट कमेटी का 1974 के बाद 33 लाख रुपया 65 प्रति ात के हिसाब से सरकार के पास आया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एक कमेटी का 33 लाख रुपया आया हुआ है तो हरियाणा की सारी कमेटियों को ज़रब देकर आप हिसाब लगा लें कि इनके पास कितना पैसा आया हुआ है। तो उसको धारा 28 के तहत सरकार किस तरह से और काम के लिए खर्च कर सकती है। इसलिये पहले से जो रुपया जमा है उस रुपये से गोदाम बगैरह बनाएं तब तो बात ठीक है। मैं यह समझता हूं कि अगर मैं ये प्वायंटस न उठाता तो अपने फर्ज की कोताही करता। इसलिये मैंने ये

प्वायंटस रखे हैं और मुझे आ ाा है कि सरकार इन पर विचार करेगी।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान (गुड़गांव) : डिप्टी स्पीकार साहब, मैं इस बिल की स्पोर्ट के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे भाई मूल चनद जी ने कुछ बातें इस बारे में कहीं हैं। मुझे लगता है कि बाबू जी की जानकारी इस बारे में पूरी नहीं है। इन्होंने 33 लाख रुपया जो कि मार्किट कमेटी का जमा है उसके बारे में कल भी बताया था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि किसी भी कमेटी का कोई पैसा अलग से कहीं पर जमा नहीं होता बल्कि हरियाणा में तमाम कमेटियों का पैसा गवर्नमैंट के एक ही हैड में जमा होता है और यह पैसा जैसे गोडाउन्ज हैं, रूरल लिंग रोडज़ हैं या डिवैल्पमैंट आफ मार्किटस है, इन पर खर्च होता है लेकिन जितना पैसा मार्केट फीस से वसूल किया जाता है वह इसके लिए बहुत थोड़ा होता है। गवर्नमैंट की असिस्टैन्स भी मार्किटिंग बोर्ड को मिलती है, सैन्ट्रल गवर्नमैंट की असिस्टैन्स भी मिलती है और वर्ल्ड बैंक से भी हरियाणा स्टेट मार्किटिंग बोर्ड को पैसा मिलता है। जहां तक मार्केट फीस बढ़ाने का सवाल है, इसके बढ़ने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसका इफैक्ट न ट्रेडर पर होता है, न किसान पर होता है। किसान पर इफैक्ट इसलिए नहीं होता कि ज्यादातर 80 फीसदी के करीब पैसा हमें दूसरी स्टेटों से आता है क्योंकि हरियाणा एक्सपोर्टिंग स्टेट है। यहां से गेहूं, राईस वगैरा कई चीजें एक्सपोर्ट होती हैं जिनकी प्रोकयोरमैंट सैन्ट्रल गवर्नमैंट

के थ्रू होती है और उस पर जो मार्केट फीस लगती है वह दूसरी स्टेटों से आती है। इसलिए इसका असर हमारे किसान पर नहीं पड़ता और न ही ट्रेडर पर पड़ता है क्योंकि ट्रेडर को यह पैसा फालतू नहीं देना पड़ता। ट्रेडर ने तो पैसा कुलैक्ट करके मार्केट कमेटियों में जमा करवाना होता है। इसी लिए दो से तीन परसैंट बढ़ौतरी की जा रही है। इससे न ट्रेडर, न हमारा किसान और न हरियाणा का कौमन आदमी एफैक्ट होता है। जो जरूरी चीजें कौमन मैन को चाहिएं वे देहात में ही खरीद लेता है क्योंकि इनकी छोटी–छोटी रिक्वायरमैंट्स होती हैं। सिर्फ मार्केट में जो चीज़ बिकने के लिए आती है उसर पर असर पड़ता है। इसलिए इस बिल में जो बढ़ौतरी की जा रही है, मैं इसको स्पोर्ट करता हूं। जय हिन्द।

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो टैक्स लगाया है मैं इसको अपोज़ करता हूं। अगर 10–20 पैसे बढ़ते तो कोई बात नहीं थी, आपने तो एक दम ही डयोड़ा कर दिया। इसका असर ट्रेडर पर ही नहीं पड़ता बल्कि कौमन मैन पर पड़ता है, जनरल प्राईसिज़ पर पड़ता है। सरकार ने आड़तिया कमी ान रिड्यूस किया था, दो रुपये से एक रुपया कर दिया था लेकिन सरकार इस पर भी नहीं टिक सकी। आज भी आढ़ती उतना ही चार्ज कर रहे हैं। सरकार अनाऊंस कुछ करती है और करती कुछ है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : अगर मैम्बर चाहें तो हाउस आधा घंटा और बढ़ा लिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस आधा घंटा और बढ़ाया जाता है।

दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्राड्यूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1977 (पुनरारम्भ)

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: The House will now take up the Bill cluase by cluause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister(Chaudhri Satvir Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speker: Question is-

That the Punjab Agricultural Produce Markets(Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा लैंड रेवेन्यू (हरियाणा अमैन्डमैंट) बिल, 1977

Finance Minister (Chaudhary Satvir Singh Malik): Sir, I beg to introduce the Punjab Land Revenue (Harana Amendment) Bill, 1977.

I also beg to move-

That the Punjab Land Revenue (Harayna Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved-

That the Punjab Land Revenue (Harayna Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speakder: Question is-

That the Punjab Land Revenue (Harayna Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister(Chaudhri Satvir Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the Punjab Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be passed.

Mr. Deputy Speker: Question is-

That the Punjab Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब आयुर्वैदिक एन्ड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज (हरियाणा अमैन्डमैंट) बिल, 1977

Finance Minister (Chaudhari Satvir Singh Malik): Sir, I beg to introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1977.

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज (हरियाणा अमैन्डमैंट) बिल

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Chaudhri Satvir Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

15.00 बजे

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल की स्टेटमैंट आफ औबजैक्टस एंड रीजन्ज में लिखा है ––

"The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963, provides that the Director of Ayurveda shall be Ex-

officio Chairman of the Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicines, Haryana. There is no provision for appointing an independent person to be the Chairman of the Board. To overcom the difficulty it has been decided to amend the Act ……."

चेयरमैन साहब, पहले डायरेक्टर जो था वह चेयरमैन होता था लेकिन अब सरकार तजवीज कर रही है कि चेयरमैन को सरकार अप्वांयट करेगी और उसकी टर्मज एन्ड कन्डी ान्ज भी गवर्नमैंट ही निर्धारित करेगी। इसमें मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि उस चेयरमैन की टमर्ज एन्ड कंडी ान रीजनेबल होनी चाहिए। कहीं ऐसी ने हो कि दो हजार रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी, बंगला मिलेगा, कार मिलेगी आदि आदि।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

*** 15.02 बजे**

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 20th October, 1977).